पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW & P M

W ebite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 9 अंक 48 प्रति सोमवार इंदौर, 13 से 19 जुलाई 2015 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

हर विदेश यात्रा में जनधन के खर्च पर मोटा लाभ पूंजीपतियों को ही दिलवाया

मोदी देश के प्रधानमंत्री या अडानी-अंबानी के व्यापार प्रतिनिधि

बांग्लादेश की यात्रा में अडानी, अंबानी के 4600 मे.वा. विद्युत परियोजना के सौदे

भारत की जनता को टीवी, समाचार पत्रों, सोशल साइटों पर अपने भाड़े के लोगों को बैठा, अरबों करोड़ रु. खर्च कर फेसबुक, ट्वीटर पर अपने झूठे सपनों को प्रसारित कर, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों में जालसाजी जो कि इंडियन एव्यूसिंग सर्विस लॉबी के भूखेरे श्वानों ने कर मोदी को देश का प्रधानमंत्री अवश्य बना दिया, पर वह देश का प्रधानमंत्री कम है, वरन जिन अडानी, अंबांनी, टाटा, बिरला व अन्य हजारों पूंजीपतियों के चंदे के दम पर सत्ता हथियाई उनका व्यावसायिक जन संपर्क प्रतिनिधि ज्यादा, सिद्ध हुआ है, वैसे जन-धन का मोदी उपयोग कर, जनहितों के नाम पर, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने जनता का और मीडिया का ध्यान बंटाने के लिए जो नौटंकिया, जिसमें झाड़ू उठाकर सफाई अभियान चलाने, फिर योग करवाने फिर डिजिटल इंडिया बनाने की कर रहा है, उसकी आड़ में अपने पूंजीपति मित्रों को ही हर कदम फायदा पहुंचा रहा है।

प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद उसे शक्तियां मिली, धन मिला, उससे वह राष्ट्र व जनहितों के नाम उसने 25 से ज्यादा देशों की विदेश यात्राएं कर, शाही अंदाज में विश्व भ्रमण कर रहा है, वहां जाकर जो व्यापारिक समझोते कर रहा है, वो राष्ट्र और जनहितों में कम वरन् खास पूंजीपति मित्रों अडानी, अंबानी टाटा और जिन व्यावसायिक घरानों, संगठनों समूहों के लिए जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में अपना काला धन निवेशित किया था, उनके हितों के लिए ज्यादा कार्य, समझोते करता है। अंतिम बांग्लादेश के दौरे पर गया तो 17000 हे. जमीन देकर, जो कि न केवल ऊपजाऊ और हरियाली आच्छादित थी, वरन सामरिक महत्व से भी भारत के लिए उपयोगी थी, जबकि 7000 हे. भूमि दलदली, अनुपयोगी है। इसी तरह 111 गांव देकर 51 गांव लिए अर्थात मोदी ने राष्ट्रसंपदा अपने भव्य स्वागत और खातिरदारी के बदले उस बांग्लादेश को दान कर दी, जहां हिंदुओं को वृहत नरसंहार किया जाता रहा है, जहां हिन्दु बंगालियों की महिलाओं का बांग्लोदशी मुसलमान सामूहिक न केवल बलात्कार करते हैं, उनकी महिलाओं को भगाकर शादी भी करते हैं। जिसे हमने आजादी दिलाई अपनी सेना की बर्बादी की, इसके विपरीत हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों से हिन्दुओं आबादी 1947 में 70 प्रश थी, 1971 में घटकर 30 प्रश और 2015 तक 8 प्रश रह गई।

(शेष पृष्ठ 10 पर)

गरीब व मध्यमवर्गीय ही मरेंगे 2005 के पूर्व के नोट बंद करने में

काला धन अमीरों, मंत्रियों, उद्योगपतियों अधिकारियों के पास- जो हैं शातिर

भारत के वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक ने रु. 500 व रु. 1000 के नोट बंद करने की जो कि 2005 के पूर्व के थे, घोषणा कालेधन को समाप्त करने के लिए कर दी थी, जिसे बढ़ाकर दिसम्बर 2015 तक कर दिया गया है। इसके विपरीत कालाधन, अघोषित आय, ये सब बड़े अधिकारियों, पूंजीपतियों, व्यावसायियों, नेताओं, उद्योगपतियों, कॉलोनाइजरों, भूमाफियाओं, शिक्षा माफियाओं, ड्रग माफियाओं, तस्करों आदि के पास ही होती है, तो सब न केवल कालाधन, बेइंतिहा इकट्ठा करते हैं, वरन् सब शातिर होने के साथ कालेधन को चल-अचल संपत्तियों में, बैंकों में, शेयर्स में, डिवेंचर्स आदि में बदलकर रखते हैं, तो उन्हें सरकार के 2005 के पूर्व के रु. 1000, 500 के नोट

5000 से ज्यादा कार्पो क्रिमिनल्स अडानी, अंबानी जैसों के कालेधन से चुनाव जीता उन पर कार्रवाई कैसे करें

बंद करने की चिंता भी नहीं रहती और और रु. 2, 4, 10 करोड़ उनके पास पड़े भी रहेंगे तो आसानी से झटके से बाजार में खपाना जानते हैं। इसके विपरीत आम मजदूरों से लेकर नौकरीपेशा जो रु. 10 से 25000 नगद, बच्चों की फीस घरेलू सामान, आपात स्थिति के लिए रखता ही है, सामान्यतः घर की महिलाएं, आने वाली समस्याओं के तात्कालीन समस्याओं के निपटारे के लिए पति, बेटों, नाती-पोतों से छिपाकर वर्षों तक रखती है। यदि ऐसे सरकारें नोटों को बंद करने लगी, जिनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है, मरेंगे वही गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय, जो बेचारे बैंकों में जमा करने, निकालने की, बैंकों में लाइन लगाकर खड़े रहने, बैंकों के बत्तमीज स्टॉफ की झिड़कियों से बचने के लिए फिर बैंकों में बढ़ती कदम-कदम की लूट-पाट, इसके पैसे काट लिए उसके पैसे काट लिए, बैंकों की तरफ जाना ही पसंद नहीं करते, उन सबकी वर्षौं से जमा पूंजी ही नोट बंद करने से रद्दी कागज के टुकड़े बन जाएगी।दूसरी ओर सबसे बड़ी मुश्किल ये है, 99.99 प्रतिशत लोग नोट देने व लेने के समय न तो उसका सन देखता है,

(शेष पृष्ठ 10 पर)

क्या चीन के नाभिकीय परमाणु बमों के भूगर्भ में परीक्षणों का परिणाम है

नेपाल और भारत में लगातार आए भूकंप के झटके

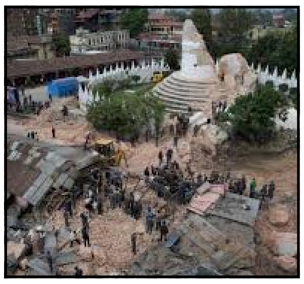

नेपाल और उत्तरी भारत से लेकर पूर्वी भारत, मध्य भारत में 25 अप्रेल से 15 से लगातार आए भूकंप के झटके जिसमें पहला 7.5 की त्रीवता का फिर उसके बाद झटके लगते रहे, उसके उपरांत 13 मई को पुनः 7.3 की त्रीवता का भूकम्प दोपहर 12:36 पर आने के बाद सांतवा झटका 4.2 की त्रीवता का भी लगा जिसका असर न केवल नेपाल वरन् भारत

चीन ने ब्रम्हपुत्र पर बनाए 24 बांधों को भरने, बहाव मोड़ने का षड़यंत्र

पोल खुलने के डर से ही भगाए भारत सहित 40 देशों के सहायताकर्मी

के 14 प्रांतों पर भी पड़ा।

चीन सन् 2000 के बाद से लगातार हिमालय से सटी भारतीय सीमाओं में धरती के नीचे और ऊपर ऐसे उत्पात लगातार कर रहा हैं जैसे शिमला, उत्तराखंड की 23 मई 2003 को आई बिना बरसात की बाढ़ से लेकर जून 2013 में आई केदारनाथ, बद्रीनाथ की भीषण बाढ़ जबकि वहां न तो घनघोर बारिश हुई थी और न ही बादल फटे थे। इसके विपरीत भीषण बाढ़ की तबाही ने लाखों यात्रियों और वहां के निवासियों को मौत की नींद सुला दिया था, जिसके पीछे चीनी षड़यंत्र ही थे। जिसका उद्देश्य था कि भारतीयों को बर्बाद कर वहां पर अपना शनैः शनैः आधिपत्य जमाना, भारत का रक्षा और गृह मंत्रालय सब जानकर भी इसलिए आंखे भींचे रहता है कि हम चीन से प्रत्यक्ष और परोक्ष युद्ध करने की मानसिक और सामरिक क्षमता में नहीं है। सत्ता में विपक्ष में खड़े रहकर, चुनाव जीतने के पहले तक मोदी का सीना 56” हुआ करता था जो सत्ता संभालने और वास्तविकता से सामना होने पर सिकुड़कर 36 का रह गया है। (शेष पृष्ठ 4 पर)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ही पूरा बकवास, बहुराष्ट्रीय कं. के हित साधक

मेगी ही नहीं सारे पेकेज्ड पेय भी घातक, स्वास्थ्य से खिलवाड़

प्रदेश की 7.25 करोड़ आबादी में मात्र 30 औ.नि., 180 खा.नि. केन्द्र व राज्यों के स्वा. मंत्रालयों में भ्रष्टों व जालसाजों का जमावाड़ा, सबको महीना मिलता है, मंत्री, प्र.स.स्वा. आयुक्तों से लेकर निरीक्षक तक सब टुकड़खोरों का गिरोह

न पर्याप्त निरीक्षक, न प्रयोगशाला, वर्षों से बैठे निरीक्षकों को वसूली से मतलब

भारत की सत्ता में कोई भी आए चाहे कांग्रेस या भाजपा सबको इस देश की जनता को लूटने और लूटवाकर कमीशन बटोरने से ही सरोकार रहा, इसके लिए इन धूर्त, मक्कार सत्ताधीशों ने कानून बनाकर जनता को लूटने, उसके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने, जहर पिलाने में इन चांडालों को कोई हिचक नहीं हुई, जिससे जनता ने सबसे पहला और बड़ा साक्षात्कार लिया। सन् 2006 में जब शीतल पेयों में इन बहुराष्ट्रीय कं. जिसमें थम्स अप, कोक, कोका कोला, लिम्का, पेप्सी आदि में खेती में उपयोग किए जाने वाले अत्याधिक घातक कीटनाशकों का उपयोग किया जाना पाया गया, तब सारी मीडिया के समाचार चैनलों और समाचार पत्रों ने अपनी कमाई और सनसनी फैलाने के लिए उछाला, तब कं. ने स्पष्टीकरण दिया कि बेशक ये कीटनाशक मिलाए जाते है ताकि इन बोतलों में मिठास के कारण कीड़े न पड़े, परंतु वह अत्याधिक सूक्ष्म मात्रा में होता है, जो कि भारत की जनता हजम कर सकती है। इतना होने पर भी सरकार में बैठे धूर्त प्र.मं. मनमोहन और ततकालीन स्वां. मं. रामदास कानून में ही अरबों रुपए डकार कर संशोधन कर उसे वैधानिक बना दिया, न विज्ञापन बंद किए गए, वरन् स्पष्टीकरण के विज्ञापन छपवा कर मोटा पैसा बांटकर मीडिया के भूखेरो का मुंह बंद कर दिया गया। तब मीडिया को भी देश की जनता ख्याल नहीं आया, न तब इन शीतल हल्के पेयों को बंद करवाने की मांग की गई, न अब की जा रही है। (शेष पृष्ठ 7 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

कुंठा

निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय भरी गाय के चाम तो, लौह भस्म हो जाए- कबीर

पृथ्वी पर प्रकृति की श्रेष्ठतम रचना है, मनुष्य उसको प्रकृति प्रदत्त उसका मस्तिष्क उसमें श्रेष्ठतम चिंतन और उस चिंतन पर कार्य करने की क्षमता, उसकी इच्छा शक्ति का ही परिणाम है, बेशक यह इच्छा शक्ति और उस पर किया गया कार्य भी प्रकृति की ही प्रकृति है, इसके विपरीत प्रकृति ने हर जीव के चाहे वह चींटी हो, हाथी हो या मनुष्य, सब को काम, क्रोध, मद, मोह, माया में बांध रखा है, बेशक काम, क्रोध, मद, मोह, माया भी उसी प्रकृति की प्रकृति है, जीवन संचालन का आधार है, हर भारी जीव, मनुष्य हल्के और कम जो पर अपने मद मोह और माया के लिए अपनी इच्छाशक्ति थोपता है, और अपने कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करता है, कभी सफल होता है कभी असफल जब हल्का और कमजोर अपने से भारी और दमदार के विरूद्ध कुछ कर नहीं पाता वहीं से कुंठा का जन्म होता है।

इसी कुंठा ने इतिहास में बड़ी-बड़ी सत्ताएं पलटा दी, महाभारत में पांच पांडवों और सौ कौरवों की युद्ध की गाथा, कौरवों का विनाश जैसी करोड़ों गाथाओं जो शब्दों का रूप लेकर इतिहास भले ही नहीं बनती हो, परंतु हर धर्मशास्त्र में निर्धनों, कमजोरों की रक्षा, कल्याण करने के तो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। उन सबका औचित्य भी यही सिद्ध करता है, कि जिसे कबीर दास ने अपने दोहे में बड़े सरल शब्दों में प्रस्तुत किया हैं

निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय
मरी श्राय के चाम ते, लौह भस्म हो जाए

वर्तमान में बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों से लेकर सत्ताधीश जिस प्रकार से जनता को अपनी लूट, खसोंट और भ्रष्टाचार से कुंठित कर रहे है, अपनी मौज, मस्ती, ऐशो-आराम के लिए जनता के मुंह से निवाला छीन उसके रोजगार को बर्बाद कर चौराहे पर भूखा मरने के लिए जो पूंजीपति उद्योगपतियों से लेकर बहुराष्ट्रीय कं. पूरे विश्व में विश्व व्यापार संगठन की शर्तों की आड़ में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन बैंक, अविकसित, अर्द्विकसित देशों को कर्ज बांटकर, पहले वहां के सत्ताधीशों को भ्रष्ट बनाते हैं। वहां के प्राकृतिक साधनों पर कब्जा करते हैं। आभासी और भौतिक समृद्धि का आभास और एहसास कराते हैं। जब ऋण को घी पचा लेते हैं। वहां के सत्ताधीश और जनता तो उनसे कागजी मुद्रारूपी ऋण को लौटाने को कहते हैं। न देने पर ग्रीस की तरह उसे दिवालियां घोषित कर देते हैं। वहां करोड़ों की जनता को क्रय शक्ति के अभाव में मरने के लिए छोड़ देते हैं। जबकि ये युरोपियन संगठन के लोग उस इतिहास को भूल जाते हैं कि ग्रीस से एलेक्जेंडर और सेल्यूकस दूनिया को रौंदते हुए एशिया के अंतिम भारत के दक्षिणी छोर तक पहुंच गए थे, ऐसे लाखों उदाहरण हमारे चारों तरफ हर दिन की जीवनी का हिस्सा होते हैं कि कुंठित निर्बल ने शक्तिशाली को निपटा दिया, यह तो मनुष्यों की बात हुई।

जंगली जानवरों में भी, शेर ने निर्बल और कमजोर भैंसे को शिकार बनाना चाहा, परंतु भैंसे ने जंगल के राजा शेर को एक बार खदेड़ दिया, जबकि दूसरी बार फिर लपका तो भैंसे ने शेर के पेट में सींग घुसेड़कर फाड़ दिया बिलकुल वैसे ही, जैसे कमजोर सुरक्षा कर्मचारियों में उनके ही घर में भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी, इसका उदाहरण है।

वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने पाखंड फैलाकर अच्छे दिन आने वाले हैं, का सपना दिखाकर सत्ता अवश्य हथिया ली, अच्छे दिन नहीं आए वहां तक तो ठीक था, परंतु जिस तरह से मजदूरों के घोर शोषण के लिए पुराने श्रम कानूनों को निष्क्रिय कर, नए कानून बनाने संशोधित करने शुरू कर, कृषकों की जमीन हड़पने, पुराने कानून समाप्त कर, नए कानून बनाकर कृषि भूमि छीन उसे कांक्रीट जंगल बनाने, शासकीय संपत्तियों, विभागों, सेवाओं, उपक्रमों आदि को जो जनधन से निर्मित किए गए थे। अपने और अपनी पूंजीपतियों के मोटे लाभ के और जनता के बेरहम शोषण के लिए सौंपे जा रहे हैं। जिससे जनता के मन-मस्तिष्क और ह्दय में कुंठा जन्म ले रही है, यह कुंठा जो सैकड़ों ज्वालामुखियों से ज्यादा घातक है, जो न केवल अदृष्य होने पर भी संघनीकृत ही किस रूप में सामने आएगी, इसको भविष्य ही परिभाषित करेगा, उस जलते बहते कुंठित संघनीकृत लावे में कौन-कौन कैसे बहेगा, इसकी इतिहास में लाखों सत्ताओं के पतन के कारणों के अध्ययन से अनुमानित भर किया जा सकता है।

निःसंदेह हर प्राणी की जल और वायु रूपी सांसे निश्चित है, वहां मात्रा समाप्त होते ही सबको नष्ट होना है, ये सत्ताधीश निश्चित कर लें कि कुंठा के लावे में नष्ट होना है, या जनता की मुस्कुराहट के फूलों में बिदा लेनी है।

सत्ता के मद में चूर होकर, है सत्ताधीशों, जितना भ्रष्टाचार कर सकते हो, खूब करो, खूब कानून बनाकर निरीहों और निर्बलों का जमकर शोषण करों, अपने को निरपराध सिद्ध करने के लिए 46 नहीं 4600 से ज्यादा हत्याएं करों व करवाओ अपने कमीशन के लिए सड़के, गिरवी कर, जनता को नोचों, जनता को अंधेरे के नाम पर, बिजली दूसरों को बैंच कर कीमतों को बढ़ाकर नोचों, सड़क परिवहन निगम बंद कर, पूंजीपतियों की बसों में 32 सीटर बस में 72 लोगों को भर, आग लगवाकर जिंदा जला दो, शिक्षा को निजी माफियाओं को सौंपकर, एक तरफ माता-पिता को लुटवाओ, दूसरी तरफ फर्जी अंकसूचियां और प्रमाणपत्रों की दुकाने सजवाओं, चिल्लाने दो जनता को, विपक्ष को, पनपने दो चारों तरफ हर मस्तिष्क में कुंठा, बनने दो ज्वालामुखी।

है, सत्ताधीशों जब तक तुम्हारा समय प्रबल है, पुलिस प्रशासन, कानून न्यायालय, स्वयं सत्ता तुम्हारी दासी है, एहसास करो, उस मूर्ख जनता पर जिसने तुम्हें चुनकर भेजा या नहीं भेजा या षड़यंत्रों से सत्ता हथियाई, समय का फेर है, प्रकृति की प्रकृति है, कि प्रकृति के निकट रहे जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित है, सब नश्वर है।

कोषालय अधिकारियों की भ्रष्ट कार्यप्रणाली और वसूली

भार. गैर न्यायिक मुद्राकों की डेढ़ से दोगुनी कीमत में बिक्री

न्यायलय में ही मुद्रांक बिक्री में अवैध वसूली पर किसी की रोक नहीं, लोकायुक्त कार्यालय पड़ोस में, पुलिस के सामने, समाचार पत्रों में आए दिन खबरों पर सरकार के भ्रष्टों को कोई असर नहीं

पूरे प्रदेश में भारतीय गैर न्यायिक मुद्राकों की बिक्री से रु. तीन हजार करोड़ से ज्यादा की आय तो सरकार को तो होती ही है, सरकार के इन स्टाम्पों की छपाई में रु. 100 करोड़ से ज्यादा खर्च भी नहीं आता, इन स्टाम्पों की बिक्री जिला कोषालयों के माध्यम से कोषालय में पंजीकृत मुद्रांक विक्रेताओं के माध्यम से, शासकीय कार्यों के लिए जनता खरीदती है।

इन मुद्रांक विक्रेताओं द्वारा रु. 10/- का मुद्रांक रु. 15/- से रु. 20 में, 50 का 55 में, रु. 100 का 110 में, बैचने के संबंध में पूछा गया तो कुछ मुद्रांक विक्रेताओं ने बताया कि मात्र 2 प्रश कमीशन मिलता है, दूसरी ओर आप अपनी मांग के अनुसार एक तो कोषालय से मुद्रांक नहीं मिलते, दूसरा गुरुवार को चालान से पैसे जमा करो, तब कहीं पेट पूजा के बाद सोमवार मंगलवार तक पुराने रजिस्टर आदि दिखाने जांच करने और सील ठप्पे लगाने के बाद भी मांग के विपरीत कोषालय अधिकारी की इच्छानुसार मुद्रांक दिए जाते हैं। अन्यथा पूर्व के बिक्री पंजी में कोई भी कारण बताकर, पंजी भी रोक लेते हैं, और मुद्रांक भी चाहेअनुसार नहीं मिलते, अर्थात कोषालय अधिकारी अपनी वसूली के लिए मुद्रांक विक्रेताओं को भी भारी प्रताड़ित करते हैं, फिर जानबूझकर में रु. 10, 50, 100 के मुद्रांकों को देने में भारी परेशान किया जाता है, दूसरी और रु. 10 का स्टॉम्प बैचों या रु. 10000 का मेहनत लिखा पड़ी उतनी ही करना पड़ती है दूसरी ओर स्वयं कोषालय अधिकारी, कर्मचारी रु. 10/- व रु.50/- के स्टॉम्प देने में स्टॉक में नहीं है का बहाना बनाकर रु. 20 के स्टॉम्प विक्रेताओं को लेने के लिए बाध्य करते हैं।

रु. 10 के स्टॉम्प को रु. 15 व रु. 20 में बैचने के समाचार, दैनिकों में छपते हुए लंबा समय गुजर गया, परंतु इंदौर न्यायालय में बैठे इन विक्रेताओं को मु.या. दंडाधिकारी न जिलाधीश, न पुलिस, न लोकायुक्त, न कोषालय अधिकारी इन जालसाजों को रंगे हाथों वीडियोग्राफी करवाकर, न केवल इनकी मुद्रांक बिक्री की पात्रता समाप्त की जाए वरन बकायदा भा.द.स. विभिन्न धाराओं में मुकदमें चलाने के साथ ही अधिवक्ता परिषद की मान्यता भी समाप्त करवाई जाए, ताकि इस तरह की लूटमार करने वालों को न केवल इंदौर वरन पूरे मप्र सबक मिले, आखिर न्यायालयों के प्रांगण में होने वाली इस खुली लूट जो प्रदेश के हर न्यायालयों में मुद्रांक विक्रेता कर रहे है।

उसे प्रशासन, कोषालय, जिलाधीश, पुलिस लोकायुक्त शायद इसलिए ही नहीं रोक पा रहे है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके भ्रष्टाचारों की पोल न खुल जाए, छपने के बाद भी सभी जिम्मेदार अर्द्धमुद्रित नेत्रों से अपने नेत्रों से अपने हिस्सों को डकार चुप बैठे हैं। ऐसा नहीं है, कि सभी अधिक दरों पर बैच रहे हो, हमें भी सूचना के अधिकार में सैकड़ों मुद्राक रु. 10, 50, 100 के लगे जो केवल इंदौर के श्री गोस्वामी उनके सामने बैठने वाले शर्माजी आदि ने सम भाव पर ही दिए, वरन उज्जैन देवास में भी बिना अधिक मूल्य दिए ही खरीदें, परंतु 90 प्रश मुद्रांक विक्रेता ये मुद्रांक अधिक मूल्य पर बैच रहे हैं। यह तथ्य नहीं नकारा जा सकता, जिस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही।

मानव संसाधन मंत्रालय विद्यार्थियों के समुचित किवास में असक्षम

10 करोड़ विद्यार्थियों को एनसीसी प्रशिक्षण की की जाए व्यवस्था

एनसीसी प्रशिक्षित विद्यार्थी राष्ट्र भविष्य में चहुं दिशा, सिद्ध होंगे उपयोगी

राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार, हमारे राष्ट्र के युवाओं की ठोस शिक्षा अनुशासन और उसमें प्रगतिशील सोच व विचारों का विकास किया जाना होता है। विश्व के श्रेष्ठ राष्ट्र होने का स्वांग भरने वाले राष्ट्रो जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान से लेकर दुनिया के हर कोने में यदि भारतीयों का जो प्रभाव और श्रमशक्ति में उनके योगदान का श्रय मूलतः शिक्षा के कारण ही है।

हमारी शालेय शिक्षा से लेकर महाविद्यालयीन शिक्षा में सैन्य शिक्षा और अनुशासन के विकास के लिए राष्ट्रीय कैडेट कार्पस जिसे एनसीसी के नाम से पुकारा जाता है की स्थापना 1950 में ही कर दी गई थी, जो चिवद्यार्थियों को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों के साथ सैन्य शिक्षा व अनुशासन का पाठ भी पढ़ाती है जिससे विद्यार्थियों को सैन्य शिक्षा के साथ छोटे हथियार चलाने, सैन्य गतिविधियों, शत्रु से लोहा लेने, परास्त करने उसकी कारगुजारियों पर अंकुश लगाने तक की शिक्षा जो वर्तमान में भारत में बढ़ते आंतरिक आतंकवाद नक्सली, बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या से आम भारतियों का जीना मुश्किल कर दिया है, में काफी उपयोगी सिद्ध होगी। वर्तमान में 90 प्रश शहरीय निजी और ग्रामीण अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में इस एनसीसी प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास और रक्षा मंत्रालय को मिलकर शीघ्र ही इस समस्या का निदान करना चाहिए ताकि भविष्य में हमारी पीढ़ी अपने दम पर देश के न केवल आंतरिक आतंकवाद नक्सली और बांग्लादेशी घुसपैठियों के उत्पात पर लगाम लगाने के साथ ही देश में बढ़ते पूंजीवाद के बढ़ते खतरों से उत्पन्न बेरोजगारी, लूटपाट, छेड़छाड़, बलात्कार, चेन स्नेचिंग, गुंडागर्दी, चड्डी बनियान गिरोह के साथ ही राष्ट्र की सीमाओं पर चीनी, पाकिस्तानी, घुसपैठियों, आतंकवादियों और सीधे आक्रमण के समय कम से कम प्राथमिक प्रशिक्षित युवा उपलब्ध हो सके, जो एनसीसी ही दे सकती है।

शिक्षा माफियाओं, दलालों ने अपनी मोटी कमाई के लिए यथार्थ में शिक्षा पर शासकीय नियंत्रण, शिक्षा मंडलों, विश्वविद्यालयों व शास. शिक्षण संस्थानों को ध्वस्त कर दिया, उन्हें ननिहालों से लेकर वर्तमान और भविष्य की युवा पीढ़ी के भविष्य से नहीं वरन् केवल वर्तमान में लूट, भ्रष्टाचार से अपनी कमाई से मतलब रहा, इसमें नेताओं, मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों से लेकर शिक्षण संस्थानों के व्याख्यता, शिक्षक, बाबू व चपरासी भी शामिल हैं। स्वाभाविक था, उन्हें विद्यार्थियों को ठोस शिक्षा, एनसीसी जैसे सारे महत्वपूर्ण आधारभूत प्रशिक्षण को नजरअंदाज किया जाने लगा।

इसके साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों में 90 प्रश से पास विद्यार्थियों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए बैठने की व्यवस्था उचित मूत्रालय, शौचालय के स्थान की व्यवस्था नहीं होती, तो 2 एकड़ का खेल का मैदान और एनसीसी के संस्थान स्तर एनसीसी की व्यवस्था कहां से होगी, क्योंकि स्कूलों , कॉलेजों, विश्वविद्यालय की मान्यताओं अनापत्ति, संबंधता, छात्रवृत्ति सब ही धन के दम पर मिलती, निरस्त होती है।

इन सबके विपरीत रक्षा मंत्रालय, मा.सं.वि. मंत्रालय जिन शिक्षण संस्थाओं का पुराना 10-15 वर्षों का इतिहास अच्छा रहा है साधन संपन्न है। उनमें इसी शिक्षण सत्र से एनसीसी प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को लागू करें, जो विद्यार्थी होनहार मजबूत कद काठी के है। इनके चयन और प्रशिक्षण की व्यवस्था स्कूलों से लेकर महाविद्यालयों तक में कर सीधे सेना में भर्ती का अभियान चलाया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही मप्र सरकार

कृषि क्रांति रथ, भाजपा, मु.मं., कृ.मं. का प्रचार रथ

जन-धन की इस बर्बादी से सैकड़ों किसानों की क्षतिपूर्ति की जा सकती थी, भ्रष्टों की पौ बारह, 15 वर्षों ये जमे हैं, वो जमे है। भ्रष्टों से गोटी नहीं बैठी तो स्नांतरण

मप्र का मुख्यमंत्री तीसरी पारी में सत्ता के मद में चूर हो कैसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए गांव-गांव में कृषि क्रांति रथ जिसमें पूरे मप्र में अरबों रुपए की बर्बादी की जा रही है अपने, अपने कृषि मंत्री के फोटो लगवाकर यथार्थ में अपना प्रचार-प्रसार कर रहा है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट आदेशित कि जन-धन से कोई भी नेता, मंत्री मुख्यमंत्री अपनी फोटो नहीं लगवाएगा, परंतु जन-धन से प्रदेश का मुखिया शिवराज इस ग्रामीण कृषि क्रांति रथ, जिसे मप्र के माध्यम से बनवाकर पूरे प्रदेश के हर जिले में 5-5 ऐसे रथ लागत से तिगुनी कीमत में अपने खास चहेतों के माध्यम से बनवाकर दिए गए हैं जिसमें पूरे प्रदेश के न केवल कृषि विभाग, उद्यानिकी, आदि के अधिकारियों से लेकर अन्य विभागीय कर्मचारियों को भी शिवराज ने अपने और अपनी पार्टी भाजपा के प्रचार प्रसार में मई और जून की चिलचिलाती गर्मियों में झोंक दिया था, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी हर जिले में न केवल बीमार हुए वरन 1-2 कर्मचारियों की मौत भी हो गई।निसंदेह यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, निर्णयों की, साथ ही जनता के धन और मन की भी अवमानना है, एक तरफ अतिवृष्टि से हुए नुकसान से हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली पर उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दे सकी, वहीं उसी कृषि को आवंटित धन से प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसे जनता और किसानों ने चुनकर सत्ता सौंपी थी, अपनी झूठी उपलब्धि का बखान करने, अपनी फोटो लगाकर गांवों में अरबों रुपए खर्च कर कृषि प्रगति रथ घुमवाया गया, धन्य है, निकम्में धूर्त शिवराज, खूब जन धन की होली खेलें। पूरे प्रदेश में 51 जिलों में कृषि विकास की 12 विभिन्न योजनाओं में अरबों रुपए का आवंटन कर जिले में आता है, जिसमें तिलहन एवं मक्का आदि की अच्छी उपज के लिए 8 कार्यक्रम है। एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम जैविक एवं रासायनिक खादों का संतुलित उपयोग, नलकूप योजना अनु. जाति व जनजाति के कृषकों हेतु 5 सूरज धार 5 योजना 6, अन्तपूर्ण योजना 7, राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम 8. बलराम ताल योजना, 9. कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन, स्प्रिकलर सेट, सिंचाई के लिए पाइप लाइन खरीदी, 11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसमें स्प्रिकलर सेट, 2 सिंचाई के लिए पाइप लाइन, 3. वर्मी कंपोस्ट यूनिट 4. पंप सेट, 5. रोटाबेटर आदि और 12. हलधर योजना में आए धन की जमकर बंदरबांट होती है। यहां तक कि शासकीय धन के आवंटन को हजम करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि व व.कृ. अधिकारी के व्यक्तिगत खातों में भी धन हस्तांतरण कर दिया जाता है, स्प्रिकलर सेट, पंप सेट, पाइप लाइन की खरीदी और उस पर अनुदान एक ही कृषक को आइसोपाम नलकूप योजना, कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में दिखाकर हर जिले से पैसा हड़पा जाता है, जिसका भौतिक सत्यापन न केवल अलीराजपुर, आगर, इंदौर, देवास, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन के साथ पूरे प्रदेश और देश के हर जिले में किया जाकर, भ्रष्टाचार के तांडव के साथ पूरे प्रदेश और देश के हर जिले में किया जाकर, भ्रष्टाचार के तांडव की पुष्टि नहीं की जा सकती है, आखिर स्थानांतरण रूकवाने, करवाने, भ्रष्टाचारों के पकड़े जाने पर बचने के लिए लाखों रुपए न केवल उपसंचालक, सहायक संचालकों से लेकर क्षे.व. कृषि विस्तार अधिकारियों से लेकर बाबु कहां से और कैसे करते है। हाल ही में हुए स्थानांतरणों में एक उपसंचालक कृषि जिलों में रु. 25 लाख तक, सहायक संचालकों को रु. 5 से 10 लाख यथास्थान बने रहने के लिए, उपसंचालक कृषि, जिलाधिकारी ने रु. 10 से 20 लाख खर्च किए, यह पैसा आयुक्त मीना, सचिव प्र.स., कृषि मंत्री बघेल और मुख्यमंत्री तक पहुंचा, जमकर किया गया।स्थानांतरणों और पदस्थापनाओं में खेल, दूसरी तरफ भ्रष्टों ने अपने आप को बचाने के लिए भी धन बांटा, एक तरफ संयुक्त संचालक, उप, सहायक संचालकों में से कई तो ऐसे हैं, जिन्होंने एक ही स्थान पर 5 से ज्यादा वर्षों से जमे हुए है, तो दूसरी तरफ बाबुओं, चपरासियों तक को 200 से 300 किमी तक दूर स्थानांतरित कर दिया गया, जो स्पष्ट करता है कि प्रशासन की मानसिकता कितनी भ्रष्ट और निम्न स्तर की है। प्रशासनिक स्तर पर ही हर विभाग में 20 प्रश से 33 प्रश तक स्थानांतरण होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भ्रष्टाचार और निकम्मेंपन पर न केवल लगाई जा सके वरन् कर्मियों में चुस्ती दुरुस्ती और भय के साथ भ्रष्टाचार के लिए जमावट और संबंध क्षेत्रीय स्तर पर न बन सकें।अप्रैल के महीने में 4 उपसंचालक धार, रतलाम और झाबुआ आदि को बिना नोटशीट लिखे कृषकों को अनुदान आबंटन करने और भ्रष्टाचार के मामलें में निलंबित किया गया था, परन्तु इस प्रकार की जालसाजियां न केवल इंदौर में वरन् पूरे मप्र के हर जिले के विभागीय कार्यालयों में धन की ऐसी बंदरबांट खुलकर वर्षों से चल रही है, सबको हिस्सा मिल रहा है तो चुप है।इंदौर में तो भ्रष्टाचार करने और इन 12 योजनाओं के अंतर्गत 40 से ज्यादा कार्यक्रमों के पैसे के अतिरिक्त हर योजना के प्रचार-प्रसार और अन्य कार्यों यथा कम्प्यूटर यात्रा भत्ता बिल, संलग्न वाहनों के रखरखाव आदि के भी करोड़ों के आबंटन में से मोटा हिस्सा डकारा जाता है, जिसके बारे में समय माया ने पहले भी विस्तृत जानकारियां प्रकाशित की है। चूंकि सारे हरामखोरों की फौज को धन चाहिए, चाहे मु.मं., मंत्री से लेकर क्षेत्रीय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों, बाबु, चपरासी तक जिनके फर्जी यात्रा बिलों का भुगतान करके मुंह बंद रखा जाता है, इसलिए किसी के भ्रष्टाचार का यथार्थ नहीं बताना चाहता।

मप्र लोक निर्माण विभाग बनाम भ्रष्टाचार निर्माण विभाग

भ्रष्टों, जालसाजों को संरक्षण-काम कैसे भी हो

मु.मं. से प्र.स. प्रमुख अभि. सबको चाहिए धन,इसलिए भ्रष्टों को खास जगह बैठाया गया, 10 विभागीय जांच वाले को सिंहस्थ संभाग की कमान

मप्र के लोग निर्माण विभाग बनाम भ्रष्टाचार निर्माण विभाग में मंत्री सरताज सिंग से लेकर प्र.स. प्रमोद अग्रवाल,सचिव मुख्य अभियंता अग्रवाल से लेकर नीचे उपयंत्रियों तक भ्रष्टाचार का तांडव बदस्तूर जारी है। कोई देखने-सुनने वाला नहीं, भ्रष्ट मंत्री सरताज सिंग ने अपनी कमाई के औरे महीना वसूली के लिए बिना वर्ष में दो बार की जान वाली विभागीय पदोन्नति समिति जो कई बार वर्षों तक नहीं होती, 25 से ज्यादा संभागों में सहायक यंत्रियों को कार्यपालन यंत्रियों के पद पर बैठा दिया ताकि आसानी से महीना वसूली कर सके। बेशक ये प्रभारी बनाने का खेल भी मुफ्त में नहीं हुआ, यह सौदा भी लाखों में हुआ, इसलिए ऐसे प्रभार सौंपने के खेल में भी वरिष्ठता, कार्य दक्षता और कर्मठता का ख्याल नहीं रखा गया इस खेल में महाभ्रष्ट प्रमुख अभियंता प्र. अग्रवाल, प्रस अग्रवाल और मंत्री सरताज सिंग ही थे, यह खेल वैसा ही है, जैसे कि प्र.स. पद पर रहते अरविंद जोशी ने मप्र जलसंसाधन विभाग में खेला था और अरविंद जोशी सभी प्रभारियों से जो का.अ. यंत्री, कार्य. यं. को अ.यं., अ.य. को प्रमुख अभियंता पदों पर बैठाकर महीना वसूली की जाती थी। वहां पर भी ये शूकर इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों ने इसीलिए डीपीसी नहीं होने देते थे, जबकि प्रभारी अधिकारियों से जमकर वसूली की जा सके, वही हाल अब लो. नि.वि. में शुरू हो गया है। अप्रेल मई में किए गए स्थानांतरणों और प्रभार के खेल में जमकर लेन-देन हुआ और भ्रष्टों को खुलकर संरक्षण दिया गया, और वे तीन वर्षों से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर धन खर्च करके ही जमे हैं।

मप्र लो.नि.के सेतु संभागों में, परिक्रिय ई, मप्र सड़क विकास निगम में तो 4-4 वर्षों से ज्यादा समय से भ्रष्ट कार्यपालन मंत्रियों को खुलकर संरक्षण दिया गया। इंदौर के सेतु संभाग में बैठे महाभ्रष्ट जालसाज रा.ना. मिश्रा की देखरेख में बने रहे हर सेतु में मूल्य वृद्धि हजम करने के लिए की जा जा रही जालसाजियों से पूरे संभाग में बने 30 से ज्यादा रेलवे ओवर ब्रिज न निर्धारित से दुगने समय में भी नहीं बन सके, वरन् लागत भी समय बढ़ने के साथ डेढ़ गुनी से ज्यादा हो चुकी है, इस धूर्त की बत्तमीजियों और भ्रष्टाचार के कारण सभी पूर्व के मंत्री सख्त विरोध में थे, परंतु कांग्रेस के समय में विधानसभा अध्यक्ष रहा श्रीनिवास तिवारी इस रेवाड़ी से बचाता रहा तो अब इसका आका रेवाड़ी राजेंद्र शुक्ल इसको बचाता है, जबकि इसके कार्यों से न केवल इंदौर के जिलाधीश रहे आकाश त्रिपाठी से लेकर अन्य जिलों के जिलाधीश जिसमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बुरहानपुर के साथ संभागायुक्त भी न केवल नाराज रहे वरन् उन्हें भी जनता के धरना प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है, इसका यहां पर रहते हुए निलंबन भी हुआ, स्थानांतरण भी हुआ, परंतु षड़यंत्रों, जी हजूरी और धन के दम पर ये टस से मस नहीं हुआ, दूसरे उदाहरण में का.यं. राणे जिसने देवास, धार, सं.क्र. 2 व 1 में अपने भ्रष्ट कार्य शैली से भ्रष्टाचार के झंडे गाड़कर अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया, हर कार्य में घोटाले किए। देवास, धार, इंदौर1,2 संभागों में 90 प्रश सड़कों में दोनों तरफ बनाई जाने वाली कच्ची पट्टियों का पूरा पैसा ठेकेदारों के साथ मिलकर हजमकर लिया गया, सड़कों की गड्ढों की भुराई और मरम्मत में 4 संभागों में पैसा हजम करने के कारण अनेकों शिकायतें हुई। सं. 2 में रहते हुए अंबेडकर भवन महू में लोकायुक्त जांच भी बैठ गर्ठ थी। इंदौर उज्जैन सड़क में भी बंदे ने 40 प्रश पैसा हजम कर लिया, क्योंकि सड़क, मप्र सड़क विकास निगम को अंतरित होना निश्चित था। सं.क्र. 1 में इंदौर में रहकर अधिकांश पैसा हजम कर लिया गया। सरकारी भवनों, जमीनों जिन पर निजी क्षेत्र का कब्जा है, किराए और पट्टा किराया तक में भारी जालसाजियां की गई यहां तक कि 40 से ज्यादा कार्यभारितें को रु. 50 हजार से लेकर ढाई तीन लाख के भुगतान कोषालय से करवाकर हजम कर लिए गए, जिन्होंने कभी लो.नि.वि. में किसी भी रूप में नौकरी ही नहीं की थी, ऐसी सारी जाली भुगतानों को निकालकर अधिकांश दस्तावेज और फाइले इनके संरक्षण में ही गायब या नष्ट कर दी गई थी, इसकी जारी जांच कोषालय में प्रस्तुत बिलों और दस्तावेजों से ही संभव है, जो वास्तविक कार्यभारित कर्मचारी समूह बीमा के हकदार थे उनके नाम से रु. 50000 निकाले तो भुगतान मात्र रु. 25 से 3000 ही किया गया, फिर जहां भी ये रहा अपने भाई को दूसरे नाम से ठेकेदारी करवाकर करोड़ों रु0 के हर वर्ष भुगतान करवाता रहा, जो कि अवैध था। अभी भी इंदौर के सं.क्र. 1 व 2 में वह ठेकेदारी कर रहा है। अब जबकि ये परि.क्रि.ई. इंदौर में ही है, एमटीएच कंपाउंड की चिकित्सालय भवन में ठेकेदार कं. को फाउंडेनशन में निर्धारित से आधी खुदाई, स्वाभाविक है आधा निर्माण कर बिल में नक्शेनुसार वसूली की गई। जहां ब्रिक्स लगानी थी बीच में भट्टा ईंटों का उपयोग किया जबकि भुगतान वले का ही किया गया पूरा, फाउंडेशन में 7000-8000 घन मीटर खोदा गया, जबकि भुगतान 15000 घन फुट का किया, इसकी मोटाई 70सेमी होनी थी जो मात्र 45 से भी जिसका रु. 70 लाख हजम कर लिया गया, यही हाल लोहा व सीमेंट डालने में किया गया, क्रांकीट मिक्सर और कांक्रीट ढुलाई में भी 10 किमी की अधिक लीड देकर भी रु. 10 लाख से ज्यादा का भुगतान करवा दिया गया। इस का.यं. राने ने रु. 2 लाख के कामों में बदलकर भी देवास, धार, इंदौर 1 व 2 मं करोड़ों रुपए के घोटाले किए और अपने भाई को फायदा पहुंचाया। इसके कार्यों की जांच करवाई जानी चाहिए। 2013 के विधानसभा 2014 के लोक सभा चुनाव में 50 से ज्यादा ठेकों को रु. 2 लाख में परिवर्तित कर करोड़ों रु. हजम करने और करवाने में भूमिका निभाई, फिर स्टॉफ के कई सदस्य यहां ठेकेदारी करते हैं। यहां अ.य. के पद बैठा भ्रष्ट बीएल जैसे बालकों को भी तीन वर्ष से ज्यादा गुजर चुके हैं। वैसे तो इनके भ्रष्टाचार का भी लंबा इतिहास है। वर्तमान में भी हर समय वृद्धि, महंगाई के भुगतान के मुद्दों पर, सुनवाई आदि में भी बिना कमीशन लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। सूचना के अधिकारों में अपील की सुनवाई में भी जमकर वसूली कर इनके अंतर्गत आने वाले इंदौर के 3 संभागों, चार झाबुआ, आलीराजपुर आदि 6 संभागों में भी आवेदकों को भी जानकारी मांगने की अपीले बाहाना ढूंढ कर रद्द कर दी जाती है। यदि जानकारी देने का आदेशकर भी दिया तो भी महीनो तक जानकारी नहीं दिलवा पाते, इंदौर 1 व 2 व धार की जानकारी महीनों से लंबित है। संभाग 2 जो अब रा.रा. संभाग बन गया है, यहां बैठे का.यं. माथुर को भ्रष्ट कार्यशैली से एक तरफ पूरा स्टाफ परेशान है, तो दूसरी तरफ अधिकांश ठेकेदार, ठेकेदारों का कहना है कि यह का.य. पैसे भी हजम कर लेता है और बिल भी पास नहीं करता है। घंटो बैठाकर ठेकेदारों को परेशान करना, इसकी आदत बन चुका है। तीसरे कार्यपालन यंत्री है, जो विद्युत यांत्रिकीय चटर्जी इनके पास आठ जिलों की विद्युत यांत्रिकीय निर्माण स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी है जिसमें हजार से कार्यालय भवन, 10000 से ज्यादा मप्र सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के आवासों में विद्युत आदि के कार्यों में हर वर्ष रु. 10 करोड़ तक हजम कर जाते है। समयमाया द्वारा उपयंत्रियों, सहा.यंत्रियों व अन्य स्टाफ की पदोन्नतियों के संबंध में इनके द्वारा लगातार कहे जाने पर जो समाचार लगाए हुए थे, उसके सार्थक परिणाम सामने आए और 25-30 वर्षों से ज्यादा समय एक ही पद पर कार्य कर रहे को पदोन्नतियां दी गई, जब वादे के अनुसार प्रतिफल चाहा गया तो हर बार की तरह सारे भ्रष्ट, वादाखिलाफी कर गए।

रिंग रोड चौराहे से मांगलिया टोल तक बनने वाली सड़क जो ढाई सान में बनना थी 5 वर्ष बाद भी अधूरी है। दूर्घटनाओं को जन्म दे रही है, पर मु.अ. और अ.यं. आंख भींचकर अपना कमीशन हजमकर उसे समय विस्तार दे रहे हैं। यही हाल हर बड़े कार्यालय का है, उज्जैन सिंहस्थ संभाग में का.यं. केलकर जिस पर 10 विभागीय जांच भ्रष्टाचार में ही लंबित है परंतु फिर भी धन के बल पर ही महत्वपूर्ण पद पर भ्रष्टाचार के लिए बैठाया गया है।

साप्ताहिक समय माया

ताप और जल विद्युत उत्पादन ही जरूरत से ज्यादा, फिर भी विद्युत क्रय, केवल मोटे कमीशन और उपभोक्ताओं को लूटने के लिए

जानबूझकर कटौती करना, कभी मीटर, डिब्बे, केबल बदलने के नाम वसूली

कं. पूरा तंत्र ध्वस्त करेगी, कमीशन पर बनते है बिल

समय माया समाचार पत्र ने विद्युत मंडलों को बांटकर कंपनियों में बदलने और निजी हाथों में सौंपकर लूटने के जिन षड़यंत्रों के बारे में जैसा छापा था वर्तमान में बिलकुल वैसा ही उपभोक्ताओं के साथ ये विद्युत कंपनियां षड़यंत्र कर स्वयं वहां बैठे धूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों से लेकर नींचे लाइनमेन, उपयंत्री, मीटर रीडर्स से लेकर मुख्य अभियंता तक अपनी कमाई में जुटे रहकर, विद्युत वितरण कंपनी में हजारों करोड़ के घाटे दिखाकर और विद्युत नियामक के माध्यम से बिजली की कीमतें हर साल जनता पर थोपकर लूट रहे हैं।

पहले हमारे प्रदेश का मु.मं. शिवराज कहता था कि बिजली कमी के कारण मंहगी बिजली खरीदना पड़ती है, परंतु यथार्थ इसके विपरीत था कि प्रदेश के ताप और जल विद्युत उत्पादन गृहों से बिजली का उत्पादन अधिक था, जिसको सस्ते में दूसरे प्रदेशों को बेंचकर जानबूझ मोटा कमीशन हड़पने के लिए बिजली की कमी बताकर, निजी टाटा, अंबानी व अन्य कईयों से न केवल ताप, पवन, विद्युत खरीदी जा रही थीं और है, समय माया ने भी पिछले अंकों में खुलासा किया था कि रु. 9000 करोड़ की विद्युत खरीद रु. 3000 करोड़ से ज्यादा का कमीशन डकारा गया, समय माया ने वर्षों पहले लिखा था कि यहां बैठे इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी जो प्रबंध संचालक के रूप में बैठाए जाते हैं।

हजारों करोड़ हर वर्ष डकार कर जानबूझकर इन विद्युत वितरण कंपनी में घाटा दिखाकर उस लूट और डकैती को जनता के सिर पर थोपने के षड़यंत्र रचकर हर वर्ष विद्युत की कीमतें विद्युत नियामक आयोग में बैठे उस सेवानिवृत्त शूकर राकेश साहनी को अपने हिस्से की कमाई समर्पित कर अपनी घाटे वाली जालसाजीपूर्ण आंकड़ों से युक्त चिट्ठे के माध्यम से भारी घाटा दिखाकर बढ़वा लेते हैं। जो कि पूर्णतः जनता के साथ सरकारी लूट का षड़यंत्र होता है, जिसमें इन धूर्त पाखंडी मु.मं. शिवराज का भी हिस्सा होता है।

दूसरी तरफ विद्युत कं. को निजी पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने के लिए ग्रिड सेपरेशन में रु. 950 करोड़ बर्बाद किए जिसमें भी निजी कंपनी के ठेको के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए हजम किया गया, अब दीनदयाल योजना जो कि रु. 1200 करोड़ की है, इसमें भी 75 प्रश पैसा हजम करने का षड़यंत्र है, जिसमें गांवों को बिजली देने के नाम पर कार्य योजना बनाई गई है, कर्मचारी संघों के अनुसार, अधिकांश सेवानिवृत्त इंजीनियरों को या तो संविदा नियुक्ति पर रखकर उनसे ये सारे जालसाजीपूर्ण कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है, या उन सेवानिवृत्त इंजीनियरों ने अपनी निजी कं. बनाकर उनके ठेकों में फर्जी बिलों का भुगतान कर प्रबंध संचालकों से लेकर नीचे तक अरबों रु. की बंदरबांट की जा रही है, जबकि काम स्तरहीन होने के साथ ही औपचारिकताएं पूरी करने का ही किया जा रहा है। रखरखाव के नाम पर भी अरबों की खरीदी लाइनों के रखरखाव के नाम पर अधिकांश कार्य ठेकों पर करवाने के साथ ही ग्रामीण, कीडरों, विद्युत केंद्रों पर भी बिना विद्युत कार्यों का प्रशिक्षण दिए, ठेकेदारों कं. ने जो कर्मचारी बैठाए गए हैं, उनसे न्यूनतम 9 से 12 घंटे काम लिया जाकर न्यूनतम मजदूरी भी भुगतान नहीं की जा रही है। जबकि उन गैर प्रशिक्षित कर्मचारियों से गैर कूाननी काम भी करवाए जाते हैं। विद्युत चोरी से लेकर विद्युत कटौती करवाना ग्रामीणों को परेशान करना आदि भी शामिल होते हैं। निष्कर्ष यह है कि ये कं. विद्युत वितरण कंपनी अपने यहां वर्षों से कर्मचारियों और अधिकारियों, इंजीनियर्स आदि की आवश्यकतानुसार न तो भर्तियां कर रही है, ताकि रखरखाव का कार्य सुचारु रूप से किया जा सके, जबकि ठेकेदार कं. के कर्मचारियों को प्रशिक्षण में पैसा भी नहीं लगाना चाहतीं। जिससे रखरखाव का न केवल खर्च बढ़ रहा है, वरन् सुचारु तरीके से विद्युत आपूर्ति भी न की जा सक रही है। इसके पीछे इन कं. के प्रबंध संचालकों का दिमाग एक तरफ निजीकरण की तरफ धकेलना है तो दूसरी तरफ ठेकेदारों के माध्यम से मोटा कमीशन हजम करना है। वर्तमान में पूरे पश्चिमी परिक्षेत्र के इंदौर, उज्जैन संभाग में ही अरबों रु. के ठेकों से कं. विद्युत पोलों को बदल रही है। जिसमें पोल लगाने के मापदंडों को पूरा करने की तो दूर खंभे इतने घटिया स्तर के उपयोग में लाए जा रहे हैं कि उन पर केवल लगाने से पूर्व ही टेढ़े हो जाते हैं। घरों में मीटर तक लगाई जाने वाली केबल लगाने वाले ठेके के कार्यकर्ता न तो प्रशिक्षित है, अव्यस्क लड़कों को भी काम पर लगा लिया गया है साथ ही ये छोटे ठेकेदार भी उल्टे सीधे तरीकों से केवल औपचारिकताएं ही निभा रहे हैं। अर्थिंग के वायर से लेकर केबल तक इतनी घटिया स्तर की होती है कि फिटिंग के साथ ही कटने फटी दिखती है, फिर इस केबल, अर्थिंग के तार आदि की फिटिंग भी काम चलाऊ तरीके से पूरे इंदौर के साथ पूरे प्रदेश में की जा रही है। बिजली कंपनी का कोई भी स्थाई कर्मचारी उपयंत्री, सहा. यंत्री तक इन ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य, उपयोग की गई सामग्री आदि की देखरेख करने वाला भी नहीं है। जबकि इन सबके हजारों के बिल ये जालसाज कं. उपभोक्ताओं से ही वसूलेगी, वही हाल मीटर पर पुराने मीटरों को, जो कि दीवारों पर लकड़ी के बोर्ड पर लगे थे, उखाड़कर सीधे ही इन ठेकेदारों ने दीवारों पर ही होल करके पतले प्लास्टिक के बिना सील किए कवर लगा दिए गए हैं। बाद में आसानी से बिजली कं. के वे ठेके के कर्मचारी उपभोक्ता पर बिजली चोरी का आरोप लगाकर वसूली का नोटिस थमा देंगे। दूसरी ओर बरसात में दीवारें गीली होने पर करेंट फैलने से उपभोक्ताओं की थोड़ी सी भी नासमझी में मौत भी हो सकती हैं।

पूंजीपतियों और ठेकेदारों की रखैल भाजपा अपना मोटा कमीशन हजम करने के लिए विद्युत मंडल की इन वितरण कं. में जिस तरह से इन धूर्त सफेदपोश शासकीय डकैत आईएएस को प्रबंध संचालक बनाकर बैठाती है। उनका मूल उद्देश्य केवल मोटा कमीशन खोरी करना है, जिसकी भरपाई में जनता को न केवल कीमतें बढ़ाकर, वरन् दोगुने से लेकर हजारों गुना बिल भेजकर मनमर्जी से वसूली करना है। झोपड़ी में भी लाखों से लेकर बिहार की बिजली कंपनी ने करोड़ों के बिल भी भेजे हैं। बिलों के भुगतान न होने की दशा में उपभोक्ताओं की गिरफ्तारी करना, लोक अदालतें लगाकर, जो पूर्णतः जालसाजी पूर्ण बिजली, फोन, बीमा, बैंकों आदि के जालसाजों से भरी होती है। उसे धमकाकर 50 से 70-90 प्रश तक के समझोते कर जमा करवा ली जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि बिजली कं. में मचे लूटपाट के तांडव की कोई देखने वाला ही नहीं है। रखरखाव के नाम पर भी केवल खानापूर्ति की जा रही है, यदि इन कं. को समाप्त कर पुनः मंडल के हाथ में कमान नहीं सौंपी गई तो ये कंपनियों में बैठे धूर्त शूकर आई.ए.एस. अपनी नोंच-खसोंट से न केवल इस विशाल संस्थान को खोखला कर देंगे वरन् उचित रखरखाव यथा 25 से ज्यादा वर्षों से खड़ी पारेषण लाइनों के टॉवर तक बिना ताम्र और एल्युमिनियम पेंट की पुताई जो हर पांच वर्ष में होनी चाहिए, 15-20 वर्षों से नहीं की गई है। जंग खाकर खंभे, टॉवर टूटने की कगार पर पहुंच जाएंगे, छोटे से लेकर 220 कि.वा. तक के ट्रांसफार्मस में समय पर तेल पानी नहीं मिलने से हजारों ट्रांसफार्मस ध्वस्त होते जा रहे हैं। पर किसी को चिंता नहीं है, इस प्रकार से नई खरीदी में मोटा कमीशन हजम कर भार जनता पर थोप दिया जाएगा, जबकि महीनों, सालों तक ग्रामीणों को ट्रांसफार्मस के अभाव में बिजली नहीं देते, इस बीच दलालों को पहुंचाकर ग्रामीणों से चंदा इकट्ठा करवाकर ये बिजली कंपनी के कर्मचारी हजम कर जाते हैं।

बिजली बिलों की दुगुनी 10 और 100 गुना तक वसूली के पीछे जो कारण सामने आया है, तो इन हरामखोर प्रबंध संचालकों से लेकर नीचे बैठे मु.अ.अ.य. व कार्य.यंत्रियों की जालसाजी और लूट का नायाब नमूना है, जैसा कि पीछले समाचार पत्रों में यह प्रकाशित किया गया था कि अधिकांश कार्य नेताओं, मंत्रियों सेलेकर यहां बैठे या सेवानिवृत्त हो चुके जालसाजों की ठेके की कं. के माध्यम से अधिकांश कार्यों को आउटसोर्सिंग में करवाकर लूट पाट की जा रही है। बिलों के बनाने वाले ठेकेदार कं. जो सांसद सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार महाजन की कंपनी को प्रति बिल के रु. 1 या 2 के हिसाब से भुगतान किए जाने की अपेक्षा बिलों को राशि के कुल भुगतान पर आय की गणना की जाती है, अर्थात उपभोक्ताओं के मीटर वाचन से यदि रु. 2000 करोड़ की राशि के यदि 2 लाख बिल बने तो रु. 2 प्रति बिल के हिसाब से 4 लाख ही बिल भुगतान किया जाता है। स्वाभाविक है कं. बिल बनाने वाली ठेका कं. अधिकतम भुगतान प्राप्त करने के लिए रु. 2000 करोड़ के बिलों को औसतन 3 गुना रु. 6000 करोड़ के बिल बनाती है ताकि उसे रु. 60 करोड़ मिल सकें, ताकि रु. 20 करोड़ कमीशन भी बांटना पड़े तो भी रु. 40 करोड़ तो बचेंगे, ये हाल इन जालसाजों ने पूरे देश में करके जनता से पूरे देश में रु. 1 लाख करोड़ की खुली लूट की जा रही है और उपभोक्ता ज्यादा बिल आने पर आत्महत्या तक कर रहा है, पर धूर्त मक्कारों को क्या फर्क पड़ता है, इन धूर्त गिद्धों को तो लूटने से काम, बिलों की अंटशंट वसूली न मिलने या विरोध करने पर सशस्त्र पुलिस बल से मारा-पीटा खदेड़ा जाने के साथ गिरफ्तार कर कारागृहों में डालकर यातनाएं देना इस लोकतंत्रों के डकैतों का परम ध्येय बन चुका है।

नेपाल और भारत में लगातार आए भूकंप के झटके

प्रथम पृष्ठ का शेष

इसके विपरीत मोदी ने देश की रक्षा के प्रति सार्थक प्रयास करना शुरू किए हैं। फिर चीन से भारत की सीमा 4200 किमी लंबी है, छोटा-मोटा खेल नहीं,साथ ही चीन को घेरने के लिए मंगोलिया की यात्रा और 1 अरब डॉलर का दान, मुफ्त में नहीं दिया गया। वियतनाम, जापान, कोरिया से मित्रता का हाथ बढ़ाकर भी यथार्थ में चीन को घेरने का ही प्रयास किया है, जो शायद मोदी के दूरगामी सार्थक प्रयास है। इस शृंखला में वियतनाम जापान भी चीन के न केवल पुराने ऐतिहासिक शत्रु है, वरन् चीन वर्तमान में इनका नाम सुनकर बौखलाता है।

चीन में अरुणांचल और आसाम से लगी अपनी सीमा में जो 24 बांध जल संग्रहण के लिए बनाए है, आखिर उसमें पानी तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से लाना है,इसलिए जो पानी अभी बाग्लादेश और बंगाल की तरफ बहता है उसके बहाव को मोड़ने के प्रयासों की शृंखला का हिस्सा है, नेपाल और भारत तक जो भूकम्प जो नेपाल की सीमा में सतह से 8 से 15 किमी नीचे परमाणुीतय और नाभिकीय विस्फोटकों के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हुए हैं। समाचार पत्रों में छपी सूचनाओं से सिद्ध होता है कि इसके पूर्व 800 वर्षों में भी ऐसी भयानक तीव्रता के भूकम्प कभी नेपाल में नहीं आए, परंतु फिर प्राकृतिक भूकंपों मेंएक बड़े झटके के बाद 3-4 दिन तक छोटे-छोटे कम त्रीवता के झटके आकर बंद हो जाता है, परंतु यह प्राकृतिक भूकंप न होने के कारण झटके लगातार आ रहे हैं। क्योंकि अंदर हुए अप्राकृतिक विस्फोटकों से धरती के अंदर की चट्टानों की मोटी परतों को समायोजित होने से समय लगा, यह समायोजन नहीं भूकंपों के लगातार आने के कारण हुआ है।

नेपाल में चीनी घुसपैठ पिछले 50 से ज्यादा वर्षों से लगातार जारी है, और सत्ता में अच्छी पकड़ है। यही कारण है कि चीन के इस यथार्थ का पता मय सबूतों के अन्य राष्ट्रों का न लग जाए। चीन ने नेपाल की सरकार पर दबाव डलवाकर 40 से ज्यादा देशों से आधी सहायता और सहायता कर्मियों को 5-7 दिन के बाद ही वापिस लौट जाने को कहा, और बहाना बनाया गया कि, भारत व अन्य देशों के सहायताकर्मी नेपाल की जनता की सहायता के बहाने अपमान कर रहे हैं।

समय माया डॉट काम ने अपनी साइट पर 26 अप्रैल को ही इस सच्चाई को डालकर पूरे विश्व में ई-मेल से सूचित कर दिया था। स्वाभाविक है इस यथार्थ की खबर उसे लग चुकी थी, इसीलिए उसने नेपाल पर दबाव डलवाकर सारे सहायताकर्मियों को अपमान का आरोप लगवाकर बाहर जाने को मजबूर कर दिया, अन्यथा उसे डर था कि सहायताकर्मी इस बहाने सत्यता के प्रमाण इकट्ठे कर दुनिया के सामने रखकर चीन की बत्तमीजियों की पोल न खोल दें, क्योंकि पहले से अपने इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर माल, विद्युत सामग्री, ऑटोमोबाइल, दवाइयों, गारमेंट, की घटियापन, असामायिक मिलावटी और जालसाजी के साथ उपभोक्ता की जासूसी के आरोपों और प्रमाणों से दुनिया में साख बिगड़ी हुई है और भूकम्पों का ये सच सामने आने पर दुनियाभर के देशों के शिक्षित और संवेदनशील नागरिक सारे माल का बहिष्कार कर चीन की अर्थव्यवस्था ही चौपट न कर दें।

चीन और जापान ऐतिहासिक चिर शत्रु है। 11 मार्च 2011 को जापान में आई सुनामी भी, जो चीन ने जापानी तटों पर के निकट समुद्र तक में फोरे नाभिकीय और परमाणु बमों का ही परिणाम थी, जिसके बारे में में भी समय माया ने अपने अंकों में तथ्य प्रकाशित किए थे।

कहानी की पहली शुरूआत अमेरिका ने 26/12/2014 को सुमात्र मलाया, इंडोनेशिया के तटों के निकट समुद्र में बम फोड़कर जो सुनामी लाई गई थी से की थी, तब भी समय माया ने 27 दिसम्बर 2004 की रात्रि 12.30 पूरी दुनिया को इस यथार्थ की जानकारी थी। जिसमें समय माया के हाथ लहरों में लपटों जो 200 फूट से ऊपर निकली थी, इंटरनेट साइट से लगाने के साथ ही लहरों का एशिया में भारत से लेकर उसके दिशा के विपरीत आस्ट्रेलियाई महाद्वीप तक जाना, लहरों की गति प्राकृतिक तूफानों में 250-300 किमी प्रति घंटे के विपरीत 5 से 7 हजार किमी की लहरों के कारण लगे थे, जिसे साइट पर लोड करने और पूरी दुनिया में ईमेल से भेज देने के कारण प्रभावित देशों को अमेरिका ने अरबों डॉलर की सहायता बांटने 28 दिसम्बर 04 से ही निकल गया था। आखिर अमेरिका ने क्यों बांटी सहायता सुनामी प्रभावित देशों को यदि उसने कुछ नहीं किया था तो दूसरी औरे भारत में बंगाल से लेकर केरल के आखिरी कोने, श्रीलंका में भी पानी समुद्र तटों से 10 से 15 किलोमीटर अंदर घुस गया था, उन लहरों की तबाही के निशान अभी तक मौजूद है। जब अमेरिका ने भारत को सहायता देने की बात कही तो तात्कालीन मनमोहन सरकार ने राष्ट्रीय मंच पर तो अमेरिका की सहायता लेने से यह कहकर मना कर दिया था कि भारत अपने साधनों से इस त्रासदी से निपट लेगा, जबकि वह सहायता मनमोहन ने अपने और सोनिया के अमेरिकी खातों में चूपचाप जमा करवा ली थी। जिसका मोदी सरकार को जांच करवानी चाहिए। अमेरिका के इस कुकृत्य को ऊपरी स्तर पर दुनिया के सारे देशों को मालूम पड़ गया पर जब इसके बारे में दुनियाभर में कोई विरोध की आवाज नहीं उठी तो चीन इस कृत्य से प्रोत्साहित हुआ, उसके ठीक 7 वर्ष बाद चीन ने अपने चिर शत्रु जापान के समुद्र में बम फोड़कर कई सारे बदले लिए, उसके फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को नष्ट कर दिया, इससे बिजली बाधित हो गई और जापानी नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, परंतु वह दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमशील देश है एक महीने में वह भूकम्प के झटकों से उबरने के साथ ही उसने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को भी सुधार लिया था। यथार्थ यह है कि परमाणु बम शक्ति संपन्न राष्ट्र, समय बाधित परमाणु बमों का क्या उपयोग करें। सुनामी लाना और भूकंप लाना ये उन बमों के सदुपयोग है। यदि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन दुष्कर्मों को विश्व के नेताओं ने नहीं रोका तो आने वाला कल भी भयावह होगा, प्राकृतिक आपदाओं की आड़ में दुनिया को नष्ट कर देंगे।

मप्र जल संसाधन विभाग 65 से ज्यादा उपसंभाग किए बंद, काम न होने का बहाना

प्र.स. जुलानिया भी पालते हैं, भ्रष्टों को दूरगामी सोच का अभाव

जल के अभाव में जग जाएगा जल, वर्षा की हर बूंद को सहेजना जरूरी, जरूरी जल, स्थाई भर्तियां करो, वन विभाग के साथ तालमोल बैठाकर, वर्षा जल सहेज प्रदेश के हजारों पहाड़ों पर हरियाली बिछाओ

मप्र जल संसाधन विभाग में प्र.स. जुलानिया के आने से और लंबे समय तक रहने से, विभाग की न केवल छवि सुधरी, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं, पर आर्थिक नियंत्रण की जिद् में कुछ कार्य बेहद निराशाजनक रहे, जिसमें सबसे ज्यादा निराशाजनक था 65 से ज्यादा उपसंभागों को बंद किया जाना दूसरा छोटे बांधों, तालाबों को जमीनों की कीमतों और क्षतिपूर्ति के कारण निरस्त किया जाना, तीसरा शासकीय वन भूमि और वन विभाग से सामंजस्य न बिठा पाना, जिसके कारण जल संग्रहण की पूरे प्रदेश में हजारों प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में डाला जाना, जिनमें करोड़ों रुपए का मानव श्रम और धन बर्बाद हुआ, फिर काम न होने का बहाना बनाकर, इंदौर जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक जिले के उपसंभाग बन्द करने के साथ ही संभागीय कार्यालय को बंद करने का निर्णय लेना। ठीक है, कि अभी वह बंद नहीं किया गया क्योंकि वहां सैकड़ों न्यायालयीन प्रकरण लंबित है, जबकि इंदौर की प्राकृतिक नदियां जिसके कारण यह नगर इतनी समृद्धि पा सका, भूमाफियाओं की हवस, शासन के मक्कार, भ्रष्ट जिलाधीशों आयुक्तों से लेकर पटवारियों तक की नोंच-खंसोट, नेताओं की गुंडागर्दी और रातोंरात करोड़पति बनने की नियत ने न केवल इन नदियों को गंदे नालों में बदल दिया वरन् आजादी के पूर्व जो 55 तालाबों में भी कालोनियां तान दी गई, बचे खुचे 5-7 तालाबों के ऊपर भी भूमाफिया और नेताओं की गिद्ध निगाहें लगी हैं, जबकि उनके जल संग्रहण क्षेत्र में अवैध निर्माण और कब्जे हो चुके हैं। जिस पर न तो जल संसाधन, विभाग कार्रवाई कर पा रहा है, न नगर निगम न राजस्व, यह कहानी न केवल इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, भोपाल, ग्वालियर जैसे बड़े नगरों से लेकर प्रदेश के हर जिले की है, जबकि आबादी हर जिले, तहसील की लागातार बढ़ रही है। मोदी का मेक इन इंडिया, शिवराज का मेक इन एमपी स्मार्ट सिटी जैसे औद्योगिकीकरण, व्यावसायिकरण, विकास सबके मूल आधार में जल है, जल के बिना सारे सपने तो दूर जग भी जाएगा, जल

अकेले इंदौर के नर्मदा ताप्ती कछार में आने वाले 14 जिलों में ही 5000 से ज्यादा जल संग्रहण के लिए तालाब और बांधों के निर्माण की संभावनाएं अभी भी विद्यमान है, जिन्हें जल संसाधन विभाग बेहतर तरीके से न केवल जानता है, वरन् हजारों प्रस्ताव मंत्रालय में वित्त, वन भूमि और निजी भूमि की लागत और मुआवजे के चक्कर में उलझे हैं। यदि वर्तमान में शासन ने इन्हें स्वीकृत नहीं किया तो आने वाले कल में शासन 5 से 10 गुना पैसा खर्च करके भी इन जलाशयों का चाहकर भी निर्माण नहीं कर सकेगा, जबकि आने वाले समय में न केवल जनता को प्रकृति में निवासरत अन्य जानवरों पशु पक्षियों को वरन् पेड़-पौधों के लिए न केवल, मानव आबादी में वरन् वनों में भी जल की आवश्यकता होगी, जबकि बेहतर और चौमासी फसलों के लिए भी घटती वर्षा से भी जल की मांग बढ़ना स्वाभाविक है।

इसके लिए प्र.स. को उपसंभाग बंद करने की अपेक्षा हर तहसील और विकास खंड स्तर पर मप्र जल संसाधन के कार्यालयों को खोलकर और नए उपयंत्रियों व सहायक यंत्रियों की भर्ती कर, क्योंकि 1985 के बाद भर्ती न होने से, 30 वर्षों में जो कमी आई है, टोपोग्राफी और आधुनिक तकनीकों के माध्यम जिसमें वैश्विक स्थिति प्रणाली जीपीएस, उपग्रहों के नक्शे व धरती की वास्तविकता का आंकलन कर जल बहाव, नदी, नालों पर बांधों जलाशयों के प्रस्तावों को तैयार किया जाना चाहिए, ताकि बड़वानी, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम के साथ ही पूरे प्रदेश में 80 प्रश पहाड़ियों, पहाड़ों पर से बहने वाले वर्षा जल की संरक्षित किया जाकर देश प्रदेश को हरियाली की चादर पुनः ओड़ाई जा सके, अन्यथा 80 प्रश पहाड़ियां, पहाड़ मुंडी होकर देश-प्रदेश के तापमान को बढ़ा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि बुरहानपुर, बड़वानी में तापमान 47-48 डिग्री से. तक पहुंचना, जबकि भू-जल स्तर 800 से 1200 तक नीचे जा चुका है, फिर यही संचित जल न केवल भूजल स्तर बढ़ाएगा वरन कृषि की सिंचाई के साथ ग्रामीणों और नगर वासियों के लिए पेयजल स्त्रोत के रूप में वर्ष भर पानी दे सकेंगे साथ ही उद्योगों को भी पानी मिल सकेगा।

वर्तमान की देश की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार जिस औद्योगिकीकरण और रोजगार की बात कर रही हैं, ये सब जल के बिना बेमानी है। मप्र जल संसाधन विभाग प्र.स. राधेश्याम जुलानिया के रहते इस विभाग को केवल कृषि की सिंचाई तक रखने की अपेक्षा नगरीय आबादी, औद्योगिकीकरण के लिए जल की व्यवस्था के साथ ही वनों में भी प्राकृतिक पशु-पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए भी जल स्त्रोतों की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

प्र.स.रा.र. जुलानिया ने मप्र जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार को एकदम समाप्त कर दिया हो, या भ्रष्टों को संरक्षित न किया हो, ऐसा भी नहीं है। इनके रहते हुए भी वर्तमान में खरगोन मंडल कार्यालय में बैठा बागोरा खरगोन संभाग में ही सन् 2000 से पहले से सहा. यंत्री था। 2202-03 में वही कार्य. यंत्री बना और अब 2010 में अ.य. भी वहीं है। इस जालसाज ने 20 से ज्यादा जलाशयों के कार्यों में, एक ही कार्य की दो से ज्यादा बार निविदाएं निकालकर, पुराने कार्यों में भी एक, ही निविदाएं निकालकर, पुराने कार्यों को बंदकर पैसा हड़पा। ठेकेदारों के साथ मिलकर और नई निविदा निकालकर फिर कार्य शुरू करवाया, अधिकतम कार्यों में पुराने ठेकेदारों को ही फिर वहीं कार्य सौंपा गया, एक संभागीय लेखापाल ने ऐसे कार्य के बिलों पर हस्ताक्षर करने से मनाकर सीधे जुलानिया को भी सूचित किया था, इसके बाद भी इस जालसाज की न तो इसके कार्यकाल की सन् 2000 से जांच ही करवाई, न ही इसका स्थानांतरण किया, यहां भ्रष्टाचार करने के विशेषज्ञ होने के साथ पैसा बांटकर सबका न केवल मुंह बंद करने वरन् अपने आप के भ्रष्टाचारों और जालसाजियों की पोल न खुल जाए, अपने आप को 15 वर्ष से एक ही स्थान पर टिके रहने में भी सफल रहा, माही के दोनों बांधों में भी इसके समय में भारी भ्रष्टाचार हुआ, हर कार्य में समय विस्तार और महंगाई वृद्धि के लाभ भी कमीशन पर खुलबर बांटे गए। सन् 2009 से 2011-12 तक, जिसमें दोनों बांधों के गेट, नहरों के निर्माण, लाइनिंग, बड़ी छोटी वितरणी नहरों के निर्माण में स्वीकृत नक्शे और स्तर के विपरीत भी ढेर सारे कार्यों में शासन को लगभग रु. एक अरब से ज्यादा की क्षति वहां के उपयंत्री सहा. यंत्रियों से लेकर का.यं. और अ. यंत्रियों ने पहुंचाई, स्वाभाविक था इनका हिस्सा भी इन तक पहुंचा, जिसमें बड़ा बाबू जो धार के अ.यं. कार्यालय में धन खर्च कर वहां पर भी अधीक्षक की कुर्सी पर बैठे भ्रष्ट, जालसाज एसके पंवार ने भी भारी भ्रष्टाचार कर कमाई की, इसी से खुश होकर वर्तमान नर्मदा तात्पीकरण के मु.अ. एमएस डाबर धार से इंदौर बुलवाकर मु.अ. कार्यालय का अधीक्षक पद पर बैठाया, फिर सेवानिवृत्ति के बाद भी वसूली और भ्रष्टाचार के गुणों के कारण अब संविदा पर विधि सलाहकार के रूप में मानदेय पर नियुक्त कर दिया, जो अवैधानिक है। स्वाभाविक है कि इस सारे खेल में प्र.स. जुलानिया की मौन स्वीकृति थी, ये तो दो छोटे से नमूने है। जबकि प्रदेश में हजारों करोड़ की बाण सागर जैसे परियोजनाओं के साथ सैकड़ों छोटी योजनाएं प्रदेशभर में चल रही है। जहां खरगोन संभाग जैसे खेलों के साथ समयवृद्धि, महंगाई वृद्धि और स्तरहीन कार्यों को धड़ल्ले से संपन्न किया जा रहा है। जिससे पूरे प्रदेश में अरबों रु. की हानि पूरे प्रदेशभर में हो रही है। अर्थात एक तरफ इंदौर जैसे जिले में जो कि पूरे प्रदेश में विक्रयकर 50 प्रश से ज्यादा राजस्व पूरे प्रदेश में की अर्थव्यवस्था चलाने में देता है वहां पर जमीनों की कीमत, टीकमगढ़ की जमीनों रु. 20 लाख प्रति है. से आंकलन कर, जलस्त्रोत, जलाशयों के निर्माण नहीं किए जाते, दूसरी तरफर अरबों रुपए समय, मूल वृद्धि व अन्य प्रकार की जालसाजियों में बर्बाद किए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज, मु.स. एंटनी डिसुजा को इंदौर को रु. 25000 करोड़ से ज्यादा के प्रदेश के राजस्व और टीकमकगढ़ के रु. 300 करोड़ के राजस्व दिखाई नहीं देते, जबकि राष्ट्रीय राजस्व में आयकर केन्द्रीय आबकारी आदि को भी इंदौर से पूरे प्रदेश में राजस्व का आधे से ज्यादा मिलता है, फिर अगर इंदौर की जमीनों की कीमत रु. 2 करोड़ प्रति है. है, तो कौन सी नई अजूबी बात है।

दूसरी ओर इंदौर के 25 से 50 किमी के दायरें में वर्षा जल एकत्रित करना शासन को और उनके प्र.स. जुलानिया को स्वीकार नहीं परंतु जलूद से 110 फूट से 50 किमी दूर 500 मी. पानी उद्वहन कर लाने और रु. 5 करोड़ से ज्यादा बिजली भी देना मंजूर है साथ ही रु. 800 करोड़ के एडीबी के कर्ज पर रु. 80 करोड़ प्रति वर्ष ब्याज दिया जा सकता है, परंतु 40 इंच की औसत वर्षा के 50 क्यूमेक पानी का 20 प्रश पानी रोकने में रु. 1 अरब जो अगले 25 से 50 वर्ष तक उपयोगी होंगे खर्च करना मंजूर नहीं, नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना में रु. 1900 करोड़ खर्च कर 5 क्यूमेक पानी 55 किमी से वार्षिक रु. 10 करोड़ के बिजली खर्च पर लाने में रु. 200 करोड़ कमीशन बनेगा, जबकि 20 क्यूमेक पानी रोकने में मात्र रु. 200 करोड़ के काम में कमीशन मात्र रु. 20 करोड़, नहीं मजा नहीं आएगा, मत बनाइए वर्षा जल रोकने की दीर्घकालीन योजनाएं, वैसे आज नहीं तो कल, वर्षा जल रोकने की स्थाई व्यवस्था तो न केवल प्रदेश सरकार को पूरे 51 जिलों और केन्द्र सरकार को पूरे देश में करने के लिए करनी ही पड़ेगी। आखिर नर्मदा जैसी प्रदेश और देश की नदियों में जल तो वर्षा का ही बहता है, बेशक हरामखोर जालसाज नेताओं, इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों से लेकर इंजीनियरों को अब कमीशन भी सैकड़ों करोड़ में चाहिए, इसलिए काम हजारों करोड़ का तो होना ही चाहिए, जनता के खून-पसीने की कमाई जो करों से कारावास का भय दिखाकर लूटी जाती है। ऐस ही पिछले 50 वर्षो से बर्बाद की जा रही हैं। चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भुखेरे जन पार्टी की, सब वसूली करने आए हैं। इंदौर मंडल अ.य. के गंधे इतना निकम्मा है कि, जो कार्य बाबुओं ने कर दिया, आंख भींचकर हस्ताक्षर कर देता है।

सूचना के अधिकार में हरामखोर को इंदौर, देवास, शाजापुर की तीन अपीलें की गई, जालसाज ने सबसे धन डकार कर चार महीने बाद बिना सुनवाई किए निरस्त कर दिया, स्वाभाविक था, तीनों का.यं. ने उल्टे ही कहा क्या कर लिया हमारा नहीं देते हम जानकारी, वही हाल मु.अ. डाबर का भी है, वो भी बघेल अ.यं. की जानकारी देना नहीं चाहता, इसलिए बात करने पर कहतें हैं कि जाने दो उनका स्थानांतरण हो गया अब तो, एसके पंवार को पुनः संविदा पर विधि सलाहकार के रूप में नियुक्ति दे दी गई। एक तरफ तो इंजीनियर्स एक ही स्थान पर सहा. यंत्री से कार्य. यंत्री, अधीक्षण यंत्री, 15-15 वर्ष गुजारकर शासन को 500 किमी स्थानांतरितक कर देते हैं। वो नियमित किए बिना, दै.वे.भो. के साथ कौन सा न्याय है। इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधि. जुलानिया, जी 30-40 वर्ष के शोषण के उपरांत सेवानिवृत्ति के मुहाने पर खड़े दैनिक वेतन भोगी निर्धन छोटे कर्मचारियों को कैसा दंड दिया जा रहा है।

न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुओं के अड्डे हैं भू.पू. राष्ट्रपति के आर नारायण

सलमान और जया के प्रकरण में उच्च न्यायालयों में सिद्ध हुआ

फिर हर सत्ताधीश चाहता है कि न्यायिक प्रक्रिया उसके हिसाब से नाचे

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व. केआर नारायणन ने 25 जन 2002 को अपने भाषण में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर सीधा कटाक्ष किया था और कहा था कि न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुएं के अड्डे हैं। यहां जो जितना धन लगाएगा, उसे उतना न्याय मिलेगा, यह तथ्य भारत के दैनिक समाचार पत्रों ने अपने पत्रों में प्रथम शीर्षक से छापा था, वैसे यह भारतीय न्यायपालिका की कार्यप्रणाली का सारांश अपने आप में परिपूर्ण है जिसकी व्याख्या की आवश्यकता तो नहीं परंतु इस तथ्य की स्वमेव हर दिन आने वाले जिला न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से स्पष्ट पुष्टि हो जाती है, जहां एक और शराब के नशे में गाड़ी चलाकर मुंबई के फुटपाथ पर सोते 7 निरीहों की हत्या कर दी जाती है, निचली अदालत में 13 वर्ष मुकदमा चलता है, निचली अदालत ने जबकि पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर थानेदार ने मोटा धन लेकर न केवल प्रकरण को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश वरन अपने ही कांस्टेबल को जो चश्मदीद गवाह था, को तोड़ने की कोशिश और गवाह बदलने की भी कोशिश करवाई गई, ब्यान न बदलने पर उसे मानसिक विक्षिप्त करार दे दिया गया, 2-3 न्यायाधीश और अदालतें बदलने के बाद भी सलमान को सजा सुना दी, उस माफिया और अपराधी पर राजस्थान के जोधपुर की अदालतों में प्रकरण वर्षो से चल रहे हैं, क्यों? मुंबई की निचली अदालत से फैसला होने के बाद, उसे उच्च न्यायालय ने तुरंत जमानत दे दी, आखिर उस न्यायाधीश के मोबाइल फोन और चारों तरफ के माहौल के ऊपर निगरानी और जांच क्यों नहीं की गई, जहां आम आदमी की फाइले केस डायरी, पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। क्योंकि हर फाइल खिसकाने पहुंचाने का बाबु-चपरासी से लेकर हर कदम पैसा लगता है। पुलिस भारत में कहीं की भी हो, किसी भी स्तर की हो, उसे भी हर कदम काम का पैसा चाहिए, पूछताछ के बहाने उठाती है, फिर कपड़े देने और खाना के भी 2-5 हजार चाहिए, न्यायालयों में भी पुलिस जो केस डायरी प्रस्तुत करती है उसी पर कार्रवाई और प्रकरण की सुनवाई होती है, चाहे वो पूरा झूठा, आंशिक झूठा हो, फिर निर्बल और निर्धन तो बड़ा वकील खड़ा कर नहीं सकता, स्वाभाविक है अपराधी मोटा धन खर्च करके पुलिस से लेकर जो प्रकरण ही कमजोर कर देती है, वकील तक अच्छा खड़ा करके कानूनी उलझनों का फायदा उठाकर बच निकलता है। जया के प्रकरण में भी जांच एजेंसियों ने आय से ज्यादा संपत्तिया बरामद की।

13-14 वर्षो तक प्रकरण चला और निचली अदालत में सजा भी दी परंतु उच्च न्यायालय ने तत्काल जमानत देकर मुक्त कर दिया और अम्मा पुनः मुख्यमंत्री बन गई, अर्थात उच्च न्यायालय भ्रष्टों और अपराधियों को बचाने का अड्डा बन गए, जिसे स्वयं भूतपूर्व राष्ट्रपति आर नारायणन ने न केवल स्वीकारा वरन् कहा न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं, जुएं के अड्डे हैं, जो जितना बड़ा दांव खेलेगा उसे उतना न्याय मिलेगा। जो सलमान और जया के प्रकरण में सिद्ध हुआ।

साप्ताहिक समय माया

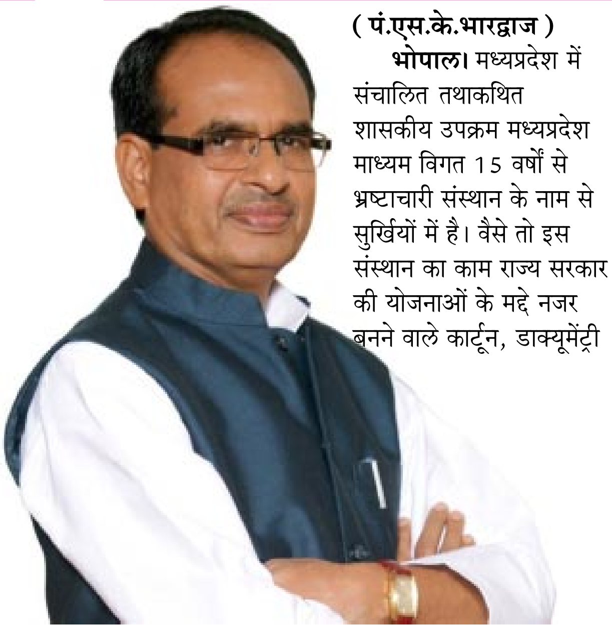

मध्यप्रदेश के मुख
शासकीय उपक्रम है

(पं.एस.के.भारद्वाज)

भोपाल। मध्यप्रदेश में संचालित तथाकथित शासकीय उपक्रम मध्यप्रदेश माध्यम विगत 15 वर्षों से भ्रष्टाचारी संस्थान के नाम से सुर्खियों में है। वैसे तो इस संस्थान का काम राज्य सरकार की योजनाओं के मद्दे नजर बनने वाले कार्टून, डाक्यूमेंट्री फिल्म, विज्ञापनों की डिजाईन आदि करने का मुख्य काम है। परंतु परोक्ष रूप से यह संस्थान सरकारी धन को नीतिगत तरीके से गबन करने का एक प्रभावशाली और मुख्य अड्डा बन गया है। इसके माध्यम से राज्य के छोटे से छोटे मीडिया संस्थान से लेकर देश और दुनिया के नामचीन मीडिया घरानों को परोक्ष रूप से आर्थिक लाभ पहुंचानेवाला संस्थान है। तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के आकाओं और चुनाव में प्रत्याशी अथवा चुने हुए प्रतिनिधि हों सभी के लिए यह मानव शरीर में रक्त संचार जैसे कार्य को अंजाम देने वाला संस्थान के नाम से जाना जाता है। राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन की लगभग हर योजनाओं के प्रचार-प्रसार के बजट और उनके लिए तैयार किए जाने वाले प्रचार-प्रसार के लिए वाहन, बैनर, झण्डे, पम्प्लेट, विभागीय प्रतिवेदन, निगम मंडलों के वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि सहित अन्य प्रसार-प्रचार सामाग्री और संचार से संबंधित कार्यों के नाम पर सरकार के मूल बजट का प्रसार-प्रचार का जनसंपर्क संचालनालय एवं उसके अधीन मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा ही किया जाता है। आम तौर पर प्रदेश में और देश में हर व्यवसायिक और शासकीय उपक्रमों के लिए एक व्यवस्था लागू है कि पूरे वर्ष का लेखा-जोखा और उसका पंजीयन क्रमांक नवीनीकरण, कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों का विवरण जनता के सामने सार्वजनिक किए जाने का नियम लागू है। परंतु मध्य प्रदेश माध्यम में ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। प्रदेश का कोई भी पत्रकार अथवा नागरिक, अथवा विधायक यहां तक की सांसद भी नहीं जानते कि यहां कंपनी है, फर्म है, निजी कंपनी है, अथवा कोई निजी चिटफंड कंपनी इस कंपनी ने हर विभाग से सरकार के

मप्र में शासकीय स्तर पर विद्युत उत्पादन 1-1-15 को कुल उत्पादन 7699 मेगावॉट... खपत मात्र 5 से 6 हजार मेगावॉट

INSTALLED CAPACITY (01-01-2015)

SL.No.	Power Station	Installed Capacity (MW)	M P SHARE (MW)
1	Amarkantak II (2x120 MW)	240	240
2	Amarkantak Extn (210 MW)	210	210
3	Satpura II (200+210 MW)	410	410
4	Satpura III (2x210 MW)	420	420
5	Satpura IV (2x250 MW)	500	500
6	Sanjay Gandhi, Birsinghpur -I (2x210 MW)	420	420
7	Sanjay Gandhi Birsinghpur -II (2x210 MW)	420	420
8	Sanjay Gandhi Birsinghpur -Extn (1x500 MW)	500	500
9	Shri Singaji TPS Dongalia (2x600 MW)	1200	1200
	Total Thermal Power Station Generation	4320	4320
1	Gandhi Sagar(5x23 MW)	115	57.5
2	Pench,Totladoh(2x80 MW)	160	107
3	Rani Awanti Bai Bargi (2x45 MW)	90	90
4	Ban Sagar I Tons(3x105 MW)	315	315
5	Birsinghpur(1x20 MW)	20	20
6	Rajghat (3x15 MW)	45	22.5
7	Ban Sagar II Silpara(2x15 MW)	30	30
8	Bansagar -III Deolond (3x20 mW)	60	60
9	Bansagar -IV Jhinna (2x10 MW)	20	20
10	Madhikheda (3x20 MW)	60	60
Jawaharsagar & Ranapratapsagar Station of Rajasthan (99MW & 172 MW), 50% of 271MW		----	135.5
	Total Hydro Power Station Generation	915	917.5
	Total	5235	5237.5

Sources From www.mp.nic.in

Construction Major Projects

S.No.	Name of Project	Estimate cost(Rs. Crore)	Proposed Potentialt	
			Irrigation(L Ha)	Power generation(MW)
1.(A)	Rani Awanti Bai Lodhi Sagar Project	2260.40	1.57	(i) 90-From River Bed PH (Completed) (ii) 10-From Left Bank Canal Head PH (Completed)
(B)	Bargi Diversion Project (Bargi Right Bank Canal)	4281.55	2.45	
2.	Indira Sagar Project	5877.57	1.23	(i) 1000-From River Bed PH (Completed) (ii) 15-From Canal Head PH (Completed)
3.	Omkareshwar Project	3539.16	1.47	(i) 520-From River Bed PH (Completed) (ii) 4.5-From Canal Head PH (Proposed)
7.	Sardar-Sarovar Inter State Project	3136.00	-	57% Share 826.5 MW (Completed)
8.	Maheshwar Hydro Power Project under construction by private firm under Energy Department	-	-	400 (Under Construction)
	Total	21224.48	7.622	2461.5 (Completed), 404.5 (Under Construction/Proposed)

Total Thermal & Hydro Electric generation installed capacity is 7609 MW generation, while demand is only 6000 to 6500 MW including industrial, agricultural, commercial & domestic demand, even all these distribution cos. unable to this electric power. This data taken from MP Power Gen. Co. & NVDA

1000 मेगावॉट विद्युत अधिक उत्पादन होने पर एक तरफ सस्ती बेची जाती है। दूसरी तरफ रिलायंस, टाटा, अडानी व अन्य से कागजों पर ही 9 हजार करोड़ की बिजली खरीदी गई। और इस प्रकार 90 अरब का घोटाला हुआ। बिजली कमी होने का बहाना बनाकर कीमतें बढ़ाते हैं। बिजली कटौती करते हैं। इस प्रकार ये धूर्त इंडियन एवयूजीन सर्विस के प्रबंध संचालक विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे में दिखाकर बर्बाद करने में तुले हुए हैं।

रु. 5000 करोड़ के लेन-देन से चला स्थानांतरण, पदोन्नति व पदस्थापना उद्योग

पृष्ठ 12 का शेष

उपायुक्त ओपी पांडेय तो एक छापे के दौरान सोने का बिस्कुट जेब में रखते हुए कैमरे में भी कैद हो चुके हैं, इसके विपरीत तो बराबर पदोन्नतियां लेते हुए उपायुक्त भी बनाए गए और भोपाल एंटी इवेजन में भी रु. 25 लाख से ज्यादा खर्च कर न केवल एंटी इवेजन में भी पदस्थ किए गए वरन् अपने पुत्र को भी एंटी इवेजन ए में सहा.वा. कर अधिकारी के रूप में इंदौर में पदस्थ करवा लिया, यहां बैठे प्र.स. मनोज श्रीवास्तव जिनके इंदौर जिलाधीश डीपी जी आयुक्त के समय के भ्रष्टाचार और अय्याशी के किस्से भी काफी समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाए रहे, यही कारण था कि सितम्बर 2014 में की गई विभागीय पदोन्नतियां समिति के लिए गए निर्णयों का लिफाफे मई 15 में जब खोला गया जब प्र.स. से सूचना के अधिकार में सितम्बर 2014 की डीपीसी की छायाप्रतिलिपियां मांगी गई, लिफाफे बंद थे, जिसमें अरबों रुपए का लेन-देन हुआ।यही हाल वित्त और आबकारी, जल संसाधन में पदोन्नतियां, स्थानांतरण आदि में मंत्री जयंत मलैया ने दलालों के माध्यम से तबियत से दोनों हाथों से रु. 5 अरब से ज्यादा की वसूली की होगी, सबसे ज्यादा कमाई आबकारी में जहां अदने से सिपाई से लेकर सहा. उप. आबकारी निरीक्षकों तक रु. लाख से लेकर रु. 25-30 लाख तक, आबकारी सहा. आयुक्त, रु. 50 लाख से 2 करोड़ तक लेन देन हुआ, क्योंकि यहां मात्र आबकारी में मात्र 10 से 20 प्रश तक की ही आय होती जबकि मासिक वसूली का आंकड़ा ही अरबों रु. में इंदौर जैसे शहर में होता है, तो वहां तक इंदौर का सहा. आयुक्त बनने के लिए रु. 10 करोड़ भी कम है। दुनिया जानती है, कि अवैध शराब, गांजा, भांग आदि का व्यवसाय अकेले इंदौर में ही अरबों रु. में जाता है।पंचायत एवं ग्रामीण विकास सा. न्याय, निःशक्त जन, सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव के इस मंत्रालय में भ्रष्टाचार और लूटपाट का आलम क्या है, जहां सरपंच, पंच चुनाव लड़ने के छः माह के अंदर ही सायकल से उतकर बोलेरो में घूमने लगता है, पंचायत सचिव के हाल भ्रष्टाचार के संबंध में अंदाज लगाया जा सकता है, जब पंचायत सचिव के स्थानांतरण में ही रु. 5 से 10 लाख तक लेन-देन हुआ, प्रदेश में 23000 पंचायतें है। 31 जनपद पंचायतें, 51 जिला पंचायतें जिनको ग्रामीण विकास के नाम केन्द्र व राज्य सरकार का लगभग रु. 50 हजार करोड़ से ज्यादा, 90 से ज्यादा योजनाओं में, मिलता है, जिसका कुछ में 50 कुछ में 75 प्रश और कुछ में सारा काम कागजों पर ही संपन्न हो जाता है। फिर सरपंचों के खातों में आवंटन भी तभी पहुंचता है जब यहां से जिला पंचायतों से स्वीकृति जाती है। जो मुफ्त में नहीं होती, वैसे तो पैसे के दम पर ही जिला पंचायतों का स्टॉफ सबसे ज्यादा मक्कार, जालसाज होने के साथ एक ही स्थान पर 25-25 वर्षों तक जमा रहता है, जमे रहने में भी पैसा ही चलता है, चाहे वह मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो, लेखाकार, अन्य अधिकारी या बाबू हो, रु. 500 करोड़ से ज्यादा का यहां भी कारोबार हुआ। परिवहन राजस्व, महिला बाल विकास, कृषि, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, ग्रामीण यांत्रीकीय, उद्यानिकी, सहकारिता, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रदूषण मंडल, नगर निगमों,पालिकाओं, शहरी विकास, ग्राम एवं नगर निवेश, आदिम जाति, अनु. जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, कोषालय, खाद्य एवं औषधि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आदि के साथ निगमों, मंडलों, आदि सब में भी लगभग रु. 3000 करोड़ का लेन-देन किया जाकर स्थानांतरण पदस्थापना का उद्योग चला जो पूर्णतः भ्रष्टाचार से कमाया काना धन ही तिजसमें मंत्रियों, दलालों,मा. प्रशा. सेवा, भा. पु.से., भा.वन सेवाओं के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों आदि सबने स्नान किया। आखिर इस काले भ्रष्टाचार के धन पर आयकर विभाग लोकायुक्त आदि कैसे कार्रवाई करेंगे, लेन-देन तो हुआ ये स्पष्ट है, धन देने वालों धन कहां से दिया, विशुद्ध वेतन में से तो नहीं दिया, भ्रष्टाचार से कमाया, भ्रष्टाचार में ही खर्च किया, सत्यता अत्याधिक कड़वी है, हर विभाग की मुख्यमंत्री, मंत्रालयों, मुख्य कार्यालयों से लेकर 23000 पंचायतों तक फैले हर शासकीय कार्यालयों में इसका खेल हुआ।

यमंत्री के सानिध्य में संचालित अथवा निजी चिटफंड कंपनी

निगम मंडलों से कोई भी काम करने के लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त किया जाता है। तथा प्रचार-प्रसार अथवा प्रिंटिंग सेवा प्रदाता कंपनी, पत्र, पत्रिका, संस्था आदि को 15 प्रतिशत अपना कमीशन तय करने के वाद काम कराती है। तथा उसका भुगतान कब किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस प्रकार चिटफंड कंपनियां सरकार द्वारा पंजीकृत होने तथा बैंकिंग प्रणाली अपनाई जाने के लिए वैध बताकर जनता से करोड़ों रूपए पहले वसूल लेती हैं। बाद में उस पैसे का क्या करती हैं, कहां निवेश करती हैं, क्या उत्पादन करती हैं आम जनता नहीं जानती कि उसका भुगतान लाभ सहित कब होगा, अथवा कभी नहीं होगा उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री के सानिध्य में संचालित मध्यप्रदेश माध्यम का भी काम है। बताते हैं मध्यप्रदेश माध्यम के पास न छपाई की मशीनें है, न इसके पास कोई किसी मीडिया हाऊस जैसा स्टूडियो और न ही कोई अपनी निजी संचार व्यवस्था।

सिवाए एक समाचार पत्र रोजगार निर्माण और समाचार पत्रिका पंचायिका आदि जैसी कुछ और प्रकाशन मात्र हैं वह भी विभागों के सरकारी विज्ञापन की राशि को हड़पने की नियत से प्रकाशित होते हैं। वहीं इसके विपरीत मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, शासकीय मुद्रणालय आदि जैसी संस्थानों को व्यवसाय में कमीशन के लिए प्रतिस्पर्धा में शून्य कर रखा है इसका मुख्य कारण है बड़े-बड़े मीडिया हाऊस और बड़ी-बड़ी प्रसार-प्रचार कंपनियां, विधायक, सांसद आदि को सीधा अघोषित लाभ पहुंचना तथा मुख्यमंत्री के स्वयं के चैयरमैनशिप में संस्थान का संचालन वहीं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.के.मिश्रा एवं भ्रष्ट कार्यपालन संचालक श्री मंगला मिश्रा जैसे लोगों को एक दलाल के रूप में प्रतिस्थापित कर रखा है ताकि इस संस्थान के माध्यम से प्रभावशाली मीडिया घरानों को उनके मुंह में दलाली का निवाला ठूंसकर उन्हें चुप किया जा सके तथा प्रभाव में न आने वाले लोगों को अघोषित रूप से अपराधियों को नियुक्त करके उन्हें पुलिस और अदालत के दलालों के माध्यम से सलाखों के पीछे भेजा जा सके अथवा यमराज को ही सीधा ठेका दिया जा सके। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि यह संस्थान सरकार की कोई लोकहितकारी संस्था नहीं है बल्कि अघोषित रूप से एक चिटफंड कंपनी है जो भ्रष्ट लाभ के लिए और सरकार के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए कृत संकल्पित है। यही कारण है कि किसी मीडिया कर्मी के ऊपर हमला हो या सरकार के विरूद्ध समाचार चलाये उसका विरोध कोई भी मीडिया संस्थान अथवा विधायक या सांसद नही कर पाता। और प्रकरण दफ? करा दिया जाता है। लेखक वरिष्ठ पत्रकार तथा त्वरित टिप्पणीकार है।

मेगी ही नहीं सारे पेकेज्ड पेय भी घातक, स्वास्थ्य से खिलवाड़

प्रथम पृष्ठ का शेष

जबकि ये शीतल पेय जिनमें कार्बनडाइआक्साइड मिली होती है जिसको मनुष्य व अन्य जीवित जानवर छोड़ते हैं। स्वाभाविक है जब वही शरी में उल्टे ही जल में प्रवेशित करवाई जाएगी तो न केवल पेट में इस वायु का आधिक्य रक्त में घुलकर शरीर के अन्य अंगों को भी दूषित करेगा, जिसका परिणाम स्वरूप कम उम्र में ही ह्दयघात, उच्च निम्न रक्तचाप, अपेन्डिस व अन्य घातक रोगों के साथ ही अपचन, अफारा, मोटापा जैसी बीमारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, पर इस यथार्थ और शासन के जनता पर बढ़ते स्वास्थ्य खर्च पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं, क्योंकि इन बहुराष्ट्रीय कं. ने मोटा कमीशन बांटकर सबको अपनी जेब में डाल रखा है। उसके साथ ही इन कं. द्वारा पेकेज्ड पानी फलों के जूस आदि में मिलाए जा रहे कीटनाशक के साथ ही अन्य रसायन जो कि फलों को रसों को सड़ने से बचाते हैं, भी मिलाए जा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाजारों में ऐसे हजारों पेय पैकटों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जिन पर राष्ट्रीय व राज्यों के साथ सुरक्षा अधिकारियों का न केवल नियंत्रण नहीं है वरन् इन सबके वर्षों से नमूने नहीं लिए गए हैं। दूसरी ओर केन्द्रीय औषधि नियंत्रक प्राधिकारी के पास ही पर्याप्त जनसंख्या मान से 25 लाख पर एक निरीक्षक व अधिकारी मानें तों 125 करोड़ के लिए 100 निरीक्षक, अधिकारी व अन्य कर्मचारी होने चाहिए जो 100 भी पूरे नहीं है। क्या खाक नियंत्रण करेंगे, वही हाल फिर मप्र में भी है, 7.25 करोड़ की आबादी पर मात्र 30 के लगभग औषधि निरीक्षक है। जिसमें 5 भोपाल और 3 इंदौर में वर्षो से जमे हैं। बाकी के पास 49 जिलों में एक-एक निरीक्षक के पास दो-तीन जिले हैं। जिसमें 10-12 नए हैं। जिन्हें कार्रवाई की तो दूर कानून तक भी पूरा याद नहीं है। जिसमें 5 वर्षो से ज्यादा समय से इंदौर में बैठे औ.नि. अजय ठाकुर और अशोक गोयल है। जिनका एकसूत्रीय कार्यक्रम है केवल मासिक वसूली, वही हाल खाद्य निरीक्षकों का है।

ये सब औषधि निरीक्षक ही जिम्मेदार है, पालदा, मूसाखेड़ी, आजाद नगर, भागीरथपुरा, शांतिनगर जैसी 99 प्रश बस्तियों में दवा विक्रेताओं द्वारा नशीली दवाएं बैचने, शराब के स्थान पर तेज अल्कोहल के कफ सिरप बैचने, नाइट्रावेट बैचने गरीबों को बिना पर्ची के दवाएं बैचने गंभीर रोगों को बढ़ाने आदि के लिए, जिसकी शिकायत ई-मेल से स्वा. मंत्री, क्षत्रिय जिलाधीशों को कीं गई थी, परंतु उस पर कार्रवाई के नाम पर, एडीएम, एसडीएम औषधि निरीक्षकों के साथ जाकर इंदौर चार दुकानों पर कार्रवाई कर वसूली कर चुप हो जाते हैं।

इंदौर जिले में 2500 से ज्यादा दुकानें फूटकर की और 800 से ज्यादा थोक विक्रेता है, 200 से ज्यादा औषधि निर्माता है। इन हरामखोरों को सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर, कोई जवाब देना नहीं चाहता और तो और मुख्यालय के पत्रों को को भी डकार जाते हैं। किसी को चिंता नहीं है कि यहां के औषधि और खाद्य निरीक्षक क्या काला-पीला कर अपनी कमाई कर जनता की कैसी बर्बादी कर रहे है। एक ही स्थान पर खाद्य निरीक्षक और औषधि निरीक्षक वर्षो से कुंडली मारे 5-5 वर्ष से ज्यादा गुजार चुके हैं। हर वर्ष 5 से 10 लाख खाद्य व औषधि नियंत्रक भोपाल को रायल्टी का भुगतान करों, और दोनों हाथों से वसूली का तांडव करते हुए जमे रहो, 4 से 10 वर्ष तक, कोई बोलने की तो दूर, देखने को भी खाली नहीं।

क्षेत्रीय स्तर एडीएम, एसडीएमे, सीएमओ से लेन-देन से जमावट हो ही जाती है, सब टुकड़खोरों को टुकड़े मिलते रहे, काहे की जांच, काहे के नमूने, काहे की प्रयोगशाला की जांच प्रतिवेदन, आखिर 33 वर्षो से मेगी ने कैसे अपने मेगा शो किए, और कैसे चॉकलेट, शीतल पेय, पेकेज्ड फलों के रस, मानव स्वास्थ्य के लिए घातक और विषैले होने के बाद भी भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के दम पर ग्रामीणों की झोपड़ियों तक में पैर पसारे बैठे हैं। देश में सियारों की फौज में किसी दम-खम वाले सियार ने हुआ-हुआ किया, फिर मीडिया के भेड़ियों ने बुद्धिहीन पटल अर्थात टीवी पर दिखा दिया बस पूरा देश हुआ-हुआ चिल्लाने लगा।

क्या हुआ इंदौर के विजय चाट, नेमा कुल्फी, अपना स्वीट्स, जैन मिष्ठान,भंडार के नमूने लिए थे, क्षेत्र के एडीएम से मोटा लेन-देन हो गया तो दस्तावेजों में मात्र हरामखोरों ने रु. 5-10 हजार के दंड किए, और छोटे गरीब दूधवालों पर 40-50 हजार के दंड कर दिए, खा.सु. एवं मानव अधि. 06 यथार्थ में न केवल खा.सु. अधि. वरन् एडीएम, एसडीएम क लिए भी दोनों हाथ से लूटने और वसूली का हथियार बन गया, जो कि पूर्णतः बड़े खाद्य व्यवसाय और पेकिंग करने वालों का पोषण और गरीब छोटे विक्रेताओं के शोषण और खत्म करने का हथियार बन गया है, जैसा कि समय माया सन् 2007 से प्रकाशित करता आ रहा है।

अब राज्यपाल रामनरेश यादव को कैसे बचाएगी मोदी सरकार..?

भोपाल। अब जबकि मध्यप्रदेश के महामहिम की कुर्सी कभी भी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने यह याद दिलाना प्रारम्भ कर दिया है कि रामनरेश यादव कॉंग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल हैं। यह भी कि वे इन्दिरा गांधी के वफादार थे और इसी के चलते सोनिया गांधी ने उन्हे राज्यपाल बनवाया था. सवाल है कि यह किसे मालूम नहीं था..? सब जानते हैं कि नियुक्ति कि घोषणा होते ही गदगद रामनरेश यादव ने सार्वजनिक रूप से इसके लिया सोनिया जी का तो आभार व्यक्त किया पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं लिया। ऐसा कर उन्होने अपने को तो हास्यास्पद बनाया ही साथ ही इस संवैधानिक पद पर इन दिनों रामनरेश जी पर राय देने से बचते हुए मुख्यमंत्री इस शब्द का ही इस्तेमाल कर रहे हैं .की भी बैंड बजा डाली थी। यह ठीक वैसा ही है जैसे पूर्व स्पीकर श्रीनिवास तिवारी के समय हुए विधानसभा भर्ती घोटाले की शिवराजसिंह चौहान को तब याद आई जब दिग्विजयसिंह ने व्यापम घोटाले पर शिवराजसिंह चौहान और उनकी पत्नी पर सीधे हमला बोल दिया। इसके बाद इस मामले मे आनन-फानन मे एफआईआर दर्ज करा कर उन्होने अपनी खूब जग हँसाई कराई। वे करीब दस साल से मुख्यमंत्री हैं और श्रीनिवास तिवारी के कार्यकाल मे भाजपा के ईश्वर दास रोहाणी लगातार डिप्टी स्पीकर रहे और बाद मे लंबे समय तक स्पीकर भी रहे। वे इस घोटाले से वाकिफ रहे होंगे पर मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की।इसी प्रकार प्रधानमंत्री बनते ही नरेन्द्र मोदी ने कॉंग्रेस के समय नियुक्त राज्यपालों से इस्तीफा मांगने, न देने पर तबादला कर देने और बर्खास्त कर देने का सिलसिला शुरू कर दिया। लाख टके का सवाल है की रामनरेश यादव मे ऐसा क्या है जो वे ढेर सारी बदनामियों के बावजूद राजभवन मे टिके हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी केंद्र सरकार मूक दर्शक बन कर रामनरेशजी के हाइकोर्ट से स्टे लेने मे सहभागी बनी। वे जबसे राज्यपाल बने हैं उनका एक पैर राजभवन मे और दूसरा अस्पताल मे रहता है। यह भी दोहरा दें कि उनके साथ यूपी से आए ओएसडी धनराज यादव व्यापम घोटाले मे जेल की हवा खा रहे हैं। इस बीच व्यापम की जांच से भाग रहे उनके पुत्र की मौत से सब वाकिफ हैं ही।इस सब के बावजूद उनका पद पर बना रहना भाजपा, शिवराजसिंह चौहान और प्रधानमंत्री को कठघरे मे खड़ा कर रहा है।

मध्यप्रदेश में हो रहे पाप में जनसंपर्क मंत्री राजेन्द्र शुक्ल की भूमिका भी संदेहास्पद व रहस्यमयी !

भोपाल (पं.एस.के.भारद्वाज)। मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क एवं खनिज संसाधन मंत्री राजेन्द्र शुक्ला की कार्यशैली से प्रदेशवासी स्तब्ध है। इसके कार्यकाल में खनिज माफियाओं द्वारा कई अधिकारियों पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी है कई पर हमले हो चुके पर मंत्री महोदय चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। मंत्री जी इतने संवेदनहीन हो चुके है कि मृतकों के संवेदना हेतु उनके पास एक फूटा शब्द भी नहीं है। प्रदेश में कई पत्रकारों की हत्यायें हो चुकी है और हजारों पत्रकारों पर फर्जी मुकद्दमे दर्ज हो चुके है परन्तु मंत्री जी चैन की बंसी बजाते हुए सत्ता स्वाद में मदमस्त हैं। यही नहीं अपने इर्द-गिर्द भ्रष्ट अधिकारियों का हुजूम लगाये है। प्रदेश का भ्रष्टतम् अधिकारी जिसके खिलाफ म.प्र.हाई कोर्ट एफ. आई.आर.दर्ज करने का आदेश दे चुकी है एस. के. मिश्रा को जनसंपर्क विभाग का प्रमुख सचिव तथा मंगला प्रसाद मिश्रा जैसे भ्रष्ट अधिकारी को संचालक बनाकर इसे प्रमाणित कर दिया है। इनके खिलाफ पत्रकारों के कल्याण और सुविधाओं के नाम पर करोड़ों डकारने का आरोप है। मंगला मिश्रा को पत्रकारों के कल्याण संबंधी जिम्मेदारी देकर पत्रकारों का मुंह बंद करने की रणनीति पर चल रहे है। शिवराज के प्रिय पात्रों में शुमार श्री राजेन्द्र शुक्ल सुनियोजित तरीके से खनन माफियाओं को संरक्षण प्रदान किए हुए है। खनन माफिया और खनिज मंत्री के साजिश का शिकार पत्रकार और खनिज विभाग के कर्मचारी अधिकारी हो रहे है,और जान से हाथ धो रहे है। मंत्री जी अपने विभाग द्वारा प्रदेश में खनन माफियाओं द्वारा पत्रकारों अधिकारियो की हुई हत्याओं की जांच कराने का साहस क्यों नही जुटा पाए?क्या पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मात्र मीडिया कर्मियों की उपयोगिता प्रदेश में राजनीतिक बाजार सजाने के लिए ही है,जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव एस. के.मिश्रा और राजेन्द्र शुक्ला के मधुर संबंध जगजाहिर है। पूर्व में मिश्रा को अपने गृह जिला रीवा का कलेक्टर मंत्री की कृपा पर ही बनाया गया था,जहां हनुमना तहसील में लगभग ढाई सौ एकड़ सरकारी जमीन की हेराफरी इन्होंने की थी। इसकी शिकायत पर ही हाईकार्ट ने एस.के. मिश्रा को दोषी मानते हुए ही एफ.आई.आर.दर्ज करने का आदेश दिया था। वह कार्यवाही आज तक क्या हुई? पूरा प्रदेश जानता है। इसके विपरीत मंत्री जी के पास जैसे ही खनिज संसाधन विभाग आया,मंत्रीजी ने इन्हें खनिज विभाग का सचिव बना लिया। जैसे ही राजेन्द्र शुक्ल के पास जनसंपर्क विभाग मिला,वैसे ही एस के मिश्रा को इन्होंने जनसंपर्क विभाग का आयुक्त एवं प्रमुख सचिव बना दिया। काफी शिकवा शिकायतों के बावजूद इन्हें जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पद से तो दूर कर दिया परन्तु विभाग का प्रमुख सचिव एवं मध्यप्रदेश माध्यम का प्रबंध संचालक का पद यथावत रखा,ताकि परोक्ष रूप से कमान इन्हीं के हाथ में रहे। एस.के .मिश्रा मुख्यमंत्री के भी प्रमुख सचिव है,लिहाजा खनिज मंत्री और मुख्यमंत्री के मध्य समन्वय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है। एस. के .मिश्रा और राजेन्द्र शुक्ल मिलकर पत्रकारों को बुरी तरह मानसिक रूप से प्रभावित किये हुए है। यही कारण है कि कोई भी खनन संबंधी समाचार जिसका संबंध सरकार ,मंत्री,किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होता है प्रकाशित ही नहीं होता और पत्रकारों के ऊपर हो रहे सुनियोजित हमलों पर एक फूटा,शब्द भी इनके मुँह से संवेदना के लिए नहीं निकलता। दूसरी ओर यदि कोई भाजपा समर्थित बॉलीबुड की नेत्री किसी आयोजन के लिए आ जाय अथवा वो किसी फिल्म को टैक्स फ्री कराने की सिफारिश लेकर आ जाये तो उसके पीछे दिल दर्शन की भावना से पूरी सरकार पलकपावड़े बिछाकर तन्मयता से लग जाती है कि कहीं उसकी चिकनी काया पर कोई दुश्प्रभाव न हो जाये। इसके प्रमाण के लिए इनके अधीन सरकारी समाचार एजेन्सी,जनसंपर्क विभाग अथवा स्वयं प्रभारी अधिकारी जनसंपर्क श्री सुरेश गुप्ता जी से मालूम किया जा सकता है। समाचार समय और कार्यकाल अवलोकन के उपरान्त देश की जनता जान सकती है कि प्रदेश में हो रहे पाप में इनकी भी भूमिका संदेहास्पद व रहस्यमयी है।

साप्ताहिक समय माया

जानकारी न देने, साइट पर न डालने हेतु उच्च स्तर पर रचे गए षड़यंत्र

सूचना आयोग बदले लो.सू.अ. और अपीलीय अधिकारी

ग्रा.यां. सेवा, कृषि, पंचायत व अन्य विभागों में जिले के कार्यालयों में जो लोक सूचना अधिकारी था उसे ही अपीलीय अधिकारी बना दिया। कौन दे जानकारी न मिलने पर अपील भी वहीं अधिकारी सुनकर एक तरफा रद्द कर देता है, वाणिज्य कर विभाग में सबसे भ्रष्ट और लूटेरी गैंग होती है। एंटी इवेजन ब्यूरो की, शासन के 2009 के आदेश में जानकारी देने से मुक्त कर दिया है, पुलिस न्यायालय सूचना के अधिकार में जानकारी मांगना और देना अपना अपमान समझते है, क्या आयोग इस मानसिकता पर लगाम लगा पाएगा।

भारत के संविधान में भारत के आम नागरिकों को शासन चाहे वह केन्द्रीय विभाग हो, मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कार्यालय हो, राज्य सरकारों के राज्यपालों के कार्यालयों से लेकर सभी मंत्रालयों सभी विभागों से लेकर, सभी क्षेत्रीय मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसे आजादी के 58 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में यथार्थ में बहुराष्ट्रीय कं. ने अपने हित साधने में लागू करवाया था, जो केवल भारतीय नागरिकों, जिनके जन-धन और परिश्रम से ये सरकारें बनती और चलती है, के लिए ही है, जो कि अक्टूबर 05 से देश की जनता को समर्पित किया गया था।

सू.अ. अधि. 05 के लागू होने के बाद से ही इसका नियम और नियमन करने के नाम पर धूर्त, देश की महाभ्रष्ट लूटेरी इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों की लॉबी ने इसका बलात्कार करना शुरू कर अपने कुकर्मों को बचाने और सुरक्षित रखने का कार्य शुरू कर दिया था, यहां तक कि कानून लागू करने से पूर्व ही मप्र सरकार ने अवलोकन के रु. 5/- प्रति घंटे का रु. 50/- प्रति घंटे में बदल दिया, जबकि केन्द्रीय व्यक्तिगत, पीढ़ा निवारण मंत्रालय की साइट पर आज भी रु. 5/- प्रति घंटे है।

वैसे कांग्रेस के समय भाजपा ने, भाजपा के समय में कांग्रेस,दोनों ने ही इस कानून को समाप्त करने से रोका, क्योंकि सत्ताधीशों को अपने कुकर्मों का भांडा फूटकर जनता के सामने जाते दिखा, जिससे भारी हंगामें का सामना करना पड़ा। जब जालसाज सत्ताधीश, सत्ता में बैठे धूर्त गिद्ध इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के बनाम आईएएस, इंडियन (क्राइम) प्रोटेक्शन सर्विस बनाम आईपीएस, इंडियन फारेस्ट (ईटिंग) सर्विस बनाम आईएफएस इंडियन रेवेन्यू (चीटिंग) सर्विस बनाम आईआरएस, सभी राज्यों की स्टेट एव्यूसिंग सर्विस बनाम एसएएस इन सबमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट और जालसाज होते हैं, आईएएस, आईपीएस और एसएएस जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों जो कि सभी 5 वर्षीय कार्यकाल लेकर आते हैं। ये सब उन्हें सत्ता के गलियारे में गधों की तरह न केवल हांकते हैं और चराते है उनकी आड़ में भ्रष्टाचार की मलाई चाटकर सप्रेटा दूध इन्हें परोसते हैं।

स्वाभाविक है सूचना के अधिकार में जानकारी मांगकर इनके कुकर्मों का यथार्थ सामने आने लगा तो इन्होंने हर कदम पर साजिश कर इस कानून का भोथरा बनाने की कोशिश की, कई स्थानों पर सफल भी रहे, खुलकर सूचना अधिकार कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लोक सूचना अधिकारी को ही अपीलीय अधिकारी बना दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाला जिला पंचायत मु.का.अ. को ही उसका अपीतीय अधिकारी बना दिया गया जहां 84 से ज्यादा योजनाओं में ग्रामीण और शहरीय विकास का पैसा राज्य व केंद्र से मिलता है, जिसमें मनरेगा, मध्यान्ह भोजन, ग्रामीण विकास के नाम पर 40 से ज्यादा योजनाओं का पैसा जो अरबों रुपए में होता है। सरपंचों को आवंटन से पूर्व 30 से 50 प्रश तक हजम कर लिया जाता है, यहां पर बैठा धूर्त और मक्कार 20-25 वर्षों से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर जमा रहने के कारण स्टॉफ की काली करतूतें पकड़ में न आ जाए, सूचना के अधिकार में जानकारी न देने के लिए हर कदम न केवल षड़यंत्र पूर्वक कई गुना पैसा वसूलने के लिए पत्र लिखता है, जो सामान्यतः 35-40 दिन के बाद ही दिया जाता है।

फिर यहां अपील करने पर मु.का.अ. की अपील भी वही सुनेगा, जो एक तरफा खारिज कर देता है। यह षड़यंत्र मुख्य सचिव परशुराम ने अपने कार्यकाल में किया क्योंकि उसके पूर्व वह हरामखोर ग्रामीण विकास का ही प्र.स. रह चुका था, उसकी जालसाजियां जब सामने आने लगी तो उसने एक परिपत्र जारी कर मु.का.अ. को अपनी जालसाजियां और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए स्वयं के विभाग का अपीलीय अधिकारी बना दिया, जबकि उसका वरिष्ठ अधिकारी जिलाधीश ही पूर्व में उसका अपीलीय अधिकारी था। वही हाल उसने का.यं.म.प्र. ग्रामीण यांत्रिकीय में भी किया कि का.यं. को ही उसका अपीलीय अधिकारी बना दिया और बाबू को लो.सू. अधि. बना दिया जो न केवल गैरकानूनी था।

यही हाल उपसंचालक सहकृषि जिला अधिकारी को जहां उसके मुख्यालय पर वरिष्ठ अधिकारी नहीं है उसको ही, उसका अपीलीय अधिकारी बना दिया गया, यह भी गैर कानूनी और भ्रष्टों को बचाने की साजिश थी।

इसी प्रकार वाणिज्य कर में भी सबसे ज्यादा भ्रष्ट और वसूलीबाज जालसाज है। यहां एंटी इवेजन ब्यूरों जहां रु. 10 से 50 लाख, खबरें रु. 80 लाख तक की भी है, उपायुक्त की नियुक्ति के लिए खर्च कर जाते हैं। गाड़ियों को पकड़ना 5 गुना दंड लगाने की आड़ में 2 गुना दंड लगाकर और यदि बाहर के बाहर सेटिंग हो गई है तो वा.क.अ. सहा. आयुक्त, उपायुक्त, सहा.वा.कर अधिकारी, कराधान सहा. जिसके हाथ लगा ले-देकर छोड़ देते हैं।

इसलिए सूचना के अधिकार में जानकारी देने में डर लगता है इन हरामखोर जालसाजों ने भी 2009 के एक परिपत्र में से जानकारी न देने की छूट प्राप्त कर ली है। जबकि सूचना के अधिकार के कानून का उद्देश्य ही था कि हर शासकीय कार्यालय में पारदर्शिता लाना भ्रष्टाचार रोकना, बाकि भ्रष्टों को बचाना और कानून को अपने बाप की जागीर समझ भ्रष्टाचार करना, ऐसा मप्र शासन के अनेकों विभाग में ही रहा है, कुछ जिलाधीश कार्यालय विभाग तो न तो आवेदन का जवाब देते हैं और न ही अपील कर इसमें वन, यातायात, विभाग, पुलिस, न्यायालय, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग, मप्र जल संसाधन आदिम जाति नगर व ग्राम निवेश, शिक्षा, वाणिज्यकर, नगर निगमों, पालिकाओं आदि अनेकों विभाग है।

सूचना के अधिकार को वैसे भी कोई भी विभाग गंभीरता से नहीं लेता, हर भ्रष्ट मुख्यमंत्री मुख्य सचिव से लेकर नीचे तक ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों तक, विश्व विद्यालयों से लेकर प्राथमिक विद्यालयों तक।

राज्य सूचना और केन्द्रीय सूचना आयोग में राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री, राज्यपाल व विपक्ष का नेता व केन्द्रीय सूचना आयोग में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और लोकसभा में विपक्ष का नेता ऐसे छटे हुए भ्रष्ट आयुक्तों को नियुक्त करते है। जो सत्ता की मंशाके विपरीत अपना मुंह न खोले, आवेदकों को ऐसी जानकारी न दिलवा दे, जो सत्ताधीशों के भ्रष्टाचार का यथार्थ देश और दुनिया की जनता के सामने रख उनकी धज्जियां बिखेर दे, वो सत्ता के टुकड़े खाए और टुकड़खोर सत्ता के इशारे पर नाचे।

भा.प्र.से. की हर वर्ष पदोन्नतियां, राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को 20-30 वर्ष तक

राज्य के कर्म. अधि. की वर्ष में 2 बार क्यों वि.प.स. नहीं

भ्रष्ट मंत्री-संत्री करते है राज्य के अधि. कर्म. का घोर शोषण

राष्ट्र की आजादी के तुरंत बाद भारतीय नागरिक सेवाएं अर्थात इंडियन एव्यूसिंग सिविल सर्विसेज, जो कि अंग्रेजों द्वारा भारत में राज्य करने के लिए अपने एजेंटों की नियुक्ति करती थी और उन एजेंटों को राजस्व संग्रहण के लिए राजस्व जिलों और जिलों को मिलाकर संभाग के संभागायुक्त कमिश्नर की नियुक्ति की जाती थी, पर आजादी के बाद इन भारतीय अंग्रेजों के एजेंटों ने देखा कि यहां के आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेता, अनपढ़ और गैर प्रशासनिक क्षमतावान है।

इन हरामखोरों ने मौके का फायदा उठाकर अपने आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बना लिया जिसके हाथ में सत्ता चलाने के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर जिलों और तहसीलों तक के न्यायिक और प्रशासनिक सूत्र अपने कब्जें में ले लिए, जनता के धन से वेतन प्राप्त करने वाले इन हरामखोरों ने जनता को कीड़े-मकोड़े, और उनके मातहत अधिकारियों को अपने आंगन में पले दुधारु पशु और छोटे कर्मचारियों को भेड़ बकरी मान अपना शासन पिछले 65 वर्षों से हांक कर रहे हैं। यथार्थ में पर्दे के पीछे बैठे ये धूर्त और मक्कारों का गिरोह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय से चलकर केन्द्र के हर मंत्रालय हर, केन्द्र शासकीय नियंत्रण वाले निगमों, मंडलों, बीमा, बैंकिंग, आदि सब में अपने के फायदे को ध्यान में रखकर ही हर नीति निर्धारण और भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है।

वही नीतियां, योजनाओं, नियम कानून आदि लागू करने पालन करने और करवाने में भी इन्हीं धूर्तों की लॉबी होती है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर राज्यों के हर मंत्रालय के प्रधान सचिव, सचिव आयुक, संचालक से लेकर जिलों के जिलाधीश और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में शीर्ष से लेकर अपनी तहसीलों जनपदों के गांवों तक हर सूत्र अपने नियंत्रण में रखकर अपनी श्रेष्ठता और सर्वोच्चता को सिद्ध करते हुए दोनों हाथों से हर कदम भ्रष्टाचार करते हुए जनता से लेकर अपने ही अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों तक का भयानक शोषण करती है, इसीलिए यथार्थ में इंडियन एडमिनिस्ट्रिव सर्विसेज के स्थान पर इन्हें इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी कहना ज्यादा बेहतर होगा, इसीलिए पिछले 15 वर्षों से समयमाया इन्हें इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी के नाम से प्रकाशित राष्ट्र के इन असली धूर्त, डकैत सत्ताधीशों की हकीकत प्रकाशित करता रहा है, सत्य तो यह भी है कि इन डकैतों की ही सबसे ज्यादा काला धन केवल स्विस वरन विश्व के अन्य देशों की बैंकों में भी जमा है, यही कारण है कि जब-जब काला धन देश में लाने की बात उठाती है तब-तब इन जालसाजों की फौज ही उस मामले को अटका देती है और गालियां खाते हैं, प्र.मं. मोदी, वित्त मंत्री जेटली और अमित शाह साथ ही इसका दूसरा स्याह पहलू यह भी है कि जब-जब काला धन लौटाने की बात मीडिया और संसद में उठती है, रुपए की तुलना में भारत में अमेरिकी डॉलर महंगा हो जाता है।

उसका सीधा सा गणित है कि ये हरामखोर अपने अरबों डॉलर में जमा काले धन के डॉलर में ज्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए वित्त मंत्रालय से मिलकर यह खेल खेला जाता है। भले ही इससे जनता को राष्ट्र को कितना भी आयातोप नुकसान उठाना पड़े, पर इन हरामखोरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कानून बदलने से लेकर देश को गिरवी करने तक जैसा कर्ज लादकर, राष्ट्र की संपत्तियों को उन्हें गिरवी कर दिया, यहां तक कि देश की सड़कों से लेकर बिजली मंडल, जलापूर्ति, नगर निगमों से लेकर बड़ी कंपनी तक जो सरकार की थी, बदले में इन हरामखोर देश की दीमकों ने मोटा कमीशन हर कदम डकारा।

ये देश के खुदा जैसी पट्टी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्र के मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों व अन्य मंत्रियों को पढ़ाते चलाते, सिखाते और हस्ताक्षर करवाते है। उनके लिए ये सब शतरंज की बिसात के मोहरों से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब सत्ता में मात्र 5 वर्ष के लिए सत्ता के मंच पर आते हैं, और ये सब असल सत्ताधीश 30 से 40 वर्षों तक सत्ता में जमे रहकर सारी सुख, सुविधाएं, धन, ऐश्वर्य चाहे वो कानून में हो न हो, भोगते व सत्ता व सरकार के सभी विभागों में बैठे अधिकारियों इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कर्मचारियों को जानवरों की तरह हांकते-जोतते और शोषण करते है। उनको पदोन्नतियों व अन्य सुविधाओं से 30-30 साल तक वंचित रखते हैं।

ये इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अपनी डीपीसी अर्थात विभागीय पदोन्नति समीति की वर्ष में दो बार बैठक बुलाकर अपनी पदोन्नतियां नियमित रूप से लेते रहते हैं। जबकि ये नियम हर शासकीय विभाग में लागू होता है, परंतु राज्य सेवा के अधिकारियों, इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, कर्मचारियों आदि की डीपीसी की बैठकें वर्षों नहीं होती हर बार कोई नया बहाना लेकर इनके टाला जाता रहता है। इस प्रकार राज्यों के हर विभागों में अधिकारी इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, कर्मचारियों की 20 से 30 वर्ष तक की पदोन्नतियां नहीं दी जाती है।

अब हर विभाग में हालात यह है कि एक तो पदोन्नतियों भरे जाने वाले पदों पर जिनमें कार्य विभाग लो. निर्माण, लो. स्वा. यांत्रिकीय, जल संसाधन, ग्रा.यां. वि. आदि में न केवल सहा. यंत्रियों से लेकर मुख्य अभियंता तक अनेकों पद खाली पड़े हैं। वही लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का हर विभाग में एक तो 90 के बाद से भर्ती नहीं की गई, 25 वर्षों में कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए, मरे और दूसरी तरफ हर विभाग में कार्य 5 से 10 गुना तक बढ़ गया, हालात ये हैं कि 2016-17 के बाद 90 प्रतिशत शासकीय विभागों में 70 प्रतिशत कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त पा जाएंगे जिससे सरकारी कार्य पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगा और जो भर्ती किए जाएंगे उनको न तो कार्यप्रणाली की जानकारी होगी और न अनुभव, अनुभवियों को पदोन्नत 30-30 वर्ष तक पदोन्नत न किए जाने से सारे वरिष्ठ पदों पर आवश्यकतानुसार अधिकारी कर्मचारी नहीं होंगे, तो विभाग कैसे चलेंगे और शासन कैसे चलेगा, यह चिंतनीय प्रश्न भा.प्र. से को बिलकुल चिंतित नहीं करता, यहां तक चुने हुए सत्ताधीशों का सवाल है, तो ये तो आज है, कल नहीं है।

दूसरी ओर पदोन्नति न करके, उन्हें प्रभारी बनाकर उनसे बदले में हर माह उनसे मोटा धन वसूलता, भ्रष्टाचार करने और धन कमाकर देने के लिए बाध्य करना, मनचाहे तरीके से काम करवाना अन्यथा हटाने की धमकी देना, ये इस खेल में, प्रधान सचिव, आयुक्त, प्रमुख अभियंता, विभागीय मंत्री तक सभी शामिल होते हैं, इसलिए भी डीपीसी नहीं कराई जाती।

यह खेल अभी लो.नि.वि. लोक स्वा. यांत्रिकीय, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण जल संसाधन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, वन, उद्यानिकी आदि अनेकों विभागों में कमाई क्के लिए खुब खूलकर चल रहा है। इसमें कोई नियम कानून, दक्षता नहीं, वरन भ्रष्ट, चालाक और धूर्त होना चाहिए, जो स्वयं लूट और समय पर मंत्री तक पैसा पहुंचाए।

पेयजल के नाम पर पी जाते हैं, अरबों रु. म.प्र.लो.स्वा.यां. विभाग में

भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण-निरीहों को लंबा स्थानांतरण

जालसाज भ्रष्टाचार छुपाने, साफ लिख देते हैं, हमारा काम नहीं है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, स्थानांतरण में पैसा, बदला,संबंधों का खेल हुआ

मप्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में मंत्रालय से लेकर नीचे उपयंत्रियों और सहा. यंत्रियों के कार्यालय तक भ्रष्टाचार हो रहा है। यही कारण है कि भ्रष्ट अधिकारियों को 3 वर्ष से ज्यादा हो जाने पर भी उनके स्थानांतरण नहीं हुए क्योंकि लूट के माल में से उन्होंने पैसा खर्च किया, इसके विपरीत, तृतीय और चातुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 500 किमी दूर प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर तक फेंका गया, यहां तक कि वर्क चार्ज कर्मचारियों और चपरासियों तक पर उस हत्यारे, अपराधी जिसे मंत्री महादेय और प्र.स. अश्विनी राय की महिमा से प्रमुख अभियंता का कार्यभारित बना दिया गया है, इस भ्रष्ट, जालसाज डामोर ने अपने पूर्व मुख्य अभियंता इंदौर के कार्यकाल में वसूली एजेंट आर के चौहान स्टेनो की बताई गई सूची के अनुसार ही किया है और अपनी भ्रष्ट मानसिकता का परिचय दिया है, जबकि इसी इंदौर आंचल में जिसमें इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिले आते हैं। यहां बैठे मुख्य अभियंता सोनगरिया को 3 वर्ष से ज्यादा, उज्जैन के अधीक्षण यंत्री तिवारी, इंदौर नगर निगम लो.स्वा.यां. के अं.यं. राजवाड़े को भी 3 वर्ष से ज्यादा हो चुके पर इन्हें नहीं हटाया गया, जबकि तीनों ही महाभ्रष्ट, जालसाज होने के साथ ही सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर स्पष्ट जवाब देते हैं कि ये काम हमारे स्तर पर कार्यालय में नहीं किया जाता, जबकि हरामखोर मुख्य अभियंता सोनगरिया न केवल कमीशन खोरी के लिए लघु उद्योग निगम से खरीदी के लिए 19 संभागों के कार्यादेश जारी करता है, वरन् पत्रकारों को भी कार्यादेश जारी कर उनके कमीशन और कमाई की व्यवस्था करता है, बेशक यह कार्य अ.यं. का मंडल कार्यालय से होना चाहिए कार्य पुस्तिका या वर्क मेन्युअल के अनुसार, वर्तमान में जिला स्तर के संभागीय,मंडल, आंचलिक से लेकर प्रधान कार्यालयों तक में किराए के वाहन चलाने की व्यवस्था चल रही है, इंदौर, उज्जैन, संभाग के 17 का.यं. कार्यालयों की वाहन स्वीकृति व्यवस्था भी यही संभालत हैं। ताकि इनके यहां व्यक्तिगत स्तर पर उपयोग किए जा रहे, पत्नी बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों के किराए डीजल का बिल एक उज्जैन संभाग में करवाया जा रहा है। विभाग में इ एंड एम की शाखा में अच्छी खासी मशीनें होने के बाद सभी संभागों में कार्य निजी मशीनों से करवाने की स्वीकृति देने, मशीनों और ठेके की फर्मों को जालसाजी पूर्ण तरीके से स्वीकृति देने में भी मोटा धन हड़प कर जाते हैं। स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार के धन की ये भेंट प्र.स. सचिव, प्रमुख अभियंता से लेकर मंत्री तक पहुंचाई जाती हैं, इसीलिए तीन वर्ष बाद भी इस धूर्त का स्थानांतरण नहीं किया गया।

वही हाल अ.य. राजवाड़े का भी है, जो इंदौर नगर निगम की पेयजल व्यवस्था के मंडलेश्वर संभाग-1 व मूसाखेड़ी स्थित संभाग-2 के साथ ही अब परि. क्रि. ईकाई का कार्य भी देख रहे हैं। इनको भी सूचना के अधिकार में प्रशा. स्वी. जारी किए ल.उ.नि. के आपूर्ति आदेशों की प्रतियां मांगी गई थी, जिसके जवाब में इस हरामखोर, जालसाज ने स्पष्ट मना कर दिया कि यह कार्य हमारे यहां से नहीं होता, जब संभाग क्रं.2 के आदेशों की प्रतियां मांगी गई तो उस जालसाज का.यं. संजीव श्रीवास्तव ने अपने क्रय आदेशों और कार्यादिशों की प्रतियां देने की अपेक्षा अ.यं. कार्यालय द्वारा जारी करीब वर्ष भर के 180 आदेशों की प्रतियों को दिया जिसके संबंध में शीघ्र ही आवेदक की ओर भादस 1860 की धारा 120 बी, दो या दो से अधिक लोगों द्वारा जालसाजी पूर्ण कृत्य करना, 217,218,420 के अंतर्गत न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है।

अ.यं. राजवाडे का. यं. सं. 1 व का. यं. 2 से श्रीवास्तव तीनों मिलकर अनावश्यक, स्टॉफ होने के बाद भी केवल कमीशन हजम करने के लिए कार्यादेश जारी कर 25 प्रश से ज्यादा फर्जी बिलों का भुगतान करना, वही हाल मरम्मत सुधार कार्यों में भी विभागीय स्तर के कर्मचारियों से काम करवा रहे ठेकेदारों के दुगुने तिगुने बिलों का भुगतान सं. 1 व 2 में धड़ल्लेसे किया जा रहा है,स्वाभाविक है, नगर निगमायुक्त, जल आपूर्ति प्रभारी, संभागायुक्त आदि भी सभी रु. 10 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े में हिस्सा बटोर रहे हैं। यही कारण है कि सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर न तो जानकारी पूरी दी जाती है, और अपील करने पर हर विभाग की तरह उनके भ्रष्टाचारों और जालसाजियों के साथ अपनी हिस्सेदारी को बचाने के लिए अपने का.यं. 1 व 2 को बचाने और अपील निरस्त करने की भरसक कोशिश की जाती है।

यहां पर सं. दो में जबकि पेयजल के लिए सामग्री कर मुक्त होने के बाद भी अधिकांश बिलों के 5 प्रश वेट की राशि का भुगतान किया गया है, जिससे शासन को लाखों का एक तरफ घाटा हुआ तो दूसरी तरफ आपूर्ति करने वालों के साथ मिलकर टैक्स वह राशि हजम की गई, यही हाल दीपक एडवरटाइजिंग को बिलों के भुगतान में किया, जिसमें व्यावसायिक दरों 4 गुना से ज्यादा भुगतान साथ 12.5 प्रश सर्विस टैक्स व अन्य सेस का 4 बिलों में लाखों का भुगतान किया गया जबकि अर्द्धशासकीय, शासकीय राज्य के विभागों को अपने विज्ञापन सीधे मप्र माध्यम जनसंपर्क माध्यम से भेजने पर डीपीआर की दरों से भुगतान करने पर कुछ हजारों में ही विज्ञापन किया जा सकता था, जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो श्रीवास्तव का.यं. का कहना था, कि नहीं हमने सबकुछ ठीक किया है, वाणिज्यिकर। वेट/ विक्रय कर की इस तरह की लूट और बंदरबांट का यह कांड बीस वर्षों से ज्यादा समय से चल रहा है।

इंदौर मंडल अ.यं. मिश्रा महाधूर्त है, साथ ही इसके यहां बैठे स्टॉफ जिसमें गोयल व अन्य जो 20 वर्षों से ज्यादा समय से इंदौर में कुंडली मारे बैठे हैं। किसी भी सूचना के अधिकार में पत्र देने पर ये हर पत्र को स्पष्ट मना कर देते हैं। अं.य. के अंतर्गत 8 जिलों के का.यं. की लॉग बुक की कॉपी जिस लो.नि.वि. विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी को दूर डायरी के साथ जमा करना आवश्यक होता है, सारे लघु उद्योग निगम से क्रिया देश पूरे संभागों के यहां से जारी होते हैं। सारी प्रशा. स्वी. हर कार्य की यहां से स्वीकृत की जाती है। पर जानकारी मांगने पर ये शूकरों की फौज हर जवाब में साफ मना कर देती है।, कां.यं. धार के आवेदन में स्पष्ट प्रमाण होने के बाद भी ये जालसाज उसे बचाने की कोशिश में लगा है, जबकि का.य. राजीव खुराना न तो किसी अपील की सुनवाई में आया, हर बार बहाने बनाकर बाबू को भेज देता है।

जबकि धार संभाग में यह भ्रष्ट अपने भ्रष्टाचारों से धन हजम करने के लिए शासन के धन की बर्बादी और जब योजनाओं के अंतर्गत कार्यों में भारी निकृष्टता से कार्यों को संपन्न कर रहा है, इसने अपने ही विभाग के सहा. यंत्री आरके शर्मा के भाई राजीव शर्मा को ठेकेदारी में दो टंकियों के ठेके दिए थे जो पूरे न होने पर रद्द किए गए जिसमें जोखिम और लागत पर दूसरों को दिए गए जिसकी रु. 4 लाख की वसूली नहीं की जा रही है, परंतु दूसरे अन्य कार्यों में अपने कमीशन के लिए धड़ल्ले से भुगतान किए जा रहे हैं। जबकि विभागीय मार्गदर्शिका में भ्रष्टाचार रोकने के लिए स्पष्ट लिखा है कि निकट संबंधी उसी संभाग में कोई भी कार्य नहीं कर सकता। चेक डेम बनाने के 90 प्रश कार्यों में न केवल धार वरन इंदौर,खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ के साथ ही देवास, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, आगर आदि के अतिरिक्त भी पूरे मप्र में हुए हैं। क्या प्रधान सचिव अश्विनी राय, मंत्री कुसुम महदेले उनकी जांच करवाएगें और विभागीय कार्रवाई करें तो 55 से ज्यादा कार्यपालन यंत्रियों को निलंबित करना पड़ जाएगा, मुख्य अभियंता अ.यं., प्रमुख अभियंता सभी हिस्सा डकारते हैं। तो सारे हरामखोर कैसे जांच करेंगे ये तो जानकारी मांगने और न देने पर अपील करने पर शूकरों की फौज हर हाल में जानकारी न देने के षड़यंत्र रचती है।

शासन के स्पष्ट आदेशों के बाद भी उपयंत्री, सहा.यंत्री, एक ही संभाग में 5 से 20 वर्षों तक जमे रहकर चारों तरफ भ्रष्टाचार करते रहते हैं। उनका स्थानांतरण पर कोई ध्यान दिया जाता, जबकि अपने बैर भुनाने के लिए बाबुओं, चपरासियों को स्थानांतरित कर 300 किमी तक दूर फेंक कर किस प्रशासनिकता का प्रमाण दिया गया, इन स्थानांतरणों में वर्क चार्ज कर्मचारी भी शामिल हैं।

प्र.अ. सेहरा को, इस अपराधी डामोर ने परेशान करवाकर भागने पर मजबूर कर दिया, दूसरी ओर प्रमुख अभियंता पद पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए न्यायालय में स्थगन के विरूद्ध लाखों रुपए खर्च कर तारीखें बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा बदले की कार्रवाइयां करने में इस धूर्त श्वान ने अ.यं. का पदोन्नति को रोके बैठा है, तो उच्च न्यायालय में इसके प्रकरणों में प्रभारी रहे का.यं. रघुवंशी यांत्रिकीय संभाग इंदौर पर पहले अवैधानिक रूप से कार्यवाई कर, बाद में जब वह स्थगन ले आया, तो उसे छह माह से वेतन नहीं दिया जा रहा, मप्र के यांत्रिकीय विभाग में बैठा मु.अ. खरे भी है, तो भारी भ्रष्ट वह भी अपने भ्रष्टाचारों को बचाने के लिए इस प्र.अ. डामोर को आंख भींचकर सहयोग करता है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर आवेदन ही हजम कर जाता है, बाद में अपील करो तो उसे भी रद्द करता है। यहां किसी को जनहितों से नहीं केवल स्वहितों और कमाई से मतलब रहता है। समय माया के 15-20 वर्षों तक उपयंत्रियों व स्टाफ पदोन्नतियों के लिए लगाए समाचार से कुछ पदोन्नतियां की गई।

विश्व व्यापार संगठन के इशारे पर मोदी सरकार कर रही नई पीढ़ी का भविष्य बर्बाद

निजी शिक्षा माफिया की लूट में सभी शामिल

5वीं, 8वीं को केन्द्र नहीं बनने दे रहा बोर्ड परीक्षा, निजी स्कूलों में पुस्तकों, कॉपियों, प्रवेश, ड्रेसेस आदि के नाम पर मोटे कमीशन का धंधा, जिलाधीश से लेकर मुख्यालय मंत्री तक को हिस्सा, इसलिए सब है चुप

पूरे विश्व में भारत के शिक्षित इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, साफ्टवेयर इंजिनियर्स, तकनीकि शिक्षा भाषा विशेषज्ञ , अर्थशास्त्री से लेकर व्याख्यता, नर्सेस तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सैकड़ों देशों की अर्थव्यवस्था के आधार बने हुए है। इससे विशेष तौर पर यूरोप और अमेरिका भारी भयभीत हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपतियों बिला क्लिंटन, जार्ज बुश, बराक ओबामा, अमेरिकी बच्चों और युवा पीढ़ी से बड़े-बड़े मंचो पर गुहार लगा चुके हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, अन्यथा तुम्हारी नौकरियां छीन लेंगे। भारतीयों को यूरोप व अन्य राष्ट्रों में नौकरियां न मिलें और वे अपनी कमाई भारत न भेजें इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की शिक्षा पद्धति में परीक्षा प्रणाली समाप्त की जाए और कांग्रेस ने उस षड़यंत्र के अंर्तगत पहली से लेकर आठवीं तक पर जिला और संभाग स्तर पर परीक्षाएं लेने का चलन ही समाप्त कर दिया, दूसरी तरफ शिक्षा का निजीकरण न केवल प्राथमिक, माध्यमिक उच्चस्तर माध्यमिक वरन् महाविद्यालयीन के साथ ही निजी विश्वविद्यालय खौलने तक के लिए कानून बनाकर, शिक्षा माफियाओं, पूंजीपति, जालसाज डकैतों के लिए रास्ते खोल दिए गए, जैसा कि अमेरिका में डिग्री बांटने की दुकाने, विश्वविद्यालय नावों में बने कार्यालस से चल रही थी वही हाल भारत में भी हो गया, जिसकी बर्बादी का कहर सामने आया, जहां शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों अध्यापकों और राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम होता वो हजारों रुपए महीने का शिक्षण शुल्क लेकर बिना बच्चों को पढ़ाएं ही अंकसूचियां और प्रमाण पत्र बांट देते हैं। जबकि शिशुओं को जो 3 से 5 वर्ष के होते हैं, पुस्तकें, कॉपीयां हजारों रुपए की खरीदवाकर अपना कमीशन हजम कर, पीठ पर बस्ते का इतना बोझ लाद देते हैं, कि चलते नहीं बनता और चलता है तो गिर पड़ता है। जबकि पढ़ाई के नाम पर 5वीं, 8वीं के बच्चों से अपना नाम लिखना भी नहीं आता। बच्चों के माता-पिता हरियाणा में स्कूलों में जाकर गुहार लगाते हैं कि हमारे बच्चे का कुछ नहीं आता इसे अनुतीर्ण करो ताकि वह कुछ सीख सकें।

इस संबंध में समय माया पिछले कई वर्षों से 5वीं, 8वीं की परीक्षाएं जिला व संभागीय स्तर पर शासन की ओर संचालित किए जाने के संबंध में प्रकाशित कर रहा था, पिछले वर्ष मंत्री पारस जैन से बात करने पर उन्होंने आश्वासन भी दिया था, इस वर्ष सत्र प्रारंभ होने के साथ 5वीं, 8वीं की परीक्षा को जिला व संभागीय स्तर पर आयोजन करने के बारे में पूछा तो उनके निजी सचिव का फोन पर कहना था कि, इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने लौटा दिया है, अर्थात केन्द्र में बैठे हरामखोर जालसाज, इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के सचिवों, प्र. सचिवों को एक तरफ शिक्षा माफिया ने उनकी लूट, डकैती और पालकों से अरबों रुपए की वसूली बंद न हो जाए, मोटा चंदा देश में भी मिला और देश की युवा पीढ़ी शिक्षित होकर विदेशों में न पहुंचे, विदेशों से भी मोटा चंदा डकारा, शासकीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, सीधे सरकार और उसके अधिकारियों को सीधे जनता को भी जवाब देना होता है वरना न केवल विधानसभा वरन लोकसभा में भी सरकार को विपक्ष के हमलों का भी सामना करना पड़ता है।

भाजपा की नेत्री और मोदी की चहेती मंत्री स्मृति इरानी की स्वयं की शिक्षा की डिग्रीया भले ही संदिग्ध हो, विपक्षी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं परंतु तत्काल सारे फर्जी व निजी मंडलों पर रोक लगाएं न केवल केन्द्रीय शिक्षा मंडल वरन् राज्यों में भी 5वीं, 8वीं की परीक्षा में बदलाव लाया जाए ताकि गुणवत्ता सुधारी जा सके और यूरोपीय षड़यंत्रों को विफल किया जा सके।

साप्ताहिक समय माया

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण- लूट सके तो लूट

कागजों पर समकों की बाजीगरी से अरबों का भ्रष्टाचार

उपा. वैश्य को तीन साल से ज्यादा, २ अ.यं. संभाल रहे मु.अ.का पद, कमांड क्षेत्र विकास का सारा पैसा कागजों पर आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर हजम, हर ठेके में समय विस्तार और मूल्य वृद्धि में भी अरबों की बर्बादी, भ्रष्टों को पोषण, निरीहों का शोषण

मप्र की जीवन दायिनी नर्मदा, जिसके विकास के नाम पर बना नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण यथार्थ में 1980 के बाद से 35 वर्षों में मुख्यमंत्रियों, नघा मंत्रियों से लेकर प्रधान सचिवों, सचिवों, प्राधिकरण के सभी सदस्यों यथा इंजिनियरिंग, वित्त प्रर्यावरण पुर्नवास आदि सभी से लेकर सभी 5 शाखाओं के इंजिनियरिंग, वित्त, पर्यावरण पुर्नवास आदि के इंजिनियरों से लेकर बाबुओं के भ्रष्टाचार और लूट की नर्मदा बन गया, उच्च स्तर पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से लेकर अभियांत्रिकीय विभागों के मुख्य अभियंता तक सभी भ्रष्टाचार की कमाई के लिए भ्रष्टाचारी अ.यं., कां.यं., सहा. यं. उपयंत्रियों से लेकर बाबुओं तक को संरक्षण देते हैं। मु.मं. शिवराज वैसे तो कदम-कदम हर मंत्रालय में न केवल भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर हिस्सा डकार रहा है, वहीं नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण में बैठाया गया, प्रं.स. व उपाध्यक्ष रजनीश वैश्य को 4 वर्ष से ज्यादा हो जाने पर भी नहीं बदला गया, जबकि ये धूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी इस प्राधिकरण में धन डकारने और भ्रष्टाचारियों को एक ही स्थान पर 15 वर्ष से ज्यादा समय नर्मदा नगर में का.यं. एसएन मीना को नं.वि. से क्रमांक 30 में मनावर में आरपी उइके को संरक्षण दे रहा है। वहीं मु.अ. यूसी जैन प्रभारी जो इंदिरा सागर मंडल क्रमांक 1 को प्रभार में अ.य. है निचली नर्मदा परियोजना के मुख्य अभियंता जो धार मंडल का क्रं. 10 का अधीक्षण यंत्री है। आखिर ये महाभ्रष्ट, महानिकम्में को दो-दो पदों पर इसीलिए जमाए हुए है, ताकि बंदरबांट में ज्यादा धन न बंटे और इन दोनों को जो 4 पदों पर जमे रहकर आसानी से आवंटन, समय विस्तार, ठेके के कार्यों में महंगाई के नाम पर ओंकारेश्वर की दाई बाई नहरों, इंदिरा सागर नहर के कार्यों में आसानी से अरबों रुपए का धन डकारने में ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े, यही हाल ऊपरी नर्मदा परियोजनाएं जिसमें रा.अ.बाई सागर की दाई-बाई नहरों के निर्माण और कांक्रीटिंग लाइनिंग का है।

न.घा.वि.प्रा. में 2000 किमी लंबी नहरों में कहीं भी कांक्रीट की मोटाई 6-7 सेमी से ज्यादा नहीं है, जबकि 10 सेमी का हजारों करोड़ रु. भुगतान ठेकेदारों को कर दिया गया, निर्धारित समय से 3 से 5 गुना कार्य लंबित करवाने में नीचे बाबु, उपयंत्रियों, सहा.यं., का.यं., अं.यं., मु.अ. से लेकर अभियांत्रिकीय सदस्य, वित्त सदस्य, उपाध्यक्ष, सचिव, प्र.स., मु. सचिवों से लेकर मु.मं. तक ने धन हड़पने के लिए आंख भींचकर अपनी भूमिका निभाई। डेढ़ गुने से दुगुने, तिगुने भुगतान करने में बहानों की लंबी सूची लगवाकर किए जाते रहे।

टर्न की प्रोजेक्ट में न समय वृद्धि की व्यवस्था होती है,न महंगाई भुगतान की इसके विपरीत ओंकारेश्वर की दाई-बाई नहरों में अधिकांश कार्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का टर्न की आधार पर 24, 30 माह में पूर्ण करने के लिए दिया, परंतु 72, 90 माह में तो दूर 120 माह में भी नहीं हुआ, दूसरी ओर यही हाल उदवहन सिंचाई योजनाओं का भी हुआ, एक तरफ बिजली की खपत उसका खर्च, भारी भरकम लागत के बाद किसानों को जो सपने और डीपीआर बनाकर दिखाए गए थे कभी न पूरे हुए और न होंगे। क्योंकि नहर की पूंछ तक पानी पहुंचाने का प्राक्कलन नक्शों पर बनाया अवश्य जाता है, परंतु केवल पैसा खाने के लए न कि पानी पहुंचाने के लिए, और अगर पानी पहुंचा भी दिया जाता है, दिखाने के लिए तो यह केवल कुछ समय के लिए, केवल बाजीगरी छिपाने के लिए।

इसका इस तथ्य से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंदिरा सागर बांध की नींव यां फाउंडेशन 20 मीटर अर्थात 60 फुट डाली जानी थी, जो मात्र 10 मी. डाली गई अर्थात 10 मी. नींव का रु. 500 करोड़ से ज्यादा हजम, अब उसके द्वारों के पास बाल्टी नुमा या बकेट में दरारें पड़ गई है। इसके लिए तत्काल में रु. 175 करोड़ स्वीकृत कर दिए गए है, ताकि पोल न खुल जाए, यही हाल ओंकारेश्वर बांध में भी किया गया जहां 12 मीटर नींव खोदकर डाली जानी थी, मात्र 5 मी. नींव डाली गई, अर्थात सर्वे से ही हरकदम जालसाजियां शुरू हो जाती है। फिर हर डीपीआर, सड़कों, पुलों, भवनों, बांधों, नहरों आदि के 25 से 40 प्रश लागत तक बढ़ाकर ही बनाई जाती है, जो सर्वे के आधार पर ही केन्द्रीय और राज्यों के सीएसआर के दरों पर भ्रष्टाचार से वसूली के लिए 25 प्रश से 40 प्रश अधिग लागत पर निर्धारित कर ही निविदाएं बुलाई जाकर ठेके जो सबसे कम हो, कार्यादेश जारी किए जाते हैं।

पाठकों को बता दें, नर्मदा पर बनने वाले सभी वृहत, माध्यम, लघु बांधों का नियोजन, मप्र शासन के 1956 में अस्तित्व में आने के बाद की तात्कालिक योजना नहीं थी, वरन अंग्रेजों की यह योजना सन् 1900 के आस-पास से नियोजित थी, पर उसी समय आजादी के आंदोलन को कुचलने और नियंत्रित करने में उलझने के कारण साकार नहीं हो सकी, जिस पर सन् 1970 के बाद कार्य शुरू हो सका, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस टोपो शीट के आधार पर पूरे भारत के केन्द्रीय और राज्यों के सभी कार्य विभागों से लेकर वैमानिकी के हवाई अड्डों पर विमानों का भूर्स्पशया लैंडिंग और हैलीकाप्टर्स का भूस्पर्श करवाया जाता है। रेलवे के हर स्टेशन पर नाम पट्टिका के साथ समुद्र तल से ऊंचाई अंकित की जाती है। आज भी अंग्रेजों को 18वीं शताब्दी की बनाई टोपो मेप पर ही होता है, यह उदाहरण का यथार्थ यह है कि जब उसमें धरती के हर फुट की गहराई, मिट्टी स्थल, चट्टान का ब्यौरा लिखा होने के बाद भी इस नर्मदा घाटी में खुदाई, निर्माण व स्थल की काली चट्टान, लाल, पिली, ठोस कच्ची, मुरम, पीली काली मिट्टी के नाम पर ही अरबों रुपयों के भ्रष्टाचार किए गए और धन हजम कर लिया गया एसे सारे भ्रष्टाचार इस नघा भ्रष्टाचार विकास प्राधि. के 35 से ज्यादा संभागों, 12 से ज्यादा मंडलों में हर कदम पर किए गए जिसके व्हाउचरों सहित, राशि व तारीखों के विवरणों के साथ प्रकाशित किया गया पर मु.मं., मंत्री, राज्य मंत्री से लेकर नीचे उपयंत्रियों और बाबुओं तक के लिए दुधारु गाय से दूध पीना ज्यादा पसंद किया गया किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पिछले वर्ष तैयार की गई नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना में रु. 432 करोड़ की लागत का आंकलन कर निविदाएं जारी की गई तो रु. 397 करोड़ में मेघा इंजिनियरिंग हैदराबाद ने ली, जिसमें 2550 पाइप 2 मी. व्यास के खरीदी बिल लगाया जबकि पाइप 1.80 व्यास का ही था, 10 प्रश यहां अधिक भुगतान किया, लोहो ढलवा होना था, लोहा हल्का स्ट्रक्चरल स्टील का था, 2550 पाइप पर जंग से सुरक्षा के लिए जो सीमेंट व अन्य का लेपण किया गया, 2550×20 मीटर 51000 मी. पर 10×2×40 सेमी हर पाइप के दोनों छोरों पर जोड़ने के लिए कम किया गया अर्थात 1,02,00,000 1020 मीटर कम किया गया पर भुगतान पूरा कर लिया गया, जो अंकेक्षण रिपोर्ट में ध्यान में लाया गया। खुलकर बंदरबांट उपयंत्री जिसने मा. पु. भरी, सहा. यंत्री जिसने सत्यापित किया और का.यं. जिसने सबके बिल भुगतान किए, अं. यं. चौहान मुख्य अभियंता अजनारे से लेकर प्रमुख अभियंता, उपाध्यक्ष, रजनीश वैश, मुमं. तक सबने धन बांटा।

इसी प्रकार मुख्य अभियंता निचली नर्मदा परि. से प्राप्त जानकारी के अनुसार आदिवासी समायोजना, राज्य उपयोजना में 14-15 में रु. 3.40 करोड़ मिले, खर्च 1.1.15 से 31.03.15 तक रुपए 1 करोड़ मिले खर्च, वही जोबट में रु. 4.642 करोड़ मिले जिसमें अंतिम त्रिमाही में रु. 1 करोड़ खर्च 1 वर्ष भर में रु. 8.042 करोड़ खर्च केवल कागजों पर, क्योंकि परियोजना पूर्ण तो वर्षों पहले हो चुकी हैं, परंतु नहरों में वर्षों गुजर गए, कीमत तीन गुनी हो गई, अनु. जाति मद में ओंकारेश्वर परि. में रु. 45 करोड़ मिले, अंतिम तिमाही में रु. 5 करोड़ खर्च करना था, मात्र रु. 1.52 लाख खर्च बाकी पैसा समर्पित, 13-14 में मान को आंवटन में रु. 6.184 करोड़, खर्च रु. 6.91 करोड़,रु. 260 करोड़ आवंटित, 31.03.14 तक रु. 407.6 करोड़ खर्च, इन सबका 60 प्रश पैसा हजम, ओंकारेश्वर को 14-15 में रु. 376.75 करोड़ मिले, जिसमें से रु. 79 करोड़ खर्च, अंतिम तिमाही में जिसका आवंटन रु. 148 करोड़ था, इा रु. 79 करोड़ मेंसे वास्तविक कार्य हुआ मात्र रु. 29 करोड़ का बाकी हजम सं.क. 32,8, 20 व 30 मनावर।

उच्च न्यायालय की फटकार के चलते दायीं तट नहर में पानी अंतिम छोर तक पहुंच गया है। परंतु बाई तट नहर अभी भी बांध के पानी के इंतजार में है, जब रख-रखाव के अभाव में दूसरा स्तरहीन और घटिया निर्माण से बर्बाद हो रही है जिसकी गाहे बगाहे मरम्मत कर दी जाती है, न केवले तल वरन दोनों तरफ का सीमेंटीकरण भी बुरी तरह से चटक और दरारों से भरा है, कहीं पर भी वर्मा न होने के कारण दाएं-बाएं निरीक्षण पथ का कचरा, मिट्टी, पत्थर भी नहर तल पर गिरकर बर्बाद कर रहा है। यह सब उपयंत्री, सहा. यंत्री, सहा. यंत्री, का.यं., अं.यं., मु.अभियंता से लेकर सदस्य उपाध्यक्ष, मंत्री और मु.मं. की ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर लूट और भ्रष्टाचार से कमाई का परिणाम है, जहां तिगुनी लागत खर्चने के बाद भी सिंचाई नहीं की जा पा रही हैं।

समयमाया ने पूर्व के प्रकाशनों में 6 वर्ष से ज्यादा समय से सेवानिवृत्त हो चुके संविदा पर पुनः, मु.अ. विद्युत व यां., लो.नि.वि, सचिव, जल संग्रहण व जल सिंचित क्षेत्र विकास का कार्यभार इस हरामखोर जालसाज बीपीएस परिहार को 14 अक्टू 2014 से पुनः सौंप दिया गया है उस भ्रष्ट प्र.सं. व उपाध्यक्ष इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी रजनीश वैश्य, मु.सं. डिसा व मु.मं. शिवराज की मेहरबानी से भ्रष्टाचार और वसूली करने के लिए, पूरे न.घा. भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण में ऊपरी नर्मदा परियोजना से लेकर निचली नर्मदा परि. और इं.सा. बांध, नहरों के कार्यों में अरबों रुपए का आवंटन आता है 50 प्रश भी कार्य नहीं होता और 50 प्रश तक पैसा हजम कर लिया जाता है।

यही कारण है कि मुख्यालय से लेकर इं.सा. नहरों तक में बैठे धूर्त और मक्कारों की फौज सूचना के अधिकार में कोई जानकारी नहीं देना चाहती।

गरीब व मध्यमवर्गीय ही मरेंगे 2005 के नोट बंद करने में

प्रथम पृष्ठ का शेष

न ही ग्रामीण आबादी के साथ 90 प्रतिशत शहरीय आबादी को पता ही नहीं है कि रु. 500 व 1000 के नोट पर सन् कहां लिखा होता है। जिसे वो देखकर यह जानकार पता लगा सकें कि नोट 2005 से पूर्व का है या बाद का तो ये नोट चलन से बाहर करेंगे, यदि रिजर्वबैंक ने बंद कर भी दिए तो भी ये वर्षो तक नगद लेन-देन में चलते रहेंगे, और शातिर किस्म के लोगों के साथ ऐसे नोटों को छापने की अपेक्षा नगद लेन-देन के साथ एटीएम मशीनों से भी बांटते रहेंगे, क्योंकि अभी भी देश की 90 प्रश आबादी नगद लेन-लेन ही पसंद करती है, फिर क्या सड़क पर बैठे सब्जी, चाय, किराना, पंचर जोड़ने वाला, क्रेडिट, डेबिट कार्ड से तो भुगतान लेगा-देगा नहीं, उसे तो नगद ही चाहिए।

जिस देश की आबादी ही 20 प्रश पढ़ी-लिखी न हो, 35 प्रश गरीबी रेखा के नीचे रहकर गुजर-बसर कर रहे हैं। जहां चारों और आम आदमी को ठगने और लूटने के लिए शासकीय कार्यालयों से लेकर बैंकों तक में अजगरों और नागों का बसेरा हो, जहां स्मार्ट सिटी का सपना दिखाने वाले 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति नहीं कर सकता तो कम्प्यूटर और इंटरनेट कैसे चलेगा, वहां नगद लेन-देन पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। फिर रु. 500 की से दिन की मजदूरी यदि उसने2005 के पहले छपे हुए नोट से कर दी तो वह दैनिक वैतनभोगी तो भूखा ही मर जाएगा, फिर हमारा पाखंडी नौटंकीबाज मोदी तो चाहता ही है कि सारे गरीब ही मर जाए, फिर मोदी बताए कि उसके पास रु. 4-5 लाख करोड़ कहां से आया, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए वह कालाधन कहां से आया। अडानी, अंबानी, टाटा, ड्रग माफिया, भूमाफिया, खदान माफिया जैसे 5000 से ज्यादा कार्पोरेट क्रिमिनल के पास देश और देश के बाहर रु. 50 खरब से ज्यादा का कालाधन है, नोट बंद करने के बजाए उनपर सीधी कार्रवाई क्यों नहीं करते।

मोदी देश के प्रधानमंत्री या अडानी-अंबानी के व्यापार प्रतिनिधि

प्रथम पृष्ठ का शेष

क्या किया मोदी ने, इसके विपरीत अपने मित्रों, अडानी और अंबानी के लिए वहां पर 4600 में.वा. विद्युत उत्पादन के साथ ही भारत से केजीवेसिन-6 के कुओं से प्राप्त गैस को बैंचने के मोटे सौदे किए, उत्खनन के लिए खदाने लीज पर ले लेना स्वाभाविक था, इनके हजारों करोड़ रु. की व्यवसायिक समझौते से फायदा पहुंचाया गया, अर्थात देश के जन-धन से यात्राएं की, राष्ट्र की संपत्तियों का हस्तांतरण किया और लाभ उठाया अडानी अंबानी ने।

यही हाल दो बार की चीन यात्रा फ्रांस, आस्ट्रेलिया, अमेरिका व अन्य देशों की यात्रा में भी किया, जनहितों को दरकिनारकर इन बड़े कार्पोरेट वित्तीय अपराधियों जिनका कालाधन विदेशों में तो जमा है ही साथ ही लाखों करोड़ के बैंक ऋणों से अपना व्यापार कर एक तरफ मात्र अंबानी बंधु हजारों करोड़ हर दिन मोबाइल सेवाओं में, पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री में करके भी हजारों करोड़ प्रतिदिन की एक्साइज वेट कर रहे हैं। यही हाल मोबाइल सेवाओं में टाटा, बिरला, एयरटेल, वीडियोकोन के साथ बीएसएनएल भी इनकमिंग कॉल पर भी अरबों रु. काट लेता है, ऐसे कार्पोरेट क्रिमिनल जो जनता को हर दिन हजारों करोड़ जनता से लूटा है, उनके विरूद्ध कार्रवाई की अपेक्षा अपनी विदेश यात्राओं में उनके लिए राष्ट्र हितों को भी दांव पर लगाने से नहीं चूकता।

मप्र वाणिज्यकर मंत्री-संत्री सभी भ्रष्ट

लेन-देन के लिए 6 माह लटकाई पदोन्नतियां

सूचना के अधिकार में मंत्रालय से जानकारियां मांगी, आदेशजारी करना मजबूरी बन गया

इंदौर। मप्र के वाणिज्यकर में मुख्यालय से लेकर नीचे तक अवैध वसूली से शासन के अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जाता है, इस तथ्य की पुष्टि, हाल ही में पड़े लोकायुक्त के छापे से स्पष्ट होती है, इसके विपरीत हर मलाईदार और कमाई के पदों पर, प्रदेश के अंतराज्यीय नाकों पर, एंटी इवेजन ब्यूरो के चुन-चुन कर भ्रष्टों और जालसाज कर सहायकों, निरीक्षकों, सहा. वा. कर अधिकारियों, सहा. आयुक्तों से नियुक्तियां ही धन लेकर की जाएगी, तो फिर क्यों नहीं अधिकारी कर्मचारी दिए गए धन की वसूली करेगा, रु. 1 लाख अधिकारी कर्मचारी तभी देगा जब उसे नाकों पर 6-6 महीनों में स्टाफ बदलने की प्रथा और नियम है, तो क्यों अधिकारी कर्मचारी साल-साल, दो साल तक रुके रहते हैं। वही हाल प्रदेश की एंटी इवेजन विंग के है, सहा.वा.कर अधिकारी प्रमिभा करारी विंग ए. का देवास, उज्जैन का इतिहास ही भ्रष्टाचारपूर्ण रहा और पिछले दो वर्षों से चारों तरफ इस विंग में रहकर ड्यूटी टाइम के अतिरिक्त भी ट्रकों को पकड़ना, उनसे रु. 10-15 हजार तक वसूलना सौदा नहीं तो यह धूर्त और चालाक उन्हें अफीम गोदाम तक लाती है, अन्यथा बाहर के बाहर ही विदाई समारोह संपन्न कर देती है।

सूत्रों की मानें तो इसके द्वारा और इसके अड्डों पर बैठाएं एजेंटों के द्वारा औसतन रु. 1 से 2 लाख तक की वसूली हजम कर जाती है। यदि इसके घर पर अचानक छापा मारा जाता तो रु. 5 करोड़ से ज्यादा नगदी पकड़ी जा सकती थी, काफी शिकायतों के बाद इसे ऑडिट विंग में भेजा गया।

वसूली के लिए बाकायदा षड्यंत्र वाणिज्यकर मंत्रालय से ही रचा जाता है, सित. 14 में सभी अधिकारियों की पदोन्नति समीतियां की बैठक दो बार होनी चाहिए, वह सन् 2014 में बड़े दबावों के बाद 18 सितम्बर 2014 को की गई, और वसूली के लिए महाभ्रष्ट जालसाज प्र.स. मनोज श्रीवास्तव मंत्री जयंत मलैया ने दबाकर रख दी, सारे अधिकारी जिस में उपायुक्तों, सहा. आयुक्तों, वा.क.अ., सहा. वा.कर. अ. तक इंतजार करते रहे, कि अनु. पदोन्नति और स्थानांतरण की सूची निकलेगी, अब निकलेगी करते-करते, 7 माह गुजर गए, प्रतीक्षारत सभी का उलाहना श्री अजमेरा को झेलना पड़ता था, कि कैसा पत्रकार और आरटीआई एक्टीविस्ट हो कि सूची जारी नहीं करवा पा रहे और न ही मालूम कर रहे हो कि क्या हुआ उस पदोन्नति सभी बैठक का, अंत में जब श्री अजमेरा ने प्र.स.म.प्र. वाणिज्यकर मंत्रालय से अप्रैल में जानकारी मांगी तो मई में कोई जवाब तो नहीं मिला, परंतु पदोन्नतियों की सूचियां निकलना अवश्य शुरू हो गई, पत्र का जवाब न मिलने के बाद जब अपील की गई। लगातार सूचियां निकल गई पर इस बीच हर पद और पदस्थापना के लिए खुलकर लेन-देन हुआ, विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार रु. 80 लाख में इंदौर एंटी इवेजन में दूसरा रु. 50 लाख में हुआ यही सौदा भोपाल एंटी इवेजन उपायुक्त के लिए जबलपुर उपायुक्त रु. 35 लाख, सतना के रु. 30 लाख और रु. 20 लाख में ग्वालियर के सौदे के अपुष्ट समाचार, मंत्री के वर्तमान ओएसडर के माध्यम से हुए, और सारे पूर्व के महाभ्रष्ट सहा. आयुक्तों को, उपायुक्तों को पदोन्नति के साथ मनचाहे स्थान पर पदस्थ कर दिया गया, स्वाभाविक था इतनी मोटी राशि का लेन-देन पूर्व के महाभ्रष्ट और सरकार का अरबों रु. का राजस्व चोरी करवाने वाले ऐतिहासिक भ्रष्ट ही करते थे, जबकि एंटी इवेजन में पदस्थ किए गए उपायुक्तों में कुछ के विरूद्ध जांचे भी लंबित थी, भोपाल एंटी इवेजन का उपायुक्त ओपी पांडेय तो छापे के दौरान सोने का बिस्कुट जेब में डालते हुए कैमरे में भी कैद हो चुका हैं, पर बंदे ने एंटी इवेजन पदस्थापना में मोटा धन देकर, एक में एक फ्री की कहावत को चरितार्थ करते हुए अपने पुत्र को एंटी इवेजन इंदौर में पदस्थ करवा लिया, धन के दम पर ही जिसने जहां स्थानांतरण और पदस्थापना चाही जो जनवरी से ही निश्चित था मिल गई। मोटे लेन-देन की आशा में ये पदोन्नतियां और स्थानांतरण ओदश दिसम्बर से तैयार होन के बाद भी रोककर रखे गए थे, ताकि मोटा लेन-देन कर जरूरत पढ़ने पर स्थानांतरण बदले जा सके, ज्यादा मोटी बोली लगाने वाले को मनचाही पदस्थापना दी जा सके।जब अप्रैल तक सूचियां जारी नहीं हुई और हर प्रतीक्षारत अधिकारी ने हम से कहा तो अंत में सूचना के अधिकार में प्रस. मनोज श्रीवास्तव से जानकारी मांगी गई, अब जब जानकारी देने में उलझन बढ़ी तो पहले सबकी सूचियां जारी की गई, तब तक एक माह पूरा होने के बाद उस संबंध में अपील की गई, जिसके जवाब में 23.06.15 को पत्र के साथ सारी सूचियां संलग्न की गई।

29.12.2014 को पत्र क्रमांक एफए 6-28/2014/01/5 दिनांक 29.01.2014 को वा.क्र.अ. एएल वर्मा श्री एसएम कानूनगो, एके हार्डीकर, जीडी माहेश्वरी, श्री बीके अरोरा व सुश्री पारुल अग्रवाल को सहा. आयुक्त के पद पर पदोन्नति आदेश को मई में जारी किया गया, यह आदेश यदि तुरंत ही जारी कर दिया जाता तो इन्हें 6 माह की वरिष्ठता के साथ सहा. आयुक्त वेतनमान मिलता, दूसरा आदेश क्रमांक ए6-37/2014/01/5 जो 12/01/2015 को जारी हुआ था, जिसमें 7 सहा.वा.कर अधिकारियों को वा.क. अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया, यह आदेश भी मई में श्री अजमेरा के सू.अ. आवेदन लगाने के बाद ही जारी हुआ, इनकी भी 4 माह की वरिष्ठता और वा.क्र. अ. का वेतनमान की हानि हुई।

दिनांक 13.11.2014 पत्र क्रमांक एफए 6-19/2014/1/5 जिसमें दो उपायुक्तों श्री प्रभाकर शिवहरे व श्रीमती सुमित्रा वर्मा को अपर आयुक्त पदोन्नत कर इंदौर मुख्यालय में ही पदस्थ किया गया, मई में जारी हुआ, दूसरा आदेश दिनांक 16.05.15 पत्र क्रमांक एफए6-19/2014/1/5 श्री जयदेश शर्मा उपायुक्त उज्जैन को अपर आयुक्त इंदौर में पदस्थ किया गया, मई में जारी हुआ।

दिनांक 21.05.15 को आदेश क्रमांक एफए6-20/2014/1/5 जो 18/09/2014 की ही सूची थी जिसमें 4 सहा. आयुक्तों श्री आरके तिवारी, श्री मनोज चौबे, श्री प्रदीप दुबे, श्री धर्मपाल शर्मा को उपायुक्त पदोन्नत किया गया। वसूली के इंतजार में यह सूची भी मई-15 में ही जारी की गई, ये विशुद्ध 4 ब्रह्माणों को ही पदोन्नत किया जो पूर्व के महाघाघ भ्रष्ट थे, इन 4 से मोटा धन मंत्री के विशेष दूत को लाखों में भेंट पूजा -चढ़ाकर ही आदेश दिए गए। जबकि इसी सूचना के अधिकार में वृतों से जानकारियां मांगने पर ये धूर्त तृतीय पक्ष की कहकर, देने से साफ मना कर देते हैं। जिसमें वृत्त क्रमांक 1,12,13 वृत्ति कर, आदि अधिकांश अधिकारी को छुपाने शासन को राजस्व हानि वह भी अरबों रुपए ही कार्य करते हैं। एंटी इवेजन ब्यूरो ने भी सू.अ.में जानकारी देने से जो छूट प्राप्त की है उसका उद्देश्य भी अपनी अवैध वसूली और भ्रष्टाचार को ही छिपाना है।

मप्र सड़क डकैती विकास निगम अमर्यादित

सड़कों पर मौत का तांडव-सत्ताधीशों को वसूली से काम

प्रदेश की राज्य रा. मार्ग की 70 प्रश सड़के कमीशन में गिरवी, सुलेमान, विवेक और शिवराज के लालच ने एक तरफ जनता को लूटवाया दूसरी तरफ हजारों करोड़ की चपत लगाई शासन को, और अब कोई सड़क नहीं बनाएंगे, बीओटी में, स्तरहीन सड़कों पर मौत का तांडव

सड़कों को सुरक्षित, सरल, तीव्रगामी बनाने के नाम शासन ने जिस सड़क का विकास निगम को बनाया था, विदेशी तर्ज पर, वह जैसा कि समयमाया ने पूर्व के प्रकाशनों में लिखा था, पूर्णतः सड़क डकैती विकास निगम बन गया, जिसमें एक तरफ सफेदपोश इंडियन एब्यूसिंग सर्विस के डकैतों, सुलेमान उर्फ आजम गड़िया उसके बाद हरियाणवी बनिए विवेक अग्रवाल जो डकैती विकास निगम के प्रबंध संचालक रह चुके है, ने बड़े पूंजीपतियों के साथ मिलकर दोगुने से चौगुने दरों पर सड़कों के बनाने और रखरखाव के ठेके देकर, स्तरहीन सड़के बनवाई, बनवा रहे हैं और रखरखाव करवा रहे है और महंगाई बड़े न बड़े परंतु 3 वर्ष के स्थान पर हर वर्ष 7 प्रश की दर से टोल दरें तय कर वाहन चालकों को लूटवा रहे हैं।

केन्द्र सरकार के भूतल मंत्रालय के स्पष्ट आदेश के बाद भी कि किसी भी 4 लेन से कम पर टोल नहीं वसूला जाएगा, मु.मं. शिवराज, उसके पूर्व के लो.नि.मं. कैलाश विजयवर्गीय दूसरी पारी के नागोद और तीसरी पारी के सरताज सिंह के साथ प्र.स. व सचिव रहे सुलेमान और विवेक अग्रवाल ने रु. 25 लाख से लेकर रु. 1 करोड़ प्रति किमी तक का कमीशन डकार 40 प्रश सड़के 2 लेन, 30 प्रश सड़के एक लेन और मात्र 30 प्रश 4 लेन रु. 25 लाख प्रति किमी से लेकर रु. 4 करोड़ प्रति किमी में एस्सार, अशोका बिल्डकॉन, पाथ के अग्रोहा जैसे पूर्व के कुख्यात ठेकेदारों को सौंपा जिसकी डीपीआर की लागत को बैंक से ऋण लेकर वित्तपोशित किया जिसमें गारंटी मप्र सरकार की थी, इन चारों पाचों व अन्य हरामखोरों ने मिलकर मप्र शासन का रु. 5000 करोड़ से ज्यादा उलझा दिया अब वे बीओटी ठेकेदार न तो बैंकों की किस्त भर रहे हैं न ही सड़कों का रखरखाव कर रहे हैं। बस दोनों हाथों से जनता को टोल के माध्यम से लूटने में लगे हैं। नतीजा सड़कों पर दूर्घटनाओं में हर दिन 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही हैं। 100-200 के हाथ पैर टूटकर घायल हो रहे हैं। पर इन रक्त पिचास राक्षसों को अभी भी कमीशन से ही मतलब है, बैंक की किस्तें जमा हो न हो, सड़के ऊबड़ खाबड़ हो, संभागीय प्रबंधकों को ये ठेकेदार बिल्कुल नहीं सुनते हैं। उनकी लिखा पढ़ी पर कोई ध्यान देने को तो दूर, सीधे कहते हैं कि हमारी प्र.स. और मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत है, आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं तब तक वो संभागीय कार्यालयों को टुकड़ा डालते हैं।

बेशक इन संभागीय कार्यालयों में भी म.प्र.लो.नि.वि. के सारे चुने हुए भ्रष्टों और निकम्मों की फौज को बैठाया ही इसीलिए गया था ताकि ठेकेदारों के कार्यों में औपचारिक खाना पूर्ति की जा सकें, बाकी लेन-देन तो भोपाल के सड़क डकैती निगम में ही हो, अर्थात अरबों रुपए हजम करके भागे सुलेमान, अग्रवाल जैसे धूर्त मक्कारों पर कोई आंच न आए, मरें तो ये संभागीय प्रबंध आदि।

उज्जैन संभाग की इस सड़क डकैती की अधिकांश सड़के जिसमें उज्जैन, झालावाड़, लेबड़ तथा गांव व अन्य सभी जहां टोल वसूली की जाती है, चाहे 1,2,4 लेन हो हालात दयनीय है, साथ ही उज्जैन बाइपास जो वर्तमान में स.प्र. राकेश जैन के द्वारा बनवाया जा रहा है, उसमें भी न केवल भारी भ्रष्टाचार किया जाने के साथ शांति पैलेस होटल के लिए, नक्शे से अलग सड़क बनाई गई, बिजली के खंभों पुराने खंभों को ही नया रंग पोतकर खड़ा कर दिया गया, यही हाल उज्जैन संभाग के सातों जिलों की सड़कों में चाहे तो मंडी निधि एडीबी या बीओटी आदि की हो कमाई के लिए हर प्रकार की जालसाजी की जा रही है, सबका एक ही उद्देश्य है वसूली करो, कार्य कैसा भी हो, सड़को की गुणवत्ता कैसी भी हो, सरकार खराब होने पर फिर पैसा देगी, फिर हजम करने का मौका मिलेगा।

इन हरामखोर संभागीय प्रबंधकों, सलाहकारों से लेकर मुख्यालय में बैठे मुख्य प्रबंधकों, प्र. संचालकों, प्रधान सचिव प्रमोद अग्रवाल, मंत्री सरताज सिंग से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़को की गुणवत्ता और चौड़ाई के कारण सड़कों पर कितनी दूर्घटनाएं हो रही हैं। कितने लोग मर रहे है, कितने घायल हो रहे हैं। कितने घरों के चिराग सड़को पर बुझ रहे है। इन गिद्धों को पैसा चाहिए, इन सब जालसाजों ने अनुबंध कर सड़कें, टोल टैक्स ठेकेदारों को सौंप दी तू जनता को लूट, और हमें हमारा कमीशन पहुंचा, इंदौर पर 203 किमी सड़क जो जालसाज अशोका बिल्डकॉन के पास है, रुपए डेढ़ अरब से ज्यादा हर वर्ष कमाई कर रहा है, परंतु उन मक्कारों को 12-12 वर्ष बाद भी पट्टियां नहीं भरी, 5-5 फीट सड़क के दोनों और हर वर्ष 33 प्रश का पुर्न निर्माण भी नहीं किया काम चलाया जाता रहा, दूसरी ओर अकेले इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों के उपप्रबंधक के रूप में बैठाया गया धूर्त सूर्यवंशी जिसके पास लगभग 3000 किमी से ज्यादा की बीओटी सड़के हैं, सबका महीना खाकर और कुछ हिस्सा ऊपर पहुंचाकर, शांति से समय पूरा कर रहा हैं, 70 प्रश सड़कों पर हालात दयनीय होने के बाद भी कोई कुछ भी इन हरामखोर जालसाज, टोलबाथ ठेकेदारों की लूट और खराब सड़कों के विरूद्ध बोलने को तैयार नहीं है। इंदौर के संभाग 1 में बैठे टेंटवाल को भी 10 वर्ष हो गए, दो के संप्र बोरासी को भी 3 वर्ष से ज्यादा गुजर जाने के बाद न तो इनका स्थानांतरण किया जाता है, न ही इनके गुणवत्ताहीन कार्यों और भ्रष्टाचारों की बारीकी से जांच की जाती है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगो तो न केवल आधी अधूरी वरन अपील करने पर मुख्यालय में बैठा पूर्व का इंदौर का एसडीएम रह अनवादेक से मोटा धन वसूलकर आवेदक की अपीलों को एकतरफा खारिज कर देता है, वैसे भी उसका इस सड़क डकैती विकास निगम के भ्रष्टाचार के कारण जो रु. 5000 करोड़ से ज्यादा के ऋणों की गारंटी बैंकों को इन बीओटी ठेकेदारों के लिए दी थी, वो एक तरफ न तो ब्याज और किस्त चुका रहे है, न वसूले गए टोल से सड़के सुधार रहे हैं। बस उन्हें सीधे मोटे खर्च दिखाकर वसूला गया टोल आसानी से हजम कर रहे है। वैसे इस टोल स्वीकृति और डीपीआर की स्वीकृति के मामलों में आज भगड़िया सुलेमान और इस हरियाणवी विवके अग्रवाले की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इन दोनों धूर्तों ने ही मोटा धन डकार कर दुगनी से 5गुनी लागत स्वीकृत कर बैंकों को गारंटी देकर ऋण दिलवाया था, जो अब शासन के गले की फांस बन चुका है। अगर शासन नहीं चेता और सड़क डकैती विकास निगम शीघ्र बंद कर सारे टोल नाके छुड़ाकर बैंक ऋण की भरपाई नहीं की तो ये ऋण 5 वर्ष में ही दुगुना हो जाएगा, साथ ही फिर सड़के मरम्मत योग्य भी नहीं रहेगी, उनका पुनर्निर्माण ही करना पड़ेगा, जो बड़ा घाटे का सौदा बनेगा और वाहन चालकों की दुर्घटना और मौत का कारण भी बनेगा।

स्थानांतरण उद्योग से प्रदेश के मंत्रियों से लेकर सचिवों, विभाग प्रमुखों ने काटी चांदी

रु. 5000 करोड़ के लेन-देन से चला स्थानांतरण, पदोन्नति व पदस्थापना उद्योग

गृह, जल, वित्त, वाणिज्य कर, आबकारी, जल संसाधन, कृषि स्वास्थ्य, लो.नि., लो.स्वा., श्रम पंचायतों, महिला बाल विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आदि 100 से ज्यादा विभागों, मंडलों, निगमों आदि में 10000 से ज्यादा कर्मचारियों अधिकारियों में हुआ खुलकर वसूली का खेल

मप्र में पिछले लगभग 20 वर्षों से पहले, विधान सभा फिर लोकसभा उसके उपरांत नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों, मंडी आदि के चुनावों के कारण आचार संहिता के चलते शास. कर्मचारियों, अधिकारियों की पदोन्नतियां, स्थानांतरण आदि रूके हुए थे, जो कि मंत्रियों, संत्रियों, दलालों की कमाई का सबसे सुरक्षित आसान व सटीक स्त्रोत है, दूसरी ओर हम मंत्री, नेता, सांसद, विधायकों के चुनाव में जो पैसा लगाया था, उसकी वसूली के इंतजार में थे, जिसका मौका मई-जून 2013 के बाद मिला, फिर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो भ्रष्ट और शातिर और समझदार है, वे भी चाहते है कि उनके कुकर्मों और भ्रष्टाचारों की कारगुजारियों का भांडा फूटे उसके पहले नई मनचाही जगह स्थानांतरण लेकर खिसक लो, ताकि हल्ला भी न मचे और माल भी आसानी से पचे, इसके लिए कमाई में से कुछ हिस्सा देना भी चाहे तो चलेगा, कुल कमाई का 2 से 5 प्रश बांटना पड़े तो क्या परेशानी है,बेशक दूसरी ओर लालची किस्म के अधिकारी, कर्मचारी ज्यादा कमाई के चलते खर्च करके वर्षों तक कुंडली मारे बैठे रहते हैं। इसके लिए भी चढ़ोत्रा नीचे से लेकर ऊपर तक बांटना पड़ता है, तभी वो लंबे समय तक एक ही स्थान पर टिके रह सकते हैं। जो यथार्थ में उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यह खेल प्र.स. सचिव से लेकर हर विभाग के बाबू, चपरासियों तक हर विभाग की कहानी है। बेशक स्थानांतरण सजा और मजा दोनों का ही हिस्सा है, जो खर्च करके जाता है। तो मजे के लिए करता है, जो खर्च नहीं करता और मनचाही जगह नहीं मिलती उसके लिए सजा है।

इन सबके विपरीत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है अधिकारियों के हर 3 प्रश वर्ष में 333 प्रश स्थानांतरण और कर्मचारियों के 3-4 वर्ष में 25 प्रश स्थानांतरण हर विभाग में मुख्यालय से लेकर ग्रामीण विकास खंडों, थानों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों तक होने ही चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही कर्मचारियों, अधिकारियों में जाजगी, कार्यक्षमता, दक्षता, मिलनसारिता, समायोजन और सामंजस्य की क्षमता बनी रहे और हर नए स्थान पर कर्मचारी, अधिकारी अपने आप का श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में अपने कर्तव्यों का उचित तरह से निर्वहन कर सकने में सक्षम बना रहे, जिसमें सत्यता में प्रशासनिक फेरबदल हर स्तर पर, हर विभाग में मुख्यालय में चलते रहना चाहिए, ताकि हर स्तर पर भय बना रहे, अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचार करने, कार्यों में और कर्तव्य पारायणता में ढिलाई बरतने की वह सोच भी न सके।

निसंदेह ये आदर्श लोक सह लूटतांत्रिक व्यवस्था के किस्से कभी नहीं रहे, अगर भ्रष्टाचार ही समाप्त हो गया तो नेताओं के पास चुनाव लड़ने का चंदा कहां से आएगा, नेता के साथ कार्यकर्ताओं की भीड़, झंडे बैनर के खर्च कहां से आएगा फिर विधायक, सांसद से लेकर पार्षद, पंच, सरपंच बनने का मतलब तो ये तो नहीं जीत जाने के बाद सत्यवादी राजा हरिशचंद्र या उसका पुत्र बन श्मशान में धुनी रमाओ जीतने के बाद 5 वर्ष में जितना लूट सके तो लूट अन्यथा अंतकाल पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट।

इसलिए इन राजनीतिज्ञ डकैतों का सबसे आसान लक्ष्य होते हैं, सरकारी कर्मचारी सत्ता में बैठे पंच-सरपंचों से लेकर चुने हुए पार्षद, विधायक और सांसद में रहकर मौके की तलाश में रहते है। स्थानांतरण, जांच समाप्त करवाने, शिकायत दबवाने, समाप्त करवाने के लिए इन सरपंचों से लेकर सांसदों तक की पहुंच के बदले खुलकर वसूली की जाती है। स्वाभाविक है, ये मौका दो वर्ष बाद हाथ आया, दो वर्ष से हर विभाग के इस अवसर की प्रतीक्षा की जा रही थी, मंत्रियों, विधायकों से लेकर मुख्यालयों में बैठे भ्रष्ट अधिकारी, सत्ता के दलालों ने जो हर विभाग में अलग किस्म के हैं, स्थानांतरण खुलते ही सक्रिय हो गए थे, सबने स्थानांतरण पदस्थापना आदि में जमकर धन बटोरा, जो कि लगभग लेन-देन और थोक स्थानांतरण में लगभग रु. 5000 करोड़ तक गया।

गृह मंत्री बाबूलाल गौर का पुलिस विभाग भ्रष्टाचार, जालसाजी और वसूली के लिए अपराधियों को पालने संरक्षण देने में भी इसकी भूमिका को हर कोई जानता है यहां भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबलों से लेकर सहा. उप थाना निरीक्षकों, सीएसपी, डीएसपी, एसपीआई, आईजी, डीआईजी, तक सभी पदों के स्थानांतरण मनचाही पदस्थापना थाना, शहर आदि के लिए खुलकर रु. 25000 से लेकर करोड़ों तक चला, जैसा पद, पदस्थापना वैसा दाम और वैसा काम। रु. 1000 करोड़ से ज्यादा का खेल हुआ यहां पर जिसमें विभाग बदलने, कमाई वाले पदों पर जाने यातायात पुलिस में जाने परिवहन विभाग में जाने आदि की कीमतें अलग से वसूली गई, वहीं हाल जेल विभाग में भी खुलकर चला, जैसी कमाई वैसी वसूली की पूर्ण पारदर्शिता बरती गई।

दूसरा था मंत्री जयंत मलैया जिनके पास वित्त, वाणिज्यकर, आबकरी विभाग, मप्र जल संसाधन जैसे भ्रष्ट विभाग थे, अकेले वाणिज्य कर के एंटी इवेजन के जाने के लिए उपायुक्तों ने रु. 50 से 80 लाख तक खर्च किए, यही कारण था सभी छटे हुए भ्रष्ट जैसे उपायुक्त डीपी शर्मा, ए मे, उपायुक्त आर के शर्मा बी में, उपायुक्त ओ पी पांडेय भोपाल में, उपायुक्त सलूजा सतना में, उपायुक्त बैस ग्वालियर में, उपायुक्त प्रदीप दुबे जबलपुर में, जिनके भ्रष्टाचार के पुराने इतिहास है, कईयों पर जांचे भी लंबित है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

गैस सब्सिडी से रु. 6000 करोड़ का बैंको को फायदा

भारत की सत्ता में बैठे धूर्त, मक्कार प्र.मं. मोदी हो या मनमोहन ये जनता को अनुदान गैस पर, पेट्रोल, डीजल कृषि आदि में जो दते हैं वो ये जालसाज अपने बाप के घर से लाकर जनता को बांटते है। जिसका ये एहसान जनता पर लादते हैं।

पूंजीपतियों से चंदा खाने वाले शूकरों की फौज पहले तो तेल गैस के कुओं को जिसे ओएनजीसी ने खोदा था, मिट्टी के मोल, अंबानी गिद्धों को सौंपती है, फिर वहीं गैस वो 4 डॉलर प्रतिघन मीटर में बांग्लादेश को बेंचता है, जबकि ये सरकारी गिद्ध उसी का भाव 8-4 डॉलर चुकाते हैं। दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल जो 30 प्रश तक देश में निकलता है उसकी बात नहीं करते, जो विदेशो से खरीदते हैं। उसका भर चिलाते हैं। और जनता से 31 प्रश एक्साइज 2 प्रश शिक्षा, 2 प्रश स्वास्थ्य, 2 प्रश सड़क, 2 प्रश अन्य अतिकार वसूलते हैं। वहीं मप्र की सरकार 32 प्रश विक्रय/वाणिज्य/ वैट वसूलती है। जो देश में अरबों करोड़ में होता है प्रतिदिन। इस वसूली के बारे में सारे सत्ताधीश बिलकुल चुप रहते हैं। यदि 10-20 प्रश अनुदान दे भी दिया तो क्यों ये डकैतों का गिरोह अनुदान-अनुदान चिल्लाता है।

फिर अनुदान देने के नाम पर बैंकों में खाते खुलवाओ, आधार कार्ड बनवाओ, पंजीयन करवाओ, जबकि बैंकों में बैठा भ्रष्ट, जालसाज, महाबत्तमीज स्टॉफ, जिन ग्राहकों के व्यवसाय से वेतन पाता है, उन्हें जानवरोंसे ज्यादा बत्तमीज तरीके से पेश आता है। क्या खाते खुलवाए, कैसे बीमा करवाएं और कैसे अनुदान पर निजी बैंकों में तो हर कदम तरह-तरह के शुल्कों के नाम पर खुली वसूली होती है। सरकारी बैंकों जिसमें स्टेट बैंक व अन्य 27 सरकारी बैंकों में भी चालू खातों में बिना कुछ किए ही रु. 1000-500 उड़ा दिए जाते हैं। बचत खाते में भी एटीएम जारी करने लेने-देन के नाम पर प्रति लेन-देन रु. 50 से 100 तक उड़ा दिए जाते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में ब्याज, उस पर सरचार्ज के नाम पर जनता की जेबों पर बिना बताए अरबों रुपए की डकैती हर दिन ये बैंक देशभर में डालते हैं।

अब गैस अनुदान के नाम पर माने कि देश भर में10 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं। हर महीने 1 सिलेंडर गैस के अनुदान पर रु. 50 का लेन-देन शुल्क काटा जाएगा, अर्थात रु. 500 करोड़ तो अनुदान का बैंक ही हजम कर जाएगी, जो वर्षभर में रु. 6000 करोड़ होगा, जो सीधा जनता की जेब से जाएगा।

ये वर्तमान में जो लालच दिया जाकर जनता के बैंक खातों को सीधे सेंध लगाने और कब जनता के खातों से रु. 2000-5000 बैंकर गायब कर देंगे, सरकार वसूलेगी मालूम भी नहीं पड़ेगा, अभी भी इस अंकीकरण या डिजिटलाइजेशन मे नाम पर भारत के बैंक खातों में हैकर्स, जालसाज न केवल भारत में वरन् पाकिस्तान व अन्य देशों में बैठकर भी निकाल लेते है दूसरी और प्राकृतिक आपदा युद्ध या अन्य किसी आपदा, इंटरनेट हैकरों की मेहरबानी जो दुनिया के किसी भी कोने से हो सकती है, वायरस विद्युत के अभाव में जब इंटरनेट फेल होगा, तब क्या होगा, और यह होगा ही, क्योंकि दुनिया केा अब आसानी से इंटरनेट बंद कर जाम किया जा सकता है। दुनिया में मुस्लिम आतंकवाद, गैर मुस्लिमों के इकट्ठे होकर जवाब न देने के कारण फैल रहा है, इससे कोई देश अछूता नहीं है, फिर भारत पर तो न केवल दुश्मनों चीन, पाकिस्तान के साथ ही दोस्ती का दंभ भरने वाले अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों की भी नजर है।

पहले बीआरटीएस अब मेट्रो के नाम बर्बाद करेंगे

15 वर्ष व रु. 1 लाख करोड़ से ज्यादा की होगी मेट्रो ट्रेन परियोजना

सन् 2030 तक झेलनी पड़ेगी जनता को पीड़ा, रु. 1 लाख करोड़ में से रु. 50000 करोड़ हजम करेंगे मंत्री, नेता, अधिकारी, इंजीनियर

भारत में जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे ज्यादा हैं, वहीं दूसरी और विक्रय कर आयकर, कस्टम, एक्साइज, संपत्तिकर, जलकर, निगमों के कर, बिजली की कीमतें, देश में और देश के मप्र में ही सबसे ज्यादा डकैती डाली जाती है, जनता की जेबों पर

मप्र में भाजपा को तीसरी पारी में राज करने का मौका क्या मिला इस जालसाज हरामखोर मु.मं. शिवराज ने लूट का तांडव मचाना शुरू कर दिया, यथार्थ में ये कांग्रेस के भ्रष्टों का भी पीछे छोड़ राक्षस बन न केवल जनता को वरन् राज्य की प्राकृतिक संपदा से लेकर जनधन से निर्मित संपदाओं यथा बिजली, पानी, सड़कें, शासकीय भूमि, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, बाग-बगीचों, भवनों आदि तक को मोटा कमीशन हजम कर निजी क्षेत्रों को सौंपने पर तुले हैं। जैसा कि जनधन से निर्मित सड़को को चलने योग्य बनाकर रखरखाव करने के नाम पर बीओटी के ठेकेदारों को मोटा कमीशन हजम कर, 10-12, 15-30 वर्षों के लिए सौंप दी, अब वह न तो रखरखाव कर रहा है, न मरम्मत बस खंभे ठोक, वसूली कक्ष बनाकर दोनों हाथों से वसूली कर रहा है। जनता लूटने के साथ सड़कों को दयनीय स्थिति के कारण मर रही है, जिसका एक उदाहरण इंदौर के बीआरटीएस का भी देखा जा सकता है, जिस जनधन के बीआरटीएस की डीपीआर रु. 650 करोड़ की थी दो साल में बननी थी रुपए 1100 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बाद 6-7 वर्ष में बनी अब उसमें एआईटीसीएल जिसका वैधानिक अस्तित्व ही संदिग्ध है, केवल 20-25 बसें तो भी किराए पर लेकर चलाई जा रही है। दोनों

तरफ भारी यातायात से जनता परेशान हो रही है। भोपाल के बीआरटीएस में पीपीपी के अंतर्गत यह कार्य परपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस चला रही है। जो कि न केवल भारी जालसाज है वरन गाड़ियां भी ठेकेदारों से लेकर ही चलाई जा रही है। एक तरफ यात्रियों से लूट, दूसरी तरफ भारी यातायात जो दोनों तरफ चल रहा है, जनता परेशान और कमाई मोटे कमीशन पर तीसरा कर रहा है। मुंबई में भी मेट्रो रिलायंस के पास है, अडानी, अंबानी, टाटा जैसे पूंजीपतियों की कठपुतली मोदी जनधन से निर्मित भारतीय रेलवे का भी अंबानी को सौंपने के लिए कटिबद्ध है। धूर्त मोदी के सपनों की मेट्रो ट्रेन, स्मार्ट सिटी, में जिसमें लाखों करोड़ रुपए जनधन के खर्च होंगे, अपने मोटे कमीशन के लिए इसके ठेके भी इन हरामखोर जालसाज अडानी, अंबानी, टाटा आदि पूंजीपतियों को सौंपकर मोटी कमाई करेगा और करवाएगा, दूसरी तरफ जनता इस सब्जबाग की हरियाली के इंतजार में बरसों तोड़-फोड़, ये सड़क बंद वो रास्ता बंद की जाएगी, जैसा की बीआरटीएस में किया, फिर वैसे ही यह भी 5 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष में पूरी होगी, और लागत भी रु. 25000 करोड़ से बढ़कर रु. 50000 करोड़ से लेकर रु. 1 लाख करोड़ तक हो जाएगी, इस बीच आने वाले अधिकारी, इंजिनियर्स, मंत्री, ठेकेदार, मिलकर हजारों करोड़ डकार लेंगे। जैसा कि रु. 300 करोड़ का बीआरटीएस रु. 1000 करोड़ का पड़ा इस बीच इं.वि.प्रा. नगर निगम, जिलाधीश, संभागायुक्त से लेकर पैसा सैकड़ों करोड़ में इंदौर भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुंचा, वहीं हाल मेट्रो स्मार्ट सिटी में होगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- मोबा. 9425125569